

संपादक

अभिजीत कुमार, 9431006107

समाचार संपादक

अखिलेश कुमार, 9431089053

विशेष संपादक

मुकेश कुमार सिंह

सहायक संपादक

कोमल सुलतानिया

राजनीतिक संपादक

प्रो. नीरज कुमार सिंह, 9431049337

संपादकीय सलाहकार

राजीव कुमार सिंह 9431210181

कॉन्सेप्ट एडिटर

अनूप कुमार शर्मा, 7004821433

राजनीतिक व्यूरो

अमरेंद्र शर्मा 9899360011

प्रभाकर कुमार राय

प्रबंधक

अविनाश कुमार 8287266244

विधि सलाहकार

वीणा कुमारी जयसवाल, पटना हाई कोर्ट

बिहार व्यूरो

अनूप नारायण सिंह 9546224277

क्राइम व्यूरो

एसएन श्याम

मुख्य संवाददाता

सोनू सिंहा, 9431006189

आशीष कुमार

जिला व्यूरो

बेगूसराय : विरेश कुमार सिंह, 9430415316

अमित सिंह, 9430595995

भागलपुर प्रमंडल : राजेश पंजिकार,

(व्यूरो चीफ), 9334114515

समस्तीपुर : राजेश कुमार

चांदन : अमोद कुमार दूबे : 8578934993

मुंगेर : सिद्धांत

कटोरिया : दीपक चौधरी, विशेष संवाददाता

9973077043

सुईया : चन्द्रशेखर मिश्र (संवाददाता)

बिहार-झारखण्ड : अभिनव कुमार 7903292877

दिल्ली : नवल वत्स, 9818901841

स्वाति, रंजीत कुमार

ग्रेटर नोएडा : गौरीशंकर, 8920215318

प्रधान कार्यालय

गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर,

काली मंदिर रोड नं.- 7, पटना - 800 020 (बिहार)

मो.- 9431006107, 9939815347

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक : अभिजीत कुमार

गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली

मंदिर रोड नं.- 7 पटना - 800 020 (बिहार) से

प्रकाशित व एस. एम. ऑफसेट पंडुईकोठी लंगर ठोली,

डीएन दास लेन, पटना-800 004, से मुद्रित।

पत्रिका में प्रकाशित किसी भी रचना के विवाद के लिए लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके लिए संपादक से सहमति जरूरी नहीं। पत्रिका से संबंधित सभी विवादों का निबटारा पटना उच्च न्यायालय से होगा।

संरक्षक



डॉ. संजय मयूरक

राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी
माजपा

जय जयराम सिंह

JJRS CONSTRUCTION
PVT. LTD.

चर्चित बिहार

वर्ष : 8, अंक : 11, जुलाई 2021, मूल्य : 25/- राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका



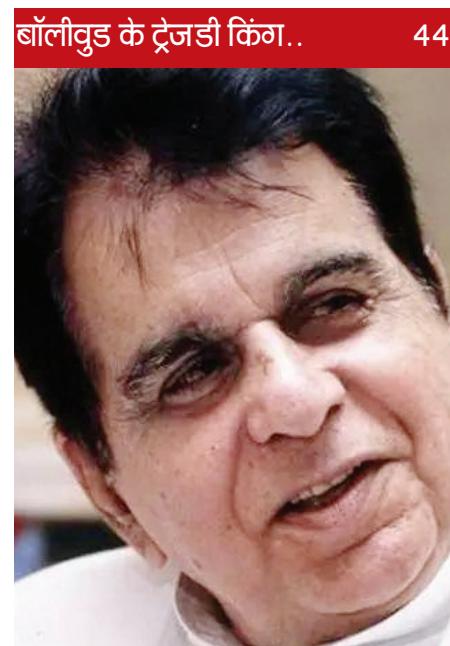
05 | अप्रैल-मई के दो महीने, जब जिंदगी की गरिमा ही नहीं बची



निर्देशकों की पसंद बनी संजना 22



पीएम केराफंड के तहत खरीदे 25



बॉलीवुड के ट्रेजडी किंग... 44



सुप्रीम कोर्ट ने कंदू की टीकाकरण ... 29

80 प्रतिशत लोगों ने माना कि भारत में आपने धर्म के पालन की पूर्ण स्वतंत्रता है

अ

मेरिका के प्यूरिसर्च सेंटर ने भारत की जनता के बारे में एक बड़ा रोचक सर्वेक्षण किया है। एजेंसी ने भारत के लगभग तीस हजार लोगों से पूछताछ करके कुछ निष्कर्ष दुनिया के सामने रखे हैं। उसने भारत के विभिन्न धर्मों के प्रति लोगों की राय इकट्ठी की है। उस राय को पढ़कर लगता है कि धर्म-निरपेक्षता या पंथ-निरपेक्षता की विष्टि से भारत दुनिया का शायद सर्वश्रेष्ठ देश है। इस सर्वेक्षण में भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और आदिवासियों से भी सवाल पूछे गए थे। 84 प्रतिशत लोगों ने कहा कि किसी भी सच्चे भारतीय के लिए यह जरूरी है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करे। 80 प्रतिशत लोगों ने कहा कि भारत में उनको उनके धर्म के पालन की पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि उनका गहरा संबंध और व्यवहार प्रायः अपने ही धर्म के लोगों के साथ ही होता है। उनका यह भी मानना था कि अंतरधार्मिक विवाह अनुचित हैं। कुछ हिंदुओं की मान्यता यह भी थी कि सच्चा भारतीय वही हो सकता है, जो हिंदू है या हिंदी भाषी हैं। इस तरह की बात कहने वाले कौन लोग हो सकते हैं? यह सर्वेक्षण इस प्रश्न का जवाब नहीं देता है लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये लोग वे हो सकते हैं, जिन्हें हम बुद्धिजीवी नहीं कह सकते हैं। ये साधारण समझ वाले लोग हैं। यह जरूरी नहीं कि इनके दिलों में अहिंदुओं या अहिंदी भाषियों के लिए कोई कदुता या दुर्भावना ही हो। अपनी मोटी समझ और उथले अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी उक्त राय जाहिर की होगी लेकिन खान-पान को लेकर तो लगभग सभी लोगों की राय साफ और लगभग एक-जैसी है। यानी जो गोमांस खाए, वह हिंदू नहीं हो सकता और जो सूअर का मांस खाए, वह मुसलमान नहीं हो सकता। इसी प्रकार जातीय समीकरणों के बारे में ज्यादातर लोगों की राय (64 प्रतिशत) यह है कि अंतरजातीय विवाह नहीं होने चाहिए। अंतरधार्मिक विवाहों के बारे में भी ज्यादातर लोगों (64 प्रतिशत) की राय यही है। मेरी समझ में भारत की एकता और समरसता के लिहाज से यह राय ठीक नहीं है, हालांकि इन धार्मिक और जातीय बंधनों का टूटना आसान नहीं है। इन बंधनों को चूर-चूर होते हुए अपनी आँखों से मैंने अंडमान-निकोबार और सूरीनाम में देखा है। एक ही परिवार में विभिन्न धर्मों के पति-पत्नी को मैंने बहुत प्रेम से रहते हुए देखा है। मॉरिशस में अंतरजातीय परिवारों की भरमार है। मेरे अपने मित्रों के ऐसे सैंकड़ों परिवार देश-विदेश में हैं, जो अंतरधार्मिक और अंतरजातीय हैं। यह कितनी विचित्र बात है कि लोग मुसलमान और ईसाई तो बन जाते हैं लेकिन वे अपनी जात नहीं भूल पाते हैं। इसे मेरे कुछ पाकिस्तानी मित्र हिंदुआना हरकत कहते रहे हैं। भारत के इस जातिवाद के आगे इस्लाम और ईसाइयत भी पस्त है। लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी मित्रों से पूछता रहता हूं कि सब धर्मों के प्रति सहनशीलता की यह हिंदुआना आदत सभी मजहबी लोग क्या कभी अपने में पैदा कर पाएँगे?

**अभिजीत कुमार
संपादक**

9431006107

cbhindi.news@gmail.com

भारत में डेल्टा प्लस वैरिएंट, कितना खतरनाक, कैसे रहें सावधान



कोरोना की दूसरी लहर थम चुकी है और तीसरी लहर का खतरा अभी से मंडराने लगा है। इस बार चुनौती बड़ी हो सकती है, क्योंकि चार राज्यों में डेल्टा प्लस वैरिएंट के केस मिले हैं।

देश में कोरोना की दूसरी लहर थम चुकी है और तीसरी लहर का खतरा अभी से मंडराने लगा है। इस बार चुनौती बड़ी हो सकती है, क्योंकि चार राज्यों में डेल्टा प्लस वैरिएंट के केस मिले हैं। अभी तक 40 लोगों में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट की पुष्टि हुई है। आइए जानते हैं कि डेल्टा प्लस कितना खतरनाक है और कैसे सावधान रहें-

डेल्टा प्लस क्या है?

यह कोरोना का नया वैरिएंट है, जो डेल्टा वैरिएंट से

म्यूटेट होकर बना है। डेल्टा प्लस को तकनीकी रूप से बी.1.617.2.1 या ए वाई.1 नाम दिया गया है। डेल्टा प्लस वैरिएंट की पहचान इस साल मार्च में हुई। यूरोप ने डेल्टा प्लस वैरिएंट की पहचान की थी। अभी तक डेल्टा प्लस वैरिएंट को लेकर ज्यादा रिसर्च सामने नहीं आया है, इस बजह से नए वैरिएंट से होने वाली बीमारी एक रहस्य बनी हुई है। डेल्टा प्लस वैरिएंट को लेकर कम जानकारी ही पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर रही है। धीरे-धीरे इस पर रिसर्च शुरू हो गया है। हालांकि माना जा रहा है कि डेल्टा वैरिएंट से डेल्टा प्लस वैरिएंट काफी खतरनाक है।

यह भारत के लिए क्यों मायने रखता है?

भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिस डेल्टा वैरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है, डेल्टा प्लस वैरिएंट उसका अपडेट वर्जन कहा जा सकता है। भारत में अभी दूसरी लहर थम रही है और डेल्टा प्लस के केस मिलने शुरू हो गए हैं। वैज्ञानिकों के बीच एक चिंता है कि डेल्टा प्लस वैरिएंट, डेल्टा वैरिएंट से भी अधिक तेजी से फैल सकता है।

महाराष्ट्र से डेल्टा प्लस के 20 से अधिक मामले ऐसे समय में सामने आए हैं, जब विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि भारत में जल्द ही कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। डेल्टा वैरिएंट ने अप्रैल और मई के महीने में जबरदस्त तबाही मचाई थी, ठीक उसी तरह डेल्टा प्लस वैरिएंट भी आने वाले महीनों में तबाही मचा सकता है।

डेल्टा वैरिएंट क्या है?

यह वैरिएंट पहली बार दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र में सामने आया था। इसे बी.1.617.2 का नाम दिया गया था। मई में डब्लू एच ओ ने इसे डेल्टा नाम दिया। डब्लू एच ओ के मुताबिक अब तक करीब 75 देशों में डेल्टा वैरिएंट के सामने आ चुके हैं। यूके जैसे देशों में डेल्टा वैरिएंट तेजी से उभरा है। अमेरिका में इस वैरिएंट के तेजी से केस आए हैं।

क्या डेल्टा वैरिएंट के कारण अलग-अलग लक्षण होते हैं?

विशेषज्ञ कह रहे हैं कि डेल्टा वैरिएंट में वह लक्षण मिल रहे हैं, जो पहले कोरोना के वैरिएंट में नहीं थे। गेवी वैक्सीन एलायंस के अनुसार, डेल्टा वैरिएंट मरीजों को बीमार बना रहा है और पिछले वैरिएंट के कारण हुए संक्रमण के मामलों की तुलना में उनकी स्थिति तेजी से बिंदड़ रही है। इस वैरिएंट में सिर दर्द, गले में खराश, नाक बहना और बुखार आम है।

क्या डेल्टा मामलों में अस्पताल में भर्ती

होने की दर अधिक है?

महामारी विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टा वैरिएंट कोविड-19 रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने के अधिक जोखिम से जुड़ा हो सकता है। 14 जून को द लैंसेट मे में प्रकाशित एक स्कॉटिश अध्ययन के अनुसार, डेल्टा संस्करण में अल्फा संस्करण की तुलना में अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम लगभग दोगुना था।

क्या डेल्टा वैरिएंट टीकों से बच सकता है?

अमेरिकी डॉक्टर और महामारी विशेषज्ञ एरिक फीगल-डिंग ने डेल्टा संस्करण के खिलाफ टीकों की प्रभावकारिता के बारे में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एस्ट्राजेनेका का टीका, जिसे भारत में कोविशील्ड कहा जाता है, डेल्टा संस्करण के खिलाफ सबसे अच्छा 60 प्रतिशत प्रभावी हो सकता है।

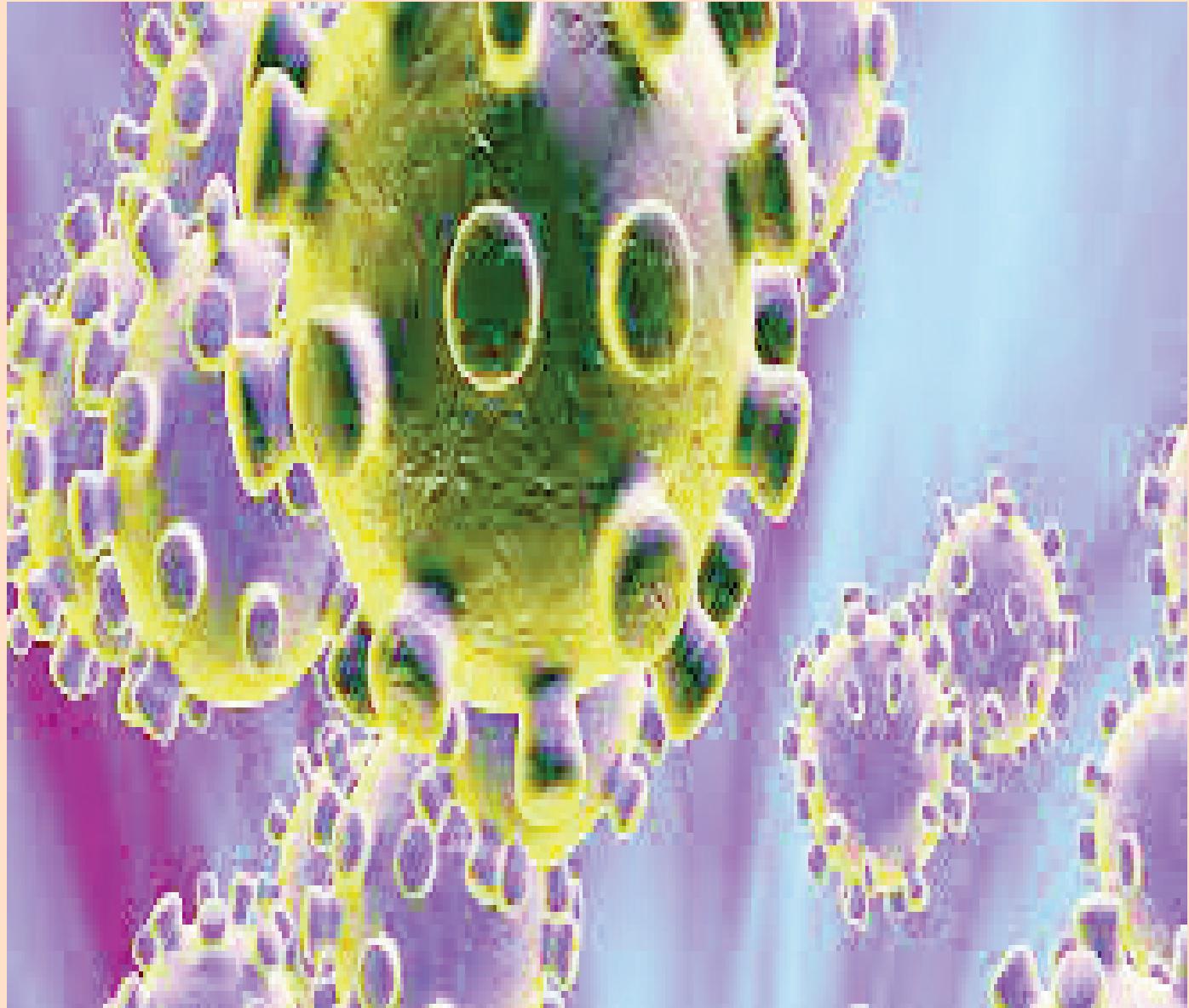
अध्ययन के अनुसार, फाइजर-बायोएनटेक के टीके की प्रभावकारिता अल्फा संस्करण के मुकाबले 92 प्रतिशत

से कम होकर डेल्टा संस्करण के मुकाबले 79 प्रतिशत हो जाती है। डेल्टा वैरिएंट में टीके की क्षमता सिर्फ 79 फीसदी रह गई।

क्या डेल्टा प्लस एक ही खतरा पैदा करता है?

अभी स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाणों का अभाव है, लेकिन जैसा कि जीव विज्ञान का नियम है, हर सफल म्यूटेंट एक वायरस को जीवित रहने के लिए अधिक सक्षम बनाता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर डेल्टा प्लस, डेल्टा वैरिएंट का एक सफल म्यूटेंट साबित होता है, तो यह डेल्टा संस्करण की सभी खतरनाक विशेषताओं को बरकरार रख सकता है।

डेल्टा प्लस संक्रमण के मामलों का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और ऐसे रोगियों में कोविड -19 की प्रगति को बेहतर ढंग से समझने के लिए सूक्ष्मता से दर्ज किया जा रहा है। केवल डेटा और वैज्ञानिक साक्ष्य ही एक स्पष्ट तस्वीर पेश कर सकते हैं। अभी डेल्टा प्लस



अप्रैल-मई के दो महीने, जब जिंदगी की गरिमा ही नहीं बची



दो महीने तक आपने देखा कि किसी की जिंदगी की कोई गरिमा नहीं बची थी। आम आदमी हो या मुगालते में रहने वाले रसूखदार लोग। सब अस्पताल में बेड खोज रहे थे और ऑक्सीजन का सिलेंडर तक हासिल नहीं कर पाए रहे थे। इस अंजाम से गुजरने के बाद भी अगर आगाज नया नहीं होगा तो फिर से वही अंजाम होगा। गुजराती अखबारों और भास्कर में दो महीने तक आपने देखा कि किसी की जिंदगी की कोई गरिमा नहीं बची थी।

गुजराती अखबारों और भास्कर समूह ने तमाम राज्यों से मौत के आंकड़े को छिपाने का जो खेल पकड़ा है उसे कुछ अंग्रेजी अखबार भी सीधा रहे हैं। नोएडा और दिल्ली में पत्रकारों का घनत्व देश में सबसे अधिक होगा। दिल्ली में पिछले साल के अप्रैल और

मई महीने की तुलना में ये 250 प्रतिशत अधिक है। दिल्ली नगर निगम ने दो महीने में 34,750 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए हैं। लेकिन इन दो महीनों में आधिकारिक तौर पर दिल्ली में 13,201 लोग कोविड से ही मरे हैं। पिछले साल मई में 5,475 की तुलना में इस साल मई में 24,000 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। चार गुना ज्यादा। पिछले साल अप्रैल की तुलना में इस अप्रैल में करीब ढाई गुना ज्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, 10750। एक एक आदमी के घर जाकर जांच होनी चाहिए कि कितने लोग कोविड से मरे और कितने लोग इलाज न मिलने के कारण मरे। अगर हम दिल्ली में ही मरने वालों की संख्या सही नहीं जान सकते, तो फिर दिल्ली को झूठ की राजनीति घोषित कर देना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से मरने के बाद भी

ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है के सरकारी झूठ के साथ-साथ भारत की जनता ने इस झूठ को भी स्वीकार कर लिया कि लाखों लोग नहीं मरे हैं। दुनिया में झूठ की इससे बड़ी जीत दूसरी नहीं हुई है। पटना के ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी भास्कर की टीम ने जब पड़ताल की तो कोविड से मरने वालों की सरकारी संख्या से कहीं ज्यादा शब्दों के अंतिम संस्कार हुए हैं। गूगल सर्च कर नहीं पता चला है बल्कि इसके लिए भास्कर को 18 रिपोर्टों की टीम लगानी पड़ी है तब जाकर झूठ के शामियाने के नीचे का खंभा दिखा है। अभी पूरी चादर नहीं दिखी है।

भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पटना शहर में मई के महीने में तीन शमशान में ही 1648 शब्दों का अंतिम संस्कार हुआ है। जबकि सरकारी आंकड़ा 446 का है।



भास्कर ने लिखा है कि पटना के तीन घाट पर ही रिकार्ड रखने की व्यवस्था है। बाकी गांवों और कई घाटों पर कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। यह रिपोर्ट केवल श्मशान घाटों की है। कविस्तान की गिनती नहीं है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना से 447 लोगों की मौत हुई है। 3,162 लोगों की मौत हुई जिनकी जांच नहीं हुई मगर कोरोना के लक्षण थे। इस तरह गांव शहर के आंकड़े जोड़ने पर मरने वालों की संख्या 5000 हो जाती है।

पेरु ने कभी दावा नहीं किया कि वो विश्व गुरु बनने के लिए सीबीएसई (ब्लैम) की परीक्षा की तैयारी कर रहा है लेकिन उस देश ने भी मरने वालों की संख्या पर संदेह किया तो जांच बिठा दी और अब संख्या दोगुनी कर दी गई है। कायदे से जिस तरह इन तीन महीनों में भारत के नागरिकों ने अपमान झेला है, पूरे साल केवल इसी दौर पर बात होनी चाहिए। मार्च और अप्रैल के महीने में लोग लिख रहे थे कि छह लाख का बिल आ गया है तो किसी का 14 दिन में 8 लाख का बिल आ गया है। ब्लैक फंगस की सर्जरी का बिल चार लाख का आ गया है तो बाकी सारा खर्च मिलाकर 14 लाख का हो गया है। लाखों रुपये देने के बाद तीमारदारों का जो अस्पताल के बाहर अनुभव हुआ है, उसी की एक जनसुनवाई होनी चाहिए। पूरी संसद को बैठ कर सुनना चाहिए कि लोगों पर क्या बीती है। कितने अस्पतालों ने बोरी बोरी भर कर कैश लिए, पता नहीं। आयकर विभाग पता कर सकता है। उनके बैंक खातों की जांच कर सकता है। देख सकता है कि तीन महीनों में अस्पताल में भर्ती हुए कितने मरीजों ने चेक या इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान किया और कितने ने कैश में भुगतान किया। डॉक्टर के प्रति कृतज्ञ होना और अस्पताल की लूट को समझना दोनों दो चीजें हैं। इससे डॉक्टर को आहत होने की जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें भी नागरिकों को समझाने में मदद करनी चाहिए कि उनसे किस तरह लाखों रुपये लिए गए हैं। ताकि लोग अधिक से अधिक

पेरु ने कभी दावा नहीं किया कि वो विश्व गुरु बनने के लिए सीबीएसई (ब्लैम) की परीक्षा की तैयारी कर रहा है लेकिन उस देश ने भी मरने वालों की संख्या पर संदेह किया तो जांच बिठा दी और अब संख्या दोगुनी कर दी गई है। कायदे से जिस तरह इन तीन महीनों में भारत के नागरिकों ने अपमान झेला है, पूरे साल केवल इसी दौर पर बात होनी चाहिए। मार्च और अप्रैल के महीने में लोग लिख रहे थे कि छह लाख का बिल आ गया है तो किसी का 14 दिन में 8 लाख का बिल आ गया है। ब्लैक फंगस की सर्जरी का बिल चार लाख का आ गया है तो बाकी सारा खर्च मिलाकर 14 लाख का हो गया है। लाखों रुपये देने के बाद तीमारदारों का जो अस्पताल के बाहर अनुभव हुआ है, उसी की एक जनसुनवाई होनी चाहिए। पूरी संसद को बैठ कर सुनना चाहिए कि लोगों पर क्या बीती है। कितने अस्पतालों ने बोरी बोरी भर कर कैश लिए, पता नहीं। आयकर विभाग पता कर सकता है। उनके बैंक खातों की जांच कर सकता है। देख सकता है कि तीन महीनों में अस्पताल में भर्ती हुए कितने मरीजों ने चेक या इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान किया और कितनों ने कैश में भुगतान किया। डॉक्टर के प्रति कृतज्ञ होना और अस्पताल की लूट को समझना दोनों दो चीजें हैं। इससे डॉक्टर को आहत होने की जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें भी नागरिकों को समझाने में मदद करनी चाहिए कि उनसे किस तरह लाखों रुपये लिए गए हैं। ताकि लोग अधिक से अधिक

कर सकता है। देख सकता है कि तीन महीनों में अस्पताल में भर्ती हुए कितने मरीजों ने चेक या इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान किया और कितनों ने कैश में भुगतान किया। डॉक्टर के प्रति कृतज्ञ होना और अस्पताल की लूट को समझना दोनों दो चीजें हैं। इससे डॉक्टर को आहत होने की जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें भी नागरिकों को समझाने में मदद करनी चाहिए कि उनसे किस तरह लाखों रुपये लिए गए हैं। ताकि लोग अधिक से अधिक

संख्या में अधिक बिलिंग और कैश में वसूली को लेकर शिकायत करने के लिए आगे आ सकें।

जमीन बेच कर इलाज कराने को मजबूर

अजीत सिंह जैसे कम लोग होते हैं जो अपने बेटे दिलीप की मौत के बाद जिला प्रशासन के पास गए कि दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल में 2 लाख 30 हजार 500 का बिल दिया है जो अधिक है। इसके

पहले अंजित सिंह ने अपने बेटे को पटना के यूनिवर्सिटी अस्पताल में रखा था। वहां अस्पताल मजबूर करता था कि पहले पैसे दो तभी इलाज करेंगे। यही शिकायत दिल्ली में भी कई लोगों ने की है। यूनिवर्सिटी अस्पताल में 12 दिन इलाज हुआ और बिल आया 9 लाख का। बाद में दरभंगा लाए गए। अंजित सिंह का अरोप है कि दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल ने मौत के बाद भी बेटे को जीवित बता कर दवा और उपचार का खर्च दिखलाया गया है। अंजित कुमार सिंह ने दरभंगा जिलाधिकारी के यहां शिकायत की। जांच के बाद पाया गया कि अंजित सिंह की बात सही है। मरीज की मौत के बाद भी बिल बनाया गया है। बिना किसी लक्षण के रेमडेसिवर दे दिया गया। ऐसी दवाओं का बिल लिया गया जिनका रिकार्ड अस्पताल के पास नहीं है। 3 दिन बैटिलेटर पर रखा और पैसे लिए 9 दिन के।

अंजित सिंह से पूछिए उनका कहना है कि भीख मांग कर पैसे दिए हैं। अंजित सिंह 12 कट्टा की जोत के किसान हैं। 12 कट्टा के किसान को 12 दिन में 12 लाख लग गए इलाज पर। इस किसान को बाहर लाख रुपये देने पड़े हैं। बेटा भी नहीं बचा। इसलिए कहता हूं कि किसी को जनसुनवाई का स्टेटफार्म बनाना चाहिए। जहां लोग सांसदों को अस्पतालों के किस्से बता सकें। विश्व गुरु भारत की कहानी बता रहा हूं। अपने एनआरआई (छत्ते) रिश्तेदार को बीडिंगो कॉल पर बताइयेगा कि यह घटना डेनमार्क की नहीं है, बेहार के दरभंगा की है। इस तरह के अपमान से गुरजना पड़ा है लोगों को। दरभंगा हो या दिल्ली, कोविड के दौरान इलाज के खर्च से भी कई लोग गरीब हो गए। लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति है। अशोक अग्रवाल आए दिन ऐसे ही मामलों से जूझते रहते हैं। अस्पताल वालों को भी पता है कि कोई है जो गरीबों के लिए लड़ रहा है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम बार बार अप्रैल और मई के महीने में लौटें और देखें कि क्यों ऐसा हुआ और क्या हो कि अब ऐसा न हो। लोगों को भरोसा नहीं है कि कार्रवाई होगी। तरह तरह का डर होगा कि अस्पताल फिर से इलाज नहीं करेगा। कुछ समय के बाद मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी दूसरे शहर में उसी अस्पताल के एक नए सेंटर का उद्घाटन कर रहा होगा।

ऐसे नेटवर्क और सांठगांठ के किस्से आपको हर राज्य में मिलेंगे। जब तक आप ऐसे नेटवर्क के खेल को नहीं समझेंगे और सबके लिए अस्पताल की बात नहीं करेंगे, सरकारी अस्पताल की बात नहीं करेंगे, आप खुद को भी जोखिम में डालेंगे। नांदेड़ के तथात सच्चर्हंड श्री हुजूर अबचलनगर साहिब ने फैसला किया है कि पचास साल में जितना भी दान मिला है उससे एक मेडिकल कालेज और अस्पताल बनाया जाएगा। 25 किलोड़ का सोना भी अस्पताल बनाने के काम आएगा। अब्बल तो सच्चर्हंड साहिब में पचास साल के दान का हिसाब है, सोना मौजूद है, इसी ईमानदारी से सबको सीख लेनी चाहिए। गुरुद्वारा समिति ने महामारी की चुनौती का सामना करने कि अस्पताल बनाने का निर्णय किया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजरेंट कमिटी ने भी दिल्ली में 125 बेड का अस्पताल बनाने के लिए 20 किलो सोना और चांदी दान दिया है। क्या यही काम सबको नहीं करना चाहिए। गुरुद्वारा समिति किसी एक मजहब के लिए अस्पताल नहीं बना रही है, सबके

लाखों रुपये देने के बाद तीमारदारों का जो अस्पताल के बाहर अनुभव हुआ है, उसी की एक जनसुनवाई हानी चाहिए। पूरी संसद को बैठ कर सुनना चाहिए कि लोगों पर क्या बीती है। कितने अस्पतालों ने बोरी बोरी भर कर कैश लिए, पता नहीं। आयकर विभाग पता कर सकता है। उनके बैंक खातों की जांच कर सकता है। देख सकता है कि तीन महीनों में भर्ती हुए कितने मरीजों ने चेक या इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान किया और कितनों ने कैश में भुगतान किया। डॉक्टर के प्रति कृतज्ञ होना और अस्पताल की लूट को समझना दोनों दो चीजें हैं। इससे डॉक्टर को आहत होने की जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें भी नागरिकों को समझाने में मदद करनी चाहिए कि उनसे किस तरह लाखों रुपये लिए गए हैं।

लिए बना रही है। तो सरकार क्यों नहीं सबके लिए अस्पताल बनाने का आंदोलन शुरू करती है। इसके बाद भी इस खबर से सामना करना पड़ता है कि हेमकुंट फाउंडेशन के बनाए अस्थायी अस्पताल को असमाजिक तत्व तोड़ गए हैं। गुरुग्राम की यह घटना है। हेमकुंट फाउंडेशन ने कहा है कि नई जगह पर अस्पताल बनाएंगे। तोड़ फोड़ के बक्त कोई मरीज भर्ती नहीं था। इसी सवाल को बार बार पूछता है कि सबके लिए सस्ता और अच्छा अस्पताल बनाने के बारे में क्या सोचा जा रहा है। जिस वक्त सरकारी अस्पतालों को ठीक करने की प्राथमिकता होनी चाहिए, उस वक्त आपदा में आइडिया निकाला जा रहा है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सरकारी अस्पतालों को सौंप दें। नीति आयोग का आइडिया देखिए कि जिला अस्पतालों से जुड़े मेडिकल कालेज को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत आ जाएंगे। केवल सरकारी अस्पतालों को बेहतर करने और सुलभ करने के लिए आइडिया नहीं आता है।

इसकी भूमिका बांधने के लिए जनवरी 2020 में 250 पेज का दस्तावेज तैयार किया गया था। जिला अस्पतालों को प्राइवेट हाथों में सौंपने का काम धीरेधीरे किया जाएगा। प्राइवेट प्लेयर को मेडिकल कॉलेज के डिजाइन, निर्माण, अपग्रेडेशन और रखरखाव का काम करना होगा। हर साल 150 डठठे के छात्र लेने होंगे। कहानी घुमा कर बताई जा रही है कि जिला अस्पताल में कम से कम 750 बेड होंगे। जिसमें से 300 बेड और बाकी बचे 20 बेड गरीबों के लिए होंगे बाकी पर प्राइवेट अपने हिसाब से पैसे लेंगे। यानी अगर 900 बेड का अस्पताल है तो 480 बिस्तर तो प्राइवेट के होंगे। क्या देश में गरीबी कम हो रही है कि हम उनके लिए सरकारी अस्पताल में बेड कम बना रहे हैं। एक साल से आप कोरोना को हरा देने के प्रोप्रैंडा की चेपट में थे इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा। अब जब

हार कर आएं तो उम्मीद है कि आप ध्यान देंगे और खेल को समझेंगे।

29 मई को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के एलान को ठीक से समझिए। किसे अच्छा नहीं लगेगा कि राज्य सरकार 16 मेडिकल कालेज और अस्पताल खोलने जा रही है। लेकिन इसी के साथ अधिकारियों से कहा है कि सभी जिलों में सोलह मेडिकल हब बनाने के लिए जमीन खोजी जा रही है। सरकार हर जिले में पांच से छह निवेशकों को सौ-सौ करोड़ निवेश करने पर निवेशक को पांच एकड़ जमीन मुफ्त में देगी। तीस एकड़ जमीन प्री में हैडलाइन बड़ी छपेगी कि सरकार तीन साल में अस्सी अस्पताल बनाने जा रही है। आगे राज्य को अस्सी अस्पताल की जरूरत है लेकिन वह केवल सोलह मेडिकल कालेज और अस्पताल खोल रही है। बाकी प्राइवेट के लिए रास्ता बना रही है।

इन्हें लोगों को गंवा कर अगर हमने ये सबक सीखा है तो अगली बार लुटने के लिए पैसे बचाने शुरू कर दीजिए। अस्पतालों की लापरवाही और लूट से डॉक्टर भी नहीं बचे हैं। यह सवाल तो है कि क्या कोविड से संक्रमित सभी डॉक्टरों को बढ़िया इलाज मिला? क्या उन्हें लाखों रुपये नहीं देने पड़े होंगे? अकेले दिल्ली में 109 डॉक्टरों की मौत हुई है। इस बार देश भर में कोविड से 624 डॉक्टर की मौत हुई है। बता अस्पताल में आक्सीजन की सप्लाई बंद होने से डॉक्टर आर और केहिंचनी (त्वं भूतज्ञीदप) की मौत हो गई। सब चुप हैं। क्या कभी उन्हें इंसाफ मिलेगा। असम के होजाई में डॉक्टर सेनापति और नर्स ललिता भराली पर 24 लोगों ने बुरी तरह हमला कर दिया। चिकित्सालुर के डॉक्टर दीपक पर चार लोगों ने हमला कर दिया। गुस्सा डाक्टर पर मत निकालिए। गुस्सा है तो सवाल पूछिए कि क्या किया जाए। कैसे सबके लिए इलाज की व्यवस्था की जाए। जो सरकार अपने दस्तावेजों में सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट हाथों सौंपने का जुगाड़ निकालती रहती है उसी सरकार के दूसरे दस्तावेज में प्राइवेट अस्पतालों के बारे में क्या लिखा गया है। जानना चाहिए। 2020-21 के आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि निजी क्षेत्र में उपचार की गुणवत्ता सरकारी क्षेत्र की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर प्रतीत नहीं होती है। फिर भी, निजी क्षेत्र में उपचार की लागत ना केवल सामान्य रूप से अधिक है, बल्कि कैन्सर का इलाज करीब चार गुना महंगा है, दिल की बीमारी का इलाज करीब 7 गुना महंगा है और सांस की बीमारी का इलाज 5 गुना से अधिक है।

महामारी के कारण ऐसे बहुत से लोगों को सरकारी अस्पताल जाने का मौका मिला। जाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था लेकिन तब भी सरकारी अस्पतालों की बात नहीं हो रही है। उनकी संख्या कम रहते या खराब रहते हुए आप कभी भी हेल्थ सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते हैं। कई सरकारी अस्पतालों में लोगों के अच्छे अनुभव भी रहे हैं। कहीं सुविधा ठीक थी तो कहीं कम थी लेकिन उसी के बीच डाक्टर और हेल्थ वर्कर को कमाल का काम करते देखा। लेकिन कई जगहों पर बेहद खराब अनुभव भी रहे। न स्टाफ था और न इलाज था। मैं नहीं कह रहा कि प्राइवेट अस्पताल नहीं चाहिए, मैं भी प्राइवेट में ही जाता हूं लेकिन मेरी तरह कई लोग इस बार सरकारी अस्पताल



गए। लेकिन बेहतर स्थिति यही है कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट से अच्छे हों और उनकी संख्या ज्यादा हो। आप टैक्स देते किस लिए हैं। सिर्फ जेएनयू का हिसाब मांगने के लिए टैक्स नहीं देते हैं। और टैक्स तो हर कोई देता है। बिस्किट खरीदो तो भी टैक्स जाता है। अनगिनत नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों ने तरह तरह से लोगों पर लाखों रुपये के बिल का बोझ डाला है। इसका अदाजा आपको अदालतों की टिप्पणियों से हो जाएगा। 24 मई को मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि प्राइवेट अस्पताल की वसूली पर नियंत्रण करें। ताकि सरकारी अस्पतालों में जगह न मिलने पर जान बचाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने वाले आम नागरिक आर्थिक रूप से बर्बाद न हो जाएं। मद्रास हाई कोर्ट ने 2 जून को भी कहा है कि लोग अच्छा इलाज हासिल करने के लिए कर्ज में ढूब गए हैं। सरकार इन वित्तीय मुश्किलों का हल निकालने के लिए नीति बनाए।

1 जून को तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि लोग इलाज का खर्च भरने के लिए सोना गिरवी रख रहे हैं। 8 मई को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि प्राइवेट अस्पतालों में आक्सीजन बेड, आइसीयू बेड, वैंटिलेटर और एंबुलेंस की दरों को तय करे। 1 जून को बताया गया कि सरकार ने कोई फैसला ही नहीं लिया है। तो इस तरह से लोगों की चिन्ता हो रही है। पीएम केर्यस के तहत खराब वैंटिलेटर की सप्लाई की जांच में पाया है कि पीएम केर्यस के तहत जो वैंटिलेटर मिले हैं वो खराब हैं। उनके इस्तमाल से किसी मरीज की जान जा सकती है। कोर्ट के कहने के बाद भी ऐसी

महामारी के कारण ऐसे बहुत से लोगों को सरकारी अस्पताल जाने का मौका मिला। जाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था लेकिन तब भी सरकारी अस्पतालों की बात नहीं हो रही है। उनकी संख्या कम रहते या खराब रहते हुए आप कभी भी हेल्थ सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते हैं। कई सरकारी अस्पतालों में लोगों के अच्छे अनुभव भी रहे हैं। कहीं सुविधा ठीक थी तो कहीं कम थी लेकिन उसी के बीच डाक्टर और हेल्थ वर्कर को कमाल का काम करते देखा। लेकिन कई जगहों पर बेहद खराब अनुभव भी रहे हैं। न स्टाफ था और न इलाज था। मैं नहीं कह रहा कि प्राइवेट अस्पताल नहीं चाहिए, मैं भी प्राइवेट में ही जाता हूं लेकिन मेरी तरह कई लोग इस बार सरकारी अस्पताल गए। लेकिन बेहतर स्थिति यही है कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट से अच्छे हों और उनकी संख्या ज्यादा हो। आप टैक्स देते किस लिए हैं। सिर्फ जेएनयू का हिसाब मांगने के लिए टैक्स नहीं देते हैं। और टैक्स तो हर कोई देता है। बिस्किट खरीदो तो भी टैक्स जाता है। अनगिनत नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों ने तरह तरह से लोगों पर लाखों रुपये के बिल का बोझ डाला है।

नहीं मिली है। बांबे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा है कि अगर खराब वैंटिलेटर से किसी की जान जाती है तो उसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की है। औरंगाबाद के मेडिकल कालेज में खराब वैंटिलेटर की सप्लाई से अगर किसी की मौत हुई है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। खराब वैंटिलेटर बदल कर नया देने की जवाबदेही भी केंद्र सरकार की है। औरंगाबाद के मेडिकल कालेज जीएमसीएच ने अपनी जांच में पाया है कि पीएम केर्यस के तहत जो वैंटिलेटर मिले हैं वो खराब हैं। उनके इस्तमाल से किसी मरीज की जान जा सकती है। कोर्ट के कहने के बाद भी ऐसी

जरूरी खबरें गायब कर दी जा रही हैं जबकि कई जगहों से पीएम केर्यस के वैंटिलेटर्स के खराब निकलने की खबरें छपी हैं। पीएम केर्यस के वैंटिलेटर को लेकर कितनी खबरें आ गईं। खराब वैंटिलेटर खरीदने का डर किस एक्सपर्ट कमेटी ने दिया। वह एक्सपर्ट कमेटी सार्वजनिक रूप से सफाई करने वाली नहीं देती है। क्या ऐसी किसी कमेटी को पता नहीं एक साल से पीएम केर्यस के वैंटिलेटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसके लिए पहले आपने कभी सुना है कि सरकारी अस्पताल को वैंटिलेटर दिया गया और वो काम नहीं कर रहा है। पीएम केर्यस के वैंटिलेटर को लेकर सुनाई दे रहा है।

बिहार के युवाओं को हुनरमंद बनाने में अहम भूमिका का निर्वहन करेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग



वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह की कलम से

बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है विकास से समझौता नहीं किया जाएगा न्याय में के साथ विकास की अवधारणा को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए जनप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह कृत संकल्पित है राज्य के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी अपनी अहम भूमिका अदा करने की तैयारी में है राज्य के युवा युवतियों को हुनरमंद करने के लिए विभाग के द्वारा कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं साथ ही साथ विभाग के द्वारा राज्य भर के लोगों से ऐसे प्रोजेक्ट अविष्कार आमंत्रित किए जा रहे हैं जिससे किसी भी क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हो ऐसे किसी भी सुझाव या अविष्कार के लिए विभाग के द्वारा ₹ 3 लाख की बजीफे की भी व्यवस्था की गई है बिहार के युवाओं को हुनरमंद बनाना पहला लक्ष्य कहा बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने। मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। विभाग द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। यदि उसमें कोई त्रुटि होगी या कोई कमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा। सुमित कुमार ने कहा कि जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है उसका निर्वाहन पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। सभी कॉलेजों की समीक्षा की जा रही है। हमारी कोशिश है कि हर बेहतर सुविधा छात्रों को उपलब्ध कराई जाए। बिहार के छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दूसरे राज्य में जाते हैं। यहां पर मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। कोई नई योजना शुरू करनी हो या पुरानी योजना में बदलाव तो हम बेहिचक करेंगे।

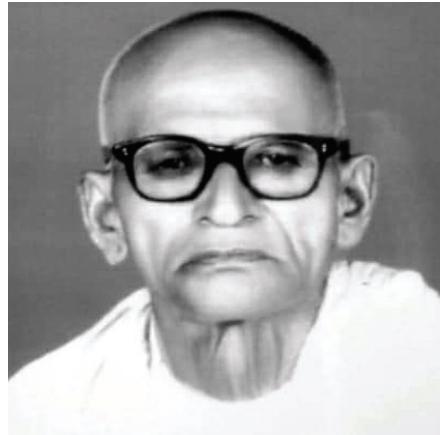
जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की जाएगी, यदि उसमें कोई त्रुटि होगी या कोई कमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा। सुमित कुमार ने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसपर पूरी तरीके से खड़ा उतरेंगे। युवाओं की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्हें निराश नहीं करेंगे। जो भी सूचना मिलेगी उसपर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई सुझाव मिलिया या आम लोगों द्वारा दिया जाएगा तो उसपर भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की बरनार जलाशय योजना, अजय, घाघरा जलाशयों को दुरुस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री की सोच है कि युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे। प्लेसमेंट सेल की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जो विश्वास उन पर राज्य के मुखिया नीतीश कुमार और क्षेत्र चकाई की जनता ने जताया है उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि चकाई बनेगा चंडीगढ़ के सपने को साकार करने के लिए हर सार्थक पहल की जाएगी। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। तीन महीने के भीतर 170 करोड़ की विकास योजना की स्वीकृति ही गयी। शीघ्र ही इन योजनाओं का कार्य शुरू होगा। क्षेत्र का सर्वांगीण विकास ही हमारी प्राथमिकता है। सड़क, सिंचाई से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं नक्सलबाद, उग्रवाद जैसी समस्याओं को लेकर भी काम किया जाएगा।

दुनिया जिसे जानती है भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में आज भी उसके परिजन बने हुए हैं भिखारी

भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के नाम पर हजारों लोग अमीर बन गए आज भी भिखारी ठाकुर के परिजन फटेहाल स्थिति में किसी तरह अपना गुजर-बसर कर रहे हैं उनकी सुध लेने की फुर्सत ना राज्य सरकार को है और ना ही उन संस्थाओं को जो भिखारी ठाकुर के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों के अनुदान प्राप्त करते हैं।

लोक संस्कृति के वाहक कवि व भोजपुरी के शेक्सपियर माने जाने वाले भिखारी ठाकुर का जयंती 18 दिसंबर को मनाई जाती है। लेकिन क्या कोई यकीन कर सकता है कि भक्तिकालीन भक्त कवियों व रीत कालीन कवियों के संथि स्थल पर कैथी लिपि में कलम चलाकर फिर रामलीला, कृष्णलीला, विदेशिया, बेटी-बेचवा, गबरधिंचोरहा, गीति नाट्य को अभिनीत करने वाले लोक कवि भोजपुरी के शेक्सपीयर भिखारी ठाकुर के परिवार चीथडो में जी रहा हो। देश ही नहीं विदेशों में भोजपुरी के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले मल्लिक जी के परिवार गरीबी का दंश झेल रहा है। यह सच है कि उनके जयंति व पुण्यतिथि पर कुछ गणमान्य पहुंचते हैं, कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, लेकिन यह सब मात्र श्रद्धांजलि की औपचारिकता तक सिमट कर रह जाते हैं। न तो ऐसे किसी आयोजन में भिखारी ठाकुर के गांववासियों का दर्द सुना जाता है न ही उनके दर्द की दवा की प्रबंध की बात होती है। कुतुबपुर दियारा स्थित मल्लिक जी का खरौल व छपर निर्मित जीर्ण-शीर्ण घर आज भी अपने जीर्णोद्धार की बाट जोह रहा है? यही से भिखारी ठाकुर ने काव्य सरिता प्रवाहित की थी और उनकी प्रसिद्धि की गूंज आज भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर सुनाई पड़ रही है।

भिखारी ठाकुर के प्रपौत्र सुशील आज भी अदद चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए भटक रहा, कोई सुधी तक नहीं लेने वाला। भिखारी ठाकुर के प्रपौत्र सुशील कुमार आज एक अदद चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए मारा-मारा फिर रहा है। दर्द भरी जुबान से सुशील बताते हैं कि अगर फुआ और फुफा नहीं रहते तो शायद मैं एमए तक पढ़ाई नहीं कर पाता। रोटी की लड्डू में मेरी पढ़ाई नेपथ्य में चली गई रहती। सम्भरणालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नौकरी के लिए वे आवेदन किये हैं। पैनल सूची में नाम भी है, लेकिन एक साल बीत गए, भगवान जाने नौकरी कब मिलेगी। हाल यह है कि विभिन्न कार्यक्रमों में उन्हें एवं उनके परिजन को मंच तक नहीं बुलाया जाता है। जिस दीपक की लौ से समाज में व्यास कुरीतियों और सामयिक संमस्याओं को उजागर करने का महती प्रयास भिखारी ठाकुर ने किया उनकी लौ में आज कई लोग रोटियां सेंक रहे हैं, लेकिन दीपक तले अंधेरे की कहावत चरितार्थ है। दबी जुबान से दिल की बात बाहर आती है कि भिखारी ठाकुर के नाम पर कई लोग



वृद्धा पेशन एवं सुख सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। परिवार को होरेक जरूरत की दरकार है। एक ओर जहां सुशील जीवकोपार्जन के लिए दर-दर भटक रहे हैं वहीं, उनकी पुत्रवधू व सुशील की माँ गरीबी का दंश झेल रही है। भिखारी ठाकुर के इकलौते पुत्र शीलानाथा ठाकुर थे। वे भिखारी ठाकुर के नाट्य मंडली व उनके कार्यक्रमों से कोई रुची नहीं थी। उनके तीन पुत्र राजेन्द्र ठाकुर, हीरालाल ठाकुर व दीनदयाल ठाकुर भिखारी की कला को जिन्दा रखे। नाटक मंडली बनाकर जगह-जगह कार्यक्रम करने लगे। लेकिन इसी बीच उनके बाबू जी गुजर गये। फिर पेट की आग तले वह संस्कार दब गई। अब तो राजेन्द्र ठाकुर भी नहीं रहे। फिलवक्त भिखारी ठाकुर के परिवार में उनके प्रपौत्र सुशील ठाकुर, राकेश ठाकुर, मुना ठाकुर एवं इनकी पत्नी रहती है। जीर्ण-शीर्ण हालात में किसी तरह सत्ता व सरकार को कोसते जिंदगी जिये जा रहे हैं उनके परिजन लोक साहित्य व संस्कृति के पुरोधा, भोजपुरी के शेक्सपीयर के गांव कुतुबपुर काश, स्थानीय सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे राजीव प्रताप रूढ़ी के सांसद ग्राम योजना के तहत गोद में होता तो शायद पुरोधा के गांव को तारणहार की प्रतिक्षा नहीं होती। गंगा नदी नाव से उस पर छपरा से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित कुतुबपुर गांव आज भी अंधेरे तले है। कार्यक्रमों की रोशनी व राजनेताओं का आश्वासन उस गांव को रोशन नहीं कर सका। शायद श्रद्धांजलि सभा और सांस्कृतिक समारोह भी कुछ लोगों तक सीमट कर है। वरन्, सरकार दो फूल चढ़ाने में भी भिखारी ही रहा है। आस-पास दर्जनों गांव, हजारों की बस्ती, नीन पंचायतों में एक मात्र अपग्रेड हाईस्कूल। वह भी प्राथमिक विद्यालय से अपग्रेड हुआ है। प्रारंभिक शिक्षक और पढ़ाई हाईस्कूल तक। आगे की पढ़ाई के लिए नदी इस पर आना होता है। कुछ बच्चे तो आ जाते हैं, बच्चियां कहाँ जाये। कुतुबपुर से सटे कोट्वापट्टी रामपुर, रायपुर, बिंदगोवा

व बड़हरा महाजी अन्य पंचायतें हैं। लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है। अब नदी इनके खेतों को निगलने लगी है। 75 फीसद भूमिखंड में सरयू, गंगा नदी का राग है। टापू सदृश गांव है। 2010 से निमाणधीन छपरा आरा पुल से कुछ उम्मीद जगी है, लेकिन फिलहाल नाव से आने-जाने की व्यवस्था है। अस्पताल है ही नहीं। बाढ़ की तबाही अलग से झेलना पड़ता है। प्रत्येक साल किसानों को परवल की खेती में बाढ़ आने पर लाखों-करोड़ों रूपयों का घाटा सहन पड़ता है। सुविधा के नाम पर इस गांव में पक्की सड़क तक नहीं है। छपरा- लोक कलाकार भिखारी ठाकुर जो समाज के न्यूनतम नाई वर्ग में पैदा हुए थे, वे अपनी नाटकों, गीतों एवं अन्य कला माध्यमों से समाज के हाशिये पर रहने वाले आम लोगों की व्याथा कथा का वर्णन किया है। अपनी प्रसिद्ध रचना विदेशिया में जिस नारी की विहर वर्णन एवं सामाजिक प्रताङ्गन का उन्होंने सजीव चित्रण किया है। वही नारी आज साहित्यकारों एवं समाज विज्ञानियों के लिए स्त्री-विमर्श के रूप में चिन्तन एवं अध्यन का केन्द्र-बिन्दु बनी हुई है। भिखारी ठाकुर ने अपने नाटकों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों, विषमता, भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। इस तरह उन्होंने देश के विशाल भेजपुरी क्षेत्र में नवजागरण का संदेश फैलाया। बेमल-विवाह, नशापान, स्त्रियों का शोषण एवं दमन, संयुक्त परिवार के विघटन एवं गरीबी के खिलाफ वे जीवनपर्यन्त विभिन्न कला माध्यमों के द्वारा संघर्ष करते रहे। यही कारण है कि इस महान कलाकार की प्रासांगिकता आज भी बनी हुई है। कभी महार्पिंदित राहुल सांकृत्यायन के जिहें साहित्य का अनगढ़ हीरा एवं भोजपुरी का शेक्सपीयर कहा था उस भिखारी ठाकुर का जन्म सरण जिले के छपरा जिले के सदर प्रखंड के कुतुबपुर दियारा में 18 दिसंबर 1847 को हुआ को हुआ था। उनके पिता का नाम दलश्रीगार ठाकुर एवं माता का नाम शिवकली देवी था। भिखारी ठाकुर निरक्षर थे, परंतु उनकी साहित्य-साधना बेमिसाल थी। रोजी-रोटी कमने के लिए वे पश्चिम बंगाल के मेदनीपुर नामक स्थान पर गये जहां बंगाल के जातरा पाटियों के द्वारा किये जा रहे रामलीला के मंचन से वे काफी प्रभावित हुए, और उससे प्रेरणा पाकर उन्होंने नाच पार्टी का गठन किया। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के समस्त साहित्य का संकलन अब तक पूरा नहीं हो सका है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना के पूर्व निदेशक प्रो० डॉ० वीरेन्द्र नारायण यादव के प्रयास से परिषद ने रचनाओं का एक संकलन भिखारी ठाकुर ग्रंथालयी के नाम से प्रकाशित किया है, परंतु अभी भी उनके लिए बहुत कुछ किये जाना बाकी है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में उनपर शोध-कार्य चल रहे हैं। कई पुस्तकें भी उनसे प्रकाशित हुई हैं।

जानिए क्यों बाढ़ के पानी के बीच चिंतन मुद्रा में है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही यह तस्वीर है बैकुंठपुर गोपालगंज से भाजपा के पूर्व विधायक और वर्तमान में बिहार प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी की जो अपने क्षेत्र बैकुंठपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके में बैठे गहन चिंतन मनन में लगे हुए उन्होंने इस तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है और साथ में एक विचारोत्तेजक कविता की चार पंक्तियां लिखी हैं इस कविता के लाइनों में बहुत कुछ छूपा हुआ है मिथिलेश कुमार तिवारी विधायक का चुनाव हारने के बाद से ही बैकुंठपुर में कुछ ज्यादा ही सक्रिय है इन्हीं के सोच के परिणाम स्वरूप नारायणी रिवर फ्रांट का निर्माण डुमरिया घाट जो बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है में किया गया है हाल ही में दिल्ली में कई मंत्रालयों में जाकर इन्होंने बैकुंठपुर गोपालगंज समेत पूरे सारण प्रमंडल के विकास के लिए कई योजनाओं की गुहार लगाई है पटना में होते हैं तो क्षेत्र के समस्याओं को लेकर सीधे विभागीय मंत्रियों तक पहुंच जाते हैं मिथिलेश कुमार तिवारी ने इस संदर्भ में बताया कि फर्क नहीं पड़ता कि आप चुनाव जीते हैं या हारे हैं फर्क पड़ता है कि जनता जब संकट में होती है तब आप कहां होते हैं जनता को आप से ढेर सारी आशा होती है जनता को लगता है कि नेता उनका नेतृत्व करेगा और संकट की इस घड़ी में सदैव बैकुंठपुर के लोगों के बीच है बाढ़ की समस्या ने उन्हें भी आहत किया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ की समस्या के स्थाई निराकरण के लिए विधायक रहते ही उन्होंने कई सारी कारी योजनाओं को बनाकर राज्य और केंद्र सरकार को सौंपा है जिस पर काम भी हो रहा है सारण तटबंध के पक्कीकरण नदी के गांद की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था इसमें प्रमुख है।



अब अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होने जा रहा है पटना का तारामंडल

पटना। राजधानी पटना के बेली रोड पर अवस्थित तारामंडल नवीनीकरण के बाद नए तकनीकों से लैस होने जा रहा है इस संदर्भ में आज एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है जिसके अंतर्गत तारामंडल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने इस अवसर पर कहा कि विभाग अत्याधुनिक तकनीकों से पूरी तरह से लैस हो रहा है यह बिहार के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा इसी कड़ी में तारामंडल के नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर तारामंडल पटना के वर्तमान 'झस्तझस्तूलूलू' स्थैतिक झस्तल २८२३१ एवं डोम स्क्रीन के स्थान पर अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित ३डी २ डी आरजीबी लेजर प्रोजेक्शन और चैन सर्पेंडेड डोमस्क्रीन तथा ऑप्टिकल टेलीस्कोप के अधिष्ठापन हेतु ३६ करोड़ १३ लाख २० हजार की लागत से आवश्यक सिविल एलिट्रिकल एवं उन्नयन कार्य का कार्यान्वयन नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम के माध्यम से ट्रन की बेसिस पर २ वर्षों में पूरा करने हेतु बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना एवं नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम कोलकाता के बीच आज दिनांक ९ जुलाई को बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह की गरिमामय उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया समिति पत्र में निर्धारित शर्तों



के अनुसार स्वीकृत राशि छतीस करोड़ तेरह लाख २० हजार का १५% ५४१९८००० तत्काल विमुक्त की गई है। नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम कोलकाता भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत मंत्रालय अंतर्गत स्वशासी संस्था है। जिसके माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों पर साइंस सेंटर, साइंस सिटी, इन्नोवेशन हब का निर्माण और विकास किया जाता है। बिहार काउंसिल आफ साइंस एंड

टेक्नोलॉजी पटना की ओर से डॉ अनंत कुमार, परियोजना निदेशक एवं नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम कोलकाता की ओर से श्री सुरेंद्र कुमार निदेशक मुख्यालय द्वारा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। इस अवसर पर सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग लोकेश कुमार सिंह निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संजीव कुमार एवं बी सी डी के कर्मचारी भी उपस्थित थे।

बिहार में लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री की कुसी

संभाल चुके सुशील मोदी कैबिनेट मंत्री बनने की चाहत रखते थे। हालांकि उन्होंने अपनी इस चाहत को जगजाहिर नहीं किया था, लेकिन दावेदार वह भी कैबिनेट मंत्री के थे। आखिर क्या वजह है कि उन्हें भी नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से बाहर रहना पड़ा है?

केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अटल-आडवाणी से बिल्कुल भिन्न है। यह जोड़ी अच्छे-बुरा का याद लंबे समय तक रखने वाली है। बात तब की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अमित शाह कोर्ट कच्चहरी के चक्कर में थे। कुछ कारणों से अमित शाह को गुरु से बाहर रहना था। वो पटना में रुके हुए थे। उस समय सुशील मोदी बिहार के उपमुख्यमंत्री हुआ करते थे। सुशील मोदी का कद अमित शाह से ज्यादा होता था। अमित शाह, सुशील मोदी से मिलने का कई बार वक्त माँगा लेकिन ये नहीं मिले। दूसरी घटना तब की है, जब भाजपा और संघ के कद्दावर नेता संजय भाई जौशी को केंद्रीय नेतृत्व से किनारा किया गया था तो इन्होंने खुलकर श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया था।



सुशील मोदी बिहार भाजपा पर दो दशक से अधिक समय तक राज किया। उन्होंने राजनीति बस नेताओं कि की, आम जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए। अतः केन्द्रीय नेतृत्व को यह जात है कि

इनके नाराज होने से बोट पर कोई असर नहीं होगा। अपने विरोधियों को कुचलते रहे और सफल भी, लेकिन विरोधियों की तादाद इतनी लंबी हो गई कि ये उनके नीचे दबते चले गए और जबतक पता चला तबतक काफी देर हो चुकी थी।

बिहार भाजपा के अंदर का विवाद भी सुशील मोदी के केन्द्र में मंत्री बनने की राह में बढ़ा रोड़ा साबित हुआ। सुशील मोदी के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी केन्द्र में मंत्री बनने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे थे। सुशील मोदी की दावेदारी को संजय जायसवाल ने एक तरह से चुनौती दे रखी थी।

सुशील मोदी की तुलना में संजय जायसवाल भाजपा के केन्द्रीय संगठन की लॉबी में ज्यादा मजबूत थे। संजय जायसवाल को ये मजबूत लॉबी भले ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल तक नहीं पहुंचा पाई, लेकिन इस लॉबी ने सुशील मोदी को मंत्री बनने से जरूर रोक दिया। इसी आंतरिक विवाद में इस बार बिहार भाजपा के हाथ खाली रह गए हैं।

बिहार के विकास के मुद्दे पर राज्य के कृषि मंत्री के साथ नजर आए बिट्कोमान चेयरमैन व राजद विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह

बिहार में सत्ता और विपक्ष के बीच रिश्ते कितने खटास से भरे हुए हैं यह बताने की जरूरत नहीं आमतौर पर किसी भी मंच पर विपक्ष के लोग सत्ता के लोगों के साथ नजर नहीं आते हैं पर आज असें बाद बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में बिस्कोमान के चेयरमैन सह राजद विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह नजर आए। खुद उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी उन्होंने लिखा है कि आज बिहार के कृषि मंत्री माननीय श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा वर्चुअल ड्राइविंग दिखाकर विश्व चर्चित नैनों तरल यूरिया की पहली खेप कलोल, गुजरात से बेतिया, बिहार के लिए रवाना किया गया, इस ऐतिहासिक अवसर के मुख्य साक्षी इफको के उपाध्यक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष बड़े भाई श्री दिलीप संघाणी जी, नैनो फर्टिलाइजर के जनक इफको के प्रबंध निदेशक डॉ उदय शंकर अवस्थी जी, इफको के विपणन निदेशक श्री योगेन्द्र कुमार एवं इफको के माननीय निदेशक श्री प्रेमचंद मुंशी जी भी इस अवसर के भागीदार थे। विश्व में पहली बार डॉ यू एस अवस्थी के दूरदर्शिता का परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में नई क्रांति का आगाज किया गया। चौंक यह कार्यक्रम माननीय कृषि मंत्री के सरकारी आवास में था, जिसमें उन्होंने मुझे अंगवस्त्रम एवं पुष्प गुच्छ से सम्मानित कर अभिभूत कर दिया।

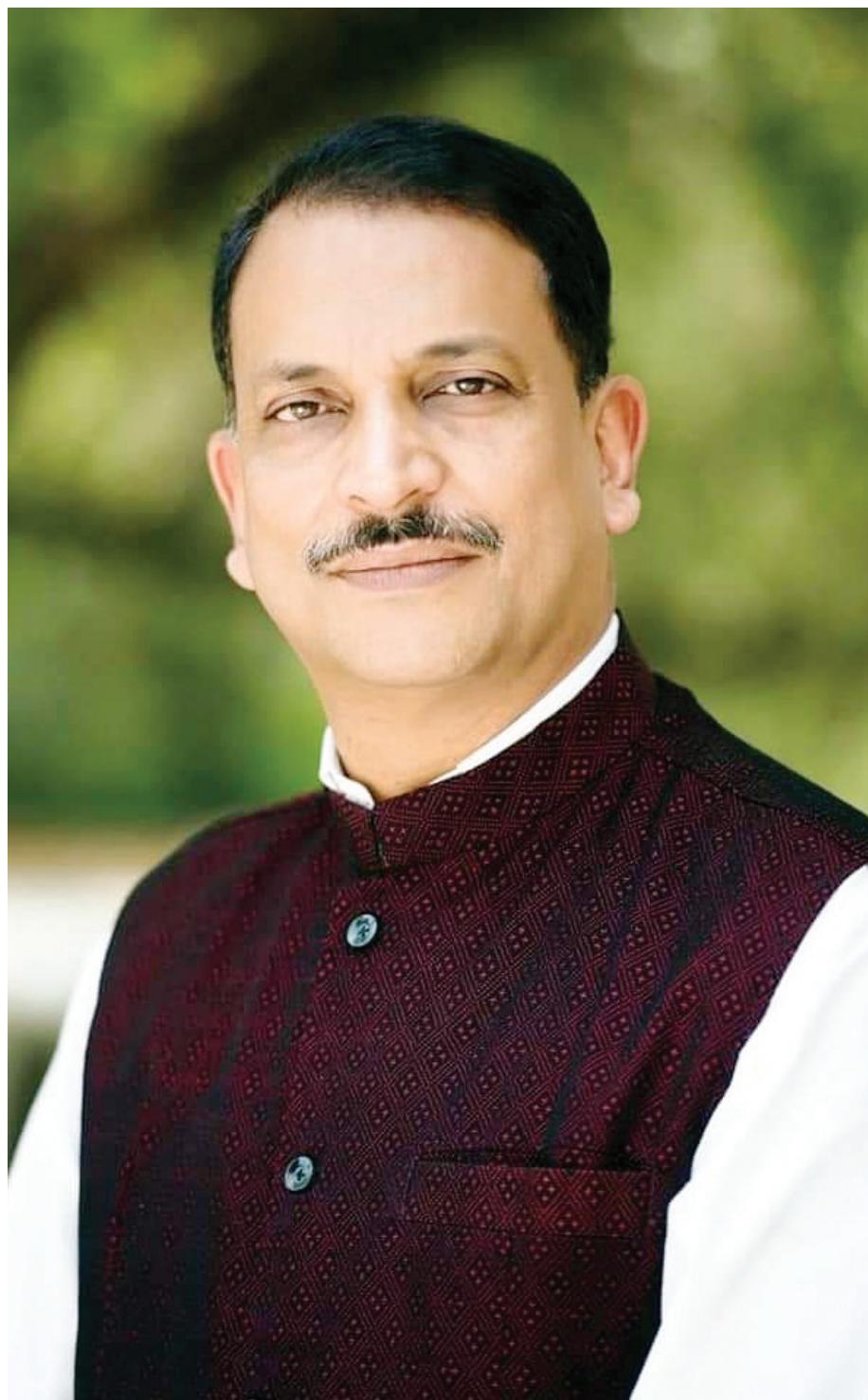


कब समाप्त होगा रूडी का अङ्गातवास...

अनूप नारायण सिंह

भाजपा के युवा तुर्क के नेताओं में शुभार सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं यह ना तो उन्हें पता है और ना ही उनके चाहने वाले समर्थकों को जब कभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है पूरे सारण प्रमंडल में यह बात लोगों के जेहन में आने लगती है कि शायद इस बार कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में राजीव प्रताप रूडी भी शपथ ग्रहण करें पर हर बार पार्टी के द्वारा उन्हें नजरअंदाज ही कर दिया जाता है बावजूद इसके राजीव प्रताप रूडी पहले से ज्यादा प्रखर हो गए हैं और क्षेत्र के लोगों के बीच लोकप्रिय भी लगातार सारण के लोगों से कनेक्ट रहते हैं। बिहारके छपरा में 30 मार्च, 1962 को जन्मे रूडी ने अपनी प्रार्थिक शिक्षा पट्टना के सेंट माइकल्स हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आ गए और पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अर्थशास्त्रमें मास्टर डिग्री करने के बाद उन्होंने बिहार के मगध विश्वविद्यालयमें प्रवक्ता की नौकरी शुरू की। उन्होंने बिहार की भी पढ़ाई की है। रूडीने अपने राजनीतिक करियर की शुरूआत जनता दल के साथकी। 1990 में उन्होंने जनता दल के ही टिकट पर बिहार के तरेयाविधानसभा से सीट से विधायक चुना गया। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीते। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के अगुवाईवाली एनडीए की सरकार में 1999 में वह दूसरी बार सांसद चुने गए। वाजपेयी की सरकार में ही उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री का कार्यभार सौंपा गया। बाद उन्हें उद्योग मंत्रालय में काम करने का मौका मिला। सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई। साल 2010 में रूडी को बिहार से राज्यसभा सांसद चुना गया और 2014 में तुलसीकालीन उन्होंने राबड़ी देवी को हराकर एक बार फिर से सांसद बन गए। रूडीका राजनैतिक करियर बहुत ही शानदार रहा है।

उन्होंने अपने 25 साल के लिए कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और उसे बखूबी निभाया भी। 2014 के चुनावों में भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को हराया और बिहार में सारण निर्वाचन क्षेत्र के सांसद बने। वे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे। वे नरेंद्र मोदी की सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) थे, लेकिन बाद में 2017 में कैबिनेट फेरबदल में उन्हें पद से हटा दिया गया। उन्हें तीन बार लोकसभा के लिए चुना गया और वर्तमान में वे सारण के सांसद के रूप में कार्य कर रहे हैं। दिसंबर 2018 में उन्हें पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र के प्रभारी के रूप में उन्होंने ऐसा कार्य किया कि भाजपा शिवसेना से अलग



अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हुई बल्कि महाराष्ट्र में सरकार भी बनाने में सफल हुई। पर बिहार का यह चमकता सितारा साजिशों का शिकार हो गया वह भी अपने लोगों के द्वारा। सारण की जनता बिहार की जनता और उसके लाखों चाहने वाले जानना चाहते हैं कि आखिर साफ-सुथरी प्रगतिशील छवि वाले इस नेता को

केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान क्यों नहीं मिल पा रहा है। वे कौन लोग हैं जो राजीव प्रताप रूडी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होकर देश के विकास का वाहक बनाया था वह एक सांसद के रूप में अपने संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित होकर क्यों रह गया है।

डिजिटल मीडिया आचार संहिता का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना - विक्रम सहाय

अनूप नारायण सिंह

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए ओटीटी प्लेटफार्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री के गुणवत्ता को बनाये रखना है। पत्र सूचना कार्यालय (पटना, लखनऊ, रांची एवं देहरादून) द्वारा डिजीटल मीडिया आचार संहिता 2021 पर एक विशेष ई-बैठक को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विक्रम सहाय ने यह बात कही। इस ई-बैठक में आचार संहिता के भाग-3 से जुड़े प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए श्री सहाय ने बताया कि आचार संहिता का उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल मीडिया की भूमिका काफी बढ़ी है और पिछले 6 वर्षों में इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल 43 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। उन्होंने बताया कि ओटीटी प्लेटफार्म पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जिसके मद्देनजर डिजिटल मीडिया आचार संहिता बनायी गयी है। इसके तहत न्यूज पोर्टल या ओटीटी प्लेटफार्म पर काम कर रहे लोगों के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सामान्य जानकारी एकत्रित करेगा।

श्री विक्रम सहाय ने बताया कि इन प्लेटफार्म पर भी देश के मौजूदा कानून लागू होंगे और इसका उद्देश्य ऐसी सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाना है जो मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करते हैं। साथ-साथ ऐसी सामग्री के प्रसारण को विनियमित करना भी है जो महिलाओं के लिए आपत्तिजनक और बच्चों के लिए नुकसानदेह है। इसके लिए समाचार प्रकाशकों, ओटीटी प्लेटफार्म और कार्यक्रम प्रसारकों को अपने यहां एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और इन शिकायतों की जानकारी भी प्रदर्शित करनी होगी। इसके साथ ही समाचार प्रकाशकों को एक नियामक संस्था का सदस्य भी बनना होगा ताकि कार्यक्रम से संबंधित शिकायतों का निपटारा हो सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक अन्तर-मंत्रालय समिति का गठन करेगा, जो समाचार प्रकाशक या नियामक संस्था द्वारा न सुलझायी गयी शिकायतों का निपटारा करेगा।

इस समिति में महिला एवं बाल विकास, गृह, विधि, सूचना प्रदौगिकी, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ डोमेन एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। श्री सहाय ने बताया कि अब तक लगभग 1800 समाचार प्रकाशकों ने मंत्रालय को अपने बारे में सूचना दे दी है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय किसी भी न्यूज पोर्टल या ओटीटी प्लेटफार्मों का पंजीकरण नहीं कर रहा है बल्कि इनके बारे में जानकारी जुटाने का उद्देश्य यह है कि कार्यक्रम के बारे में कोई शिकायत मिलने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे छोटे और मझोले स्तर के समाचार पोर्टल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री सहाय ने बताया कि इस आचार संहिता का उद्देश्य समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्रस्तुतकार्ताओं को उन नियमों और मयार्दाओं के बारे में जागरूक करना है, जिनके पालन से देश की एकता, अखंडता एवं सौहार्द कायम रह सके।

ई-बैठक का संचालन करते हुए पत्र सूचना कार्यालय, पटना के निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि पत्र सूचना कार्यालय, पटना, लखनऊ, रांची और देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस ई-बैठक में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड और उत्तरखण्ड के प्रमुख समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफार्म पर काम कर रहे नियमार्दाओं व निदेशकों के साथ-साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं पत्रकारिता से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। साथ ही पत्र सूचना कार्यालय, पटना के अपर महानिदेशक एस के मालवीय, पत्र सूचना कार्यालय, लखनऊ के अपर महानिदेशक श्री आर. पी. सरोज, पत्र सूचना कार्यालय, झारखण्ड के अपर महानिदेशक श्री अरिमर्दन सिंह एवं रीजनल आउटरीच ब्यूरो, देहरादून की प्रभारी डॉ. संतोष आशीष इस ई-बैठक में मौजूद थे। ई-बैठक में चारों राज्यों के प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रोफेसर सहित



पत्रकारिता विभागों के संकाय सदस्यों ने भाग लिया। श्री विक्रम सहाय ने इस विषय पर उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिये। प्रतिभागियों की ओर से दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए संयुक्त सचिव श्री सहाय ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि डिजिटल मीडिया आचार संहिता पर ऐसे कई कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर, खास कर पत्रकारिता से जुड़े संस्थानों के साथ, आयोजित किए जाएं।

ई-बैठक में बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतीहारी, मगध विश्वविद्यालय बोध गया, पटना विश्वविद्यालय, चानक्या लॉ यूनिवर्सिटी पटना, एमटी यूनिवर्सिटी पटना, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, रांची विश्वविद्यालय एवं पत्रकारिता व फिल्म निर्माण से जुड़ी संस्थाओं ने भाग लिया। ई-बैठक के अन्त में पत्र सूचना कार्यालय, झारखण्ड के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

महापुरुषों से प्रेरित होता हूँ: विकास वैभव

आमतौर पर आप अपने जीवन में किसी ना किसी से जरूर प्रभावित होते हैं उनके जैसा बनना चाहते हैं उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर कुछ बेहतर करना चाहते हैं लोग अपने माता पिता गुरु महापुरुषों से प्रेरित होते रहते हैं होना भी चाहिए। मैं भी अपने माता पिता अपने गुरुजनों को अपना आदर्श मानता हूँ महापुरुषों से प्रेरित होता हूँ लेकिन समकालीन लोगों में जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया अकेले संघर्ष करने की प्रेरणा दी कठिन से कठिन परिस्थिति में मुस्कुराने की ताकत दी उस व्यक्ति का नाम है बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तथा वर्तमान में बिहार सरकार गृह विभाग में विशेष सचिव श्री विकास वैभव जी का।

एक कड़क पुलिस पदाधिकारी होने के बावजूद विकास वैभव जी ने इतिहास के पन्नों को फिर से पलटने पर मजबूर किया यात्री मन के बहाने उनके सैकड़ों आलेख पढ़ने के बाद बिहार को और करीब से जानने का मौका मिला जो ज्ञान आपको किताबों में इंटरनेट पर नहीं

उपलब्ध था उसे उन्होंने सहजता के साथ उपलब्ध करवाई। उच्छकर अपनी भागीदारी उन्होंने सुनिश्चित की जितनी बार इनसे मिलने का मौका मिला उतनी बार उनके जीवन के उस व्यापकता को और नजदीक से समझने का हमें मौका भी मिलता गया। एक इंसान कैसे भीड़ से अलग खड़ा होकर नेतृत्वकर्ता बन जाता है।

तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जब भी युवाओं

पर आमतौर पर आपने जीवन में किसी ना किसी से जरूर प्रभावित होते हैं उनके जैसा बनना चाहते हैं उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर कुछ बेहतर करना चाहते हैं लोग अपने माता पिता गुरु महापुरुषों से प्रेरित होते रहते हैं होना भी चाहिए। मैं भी अपने माता पिता अपने गुरुजनों को अपना आदर्श मानता हूँ महापुरुषों से प्रेरित होता हूँ लेकिन समकालीन लोगों में जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया अकेले संघर्ष करने की प्रेरणा दी कठिन से कठिन परिस्थिति में मुस्कुराने की ताकत दी उस व्यक्ति का नाम है बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तथा वर्तमान में बिहार सरकार गृह विभाग में विशेष सचिव श्री विकास वैभव जी का।

एक कड़क पुलिस पदाधिकारी होने के बावजूद विकास वैभव जी को जानना जरूरी है सहज है सुलभ है और सबसे बड़ी बात कि लगातार नई नई खोजों में लगे रहते हैं मिलने जुलने वालों का तांता लगा रहता है पर जो व्यक्ति मिलता है बिना प्रभावित हुए नहीं जाता ज्ञान विज्ञान की बात होती है बिहार के बदलाव की बात होती है युवाओं की रोजगार की बात होती है बिहार कैसे विकसित हो बिहार कैसे सशक्त हो युवा कैसे आदर्श बने कैसे हर हाथ को काम मिले ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बिहार कैसे

विकसित करें हमेशा इसकी पीड़ा इनके अंदर झलकती है और सदैव लोगों से इसी विषय पर चर्चा करते हैं।

बिहार के सभी युवाओं को जागृत करने के लिए इन्होंने एक अभियान की तैयारी कर रखी है जिसके तहत पूरे बिहार के युवा बिहार को विकसित करने समाज को समृद्ध करने खुद को सशक्त करने के विषय पर मंथन करेंगे उसे अपने आहर व्यवहार में भी उतारेंगे। लेटेस्ट इंस्पायर बिहार के नाम से यह अभियान बहुत जल्द वास्तविकता के धरातल पर भी नजर आएगा।

आइए ! मिलकर प्रेरित करें बिहार ! #LetsInspireBihar मुहिम से जुड़ने के लिए नीचे दिए लिंक क्लिक करें ! <https://forms.gle/bchSpPkspnYEMHeL6>



"Let's Inspire Bihar ! या आईए, मिलकर प्रेरित करें बिहार ! क्या है ?



विकास वैभव

"राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका" तथा "सफलता के सूत्रों" समेत अनेक विषयों पर भौतिक समेत डिजिटल माध्यमों से लंबे समय से बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं से वार्ता करता रहा हूँ जिसके विवरण सोशल मीडिया पर भी समय-समय पर साझा करता रहा हूँ। इस बिहार दिवस पर जब अपनी अवधारणा को और स्पष्ट करते हुए मैंने आद्वान स्वरूप "Let's Inspire Bihar ! शीर्षक का प्रयोग एक हैशटैग LetsInspireBihar के साथ किया, तब से ही अनेक युवा साथी इसके संदर्भ में अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त करते रहे हैं। अतः आज इसके संदर्भ में आवश्यक विवरण आपके साथ साझा करना चाहता हूँ।

LetsInspireBihar क्या है, यह जानने के पूर्व सर्वप्रथम आप स्वयं से यह प्रश्न करें कि क्या आप मानते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष के उज्ज्वलतम भविष्य की प्रबल संभावनाएं कहीं न कहीं उसी भूमि में समाहित हो सकती हैं जिसने इतिहास के एक कालखंड में संपूर्ण अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व किया था और वही भी तब जब न आज की भाँति संचार के माध्यम थे, न विकसित मार्ग और न प्रौद्योगिकी !

आप स्वयं से यह प्रश्न करें कि क्या हमें यह स्मरण नहीं है कि बिहार ही ज्ञान की वह भूमि है जहाँ वेदों ने

भी वेदांत रूपी उत्कर्ष को प्राप्त किया तथा ज्ञान के प्राचीन बौद्धिक परंपरा की जब अभिवृद्धि हुई तब इसी भूमि ने बौद्ध और जैन धर्मों के दर्शन सहित अनेक तत्वों एवं सिद्धांतों के जन्म के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना देखी। जहाँ ज्ञान की ऐसी अद्भुत प्रेरणा रही, वहाँ शैर्य का परिलक्षित होना भी स्वाभाविक ही था और इसी कारण इतिहास स्वयं साक्षी है कि कभी बिहार से ही संपूर्ण अखंड भारत का शासन संचालित था और वह भी सशक्त एवं प्रबल रूप में। उचिता की इस प्राचीन भूमि ने ही ऐतिहासिक काल में ऐसी प्रेरणा का संचार किया जिसके कारण दक्षिण पूर्वी एशिया के नगरों तथा यहाँ तक कि राष्ट्रों का भी नामकरण भी इसी भूमि के प्रेरणादायक नगरों के नामों पर होने लगे जिसका सबसे सशक्त उदाहरण वियतनाम है जो चंपा (वर्तमान भागलपुर, बिहार) के ही नाम से लगभग 1500 वर्षों तक संपूर्ण विश्व में जाना गया।

यदि ऐसे प्रश्नों का उत्तर स्वीकारोत्तमक है, तो बस विचार कीजिए कि वैसे सामर्थ्यवान यशस्वी पूर्वजों के ही हम वशज क्या वर्तमान में भारत के उज्ज्वलतम भविष्य के निमित्त अपना सकारात्मक योगदान समर्पित कर पा रहे हैं ? लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में रहे यूनानी गण्डूत मेगास्थीन ने अपने ग्रंथ ईडिका में तत्कालीन पाटलिपुत्र को उस समय के विश्व के सर्वश्रेष्ठ नगर के रूप में वर्णित किया गया था। आप कल्पना

कीजिए कि यदि उस समय किसी पाटलिपुत्र निवासी से 2500 वर्ष पश्चात पाटलिपुत्र के स्वरूप के संबंध में पूछा जाता तो भला किस प्रकार के आशान्वित उत्तर मिल रहते और क्यों वह स्वाभाविक भी प्रतीत होते। परंतु वर्तमान परिदृश्य में जब भी भविष्यात्मक संभावनाओं के विषयों में बिहार के युवाओं से वार्ता होती है, तब ऐसी अनुभूति क्यों होती है कि कहीं न कहीं सर्वत्र एक प्रकार की निराशा व्याप्त हो रही है और वर्तमान एवं भविष्य के संबंध में नकारात्मक विचारों की स्थापना भी युवाओं के मध्य हो रही है जो भारत के उज्ज्वलतम भविष्य हेतु सर्वथा अनुचित है। जिस भूमि ने प्राचीनतम काल में ही ऐसे कीर्तिमानों को प्राप्त किया था, यदि उनकी स्वाभाविक प्राकृतिक अभिवृद्धि भी हुई रहती तो निश्चित ही वर्तमान का स्वरूप अल्पतं भिन्न रहता और निश्चित ही यदि भविष्य की संभावनाओं के संबंध में वर्तमान में प्रश्न किए जाते तो उनके उत्तरों में समाहित आशावादिता के भावों में कोई कमी नहीं रही होती। कालांतर में ऐसा क्या होता गया जिसके कारण जो आशावादित उस काल में स्थान्तरण के साथ परिलक्षित होती थी, वह आज के युवाओं से यह सहित प्रश्न करने पर भी दर्शित नहीं होती ? आखिर ऐसा क्यों है कि जिस क्षेत्र में कभी संपूर्ण विश्व के विद्वान अध्ययन हेतु दुर्लभ मार्गों से सुदूर यात्राएं कर पहुँचें हेतु लालायित रहते थे, वहीं के विद्यार्थी आज परिश्रम एवं पुरुषार्थ के मार्गों से कई अवसरों पर विच्छिन्न प्रतीत होते

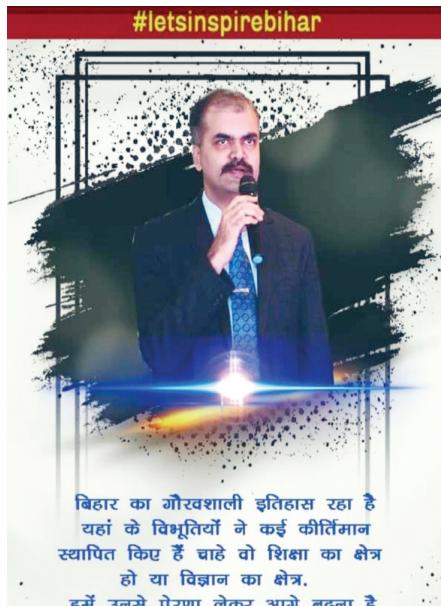
दिखते हैं तथा अधिकांशतः अन्य क्षेत्रों में अध्ययन एवं जीवनयापन हेतु प्रयासरत रहते हैं ?

यदि हो रही निराशा के प्रतिकर हेतु यह चिंतन करना आवश्यक होगा कि यदि स्वाभाविक उत्कर्ष की प्राकृतिक परंपरा बाधित हुई और जैसी कल्पना कभी रही होगी, वैसा क्यों नहीं हो सका ! ऐतिहासिक भूमि के स्वाभाविक प्राकृतिक विकास की परंपरा से अत्यंत भिन्न ऐसी अप्राकृतिक वर्तमान परिस्थितियों के प्रादुर्भाव के कारणों पर चिंतन करने से ही समाधान मिलेंगे चूंकि भूमि वही है, उर्जा भी वही है और इसमें भला कहाँ सदैह है कि हम उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के वंशज हैं जिनकी प्रेरणा आज भी मन को उद्घेलित करती है और कहती है कि यदि संकल्प सुदृढ़ हो तो इच्छत परिवर्तन अपने माध्यम स्वतः तय कर लेते हैं ।

यदि हम इतिहास में प्राप्त उत्कर्ष के कारणों पर चिंतन करें तो पाएंगे कि हमारे पूर्वजों की सोच अत्यंत बृहत् थी जो लघुवादों से विभिन्न थी । उर्जा के साथ जिज्ञासा तो हमारे पूर्वजों की ऐसी थी जो सामान्य भौतिक ज्ञान से संतुष्ट होने वाली नहीं थी तथा सत्य के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहती थी जिसके कारण ज्ञान परंपरा के उत्कर्ष को समाहित किए, उपनिषदों की दृष्टि संभव हो सकी । यदि भूमि के ऐतिहासिक शौर्य के कारणों पर हम चिंतन करें तो वहाँ भी बुहता के लक्षण तब स्पष्ट होते हैं जब हम महाजनपदों के उदय के क्रम में पाठलिपुत्र में महापद्मनंद के राज्यारोहण का स्मरण करते हैं चूंकि जिस काल में अन्य जनपदों में जहाँ पूर्व से स्थापित शाशक वर्ग के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग से सम्बद्ध शासक की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, मगध में केवल सामर्थ्य को ही कुशल शासकों हेतु उपयुक्त लक्षणों के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई थी । ऐसे चिंतन के कारण ही मगध का सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय हुआ जिसने कालांतर में साप्राज्य का रूप ग्रहण कर लिया । उत्कृष्ट चिंतन के कारण जहाँ राजतंत्र के रूप में मगध का उदय हुआ, वहीं वैशाली में गणतंत्र की स्थापना भी हुई । यदि कालांतर में ऐसे शौर्य का क्षय हुआ तो उसके कारण शस्त्र और शास्त्र में समन्वय का अभाव ही रहा चूंकि इतिहास स्वयं साक्षी रहा है कि भले ही शास्त्रीय ज्ञान अपने चरम उत्कर्ष पर क्यों न हो, यदि शस्त्रों के सामर्थ्य में कमी आती है तो उत्कृष्ट शास्त्र भी नष्ट हो जाते हैं ।

यदि कालांतर में हमारा अपेक्षाकृत विकास नहीं हुआ और यदि हम पूर्व का स्मरण करते हुए वर्तमान में वैसा तारतम्य अनुभूत नहीं करते तो इसका कारण कहीं न कहीं समय के साथ लघुवादों अथवा अतिवादों से ग्रसित होना ही रहा है अन्यथा जिस भूमि ने इतिहास के उस काल में कभी महापद्मनंद को शाशक के रूप में सहर्ष स्वीकार जन्म विशेष के लिए नहीं परंतु उनकी क्षमताओं पर विचारण के उपरांत किया था, उसके उज्ज्वलतम भविष्य में भला सदैह कहाँ था ।

यदि वर्तमान में हम विकास में अन्य क्षेत्रों से कहीं पछड़े हैं और अपने भविष्य को उज्ज्वलतम देखना चाहते हैं तो आवश्यकता केवल और केवल अपने उन यशस्वी पूर्वजों का स्मरण करते हुए लघुवादों यथा जातिवाद, संप्रदायवाद इत्यादि से उपर उठकर राज्य एवं राष्ट्रहित में बृहतर चिंतन के साथ भविष्यात्मक दृष्टिकोण को मन में स्थापित करते हुए निज सामर्थ्यानुसार आशिक ही सही परंतु निखार्थ सामाजिक योगदान अवश्य समर्पित करना होगा । आवश्यकता एक वैचारिक क्रांति की है जो



आइए मिलकर बिहार को प्रेरित करें

युवाओं के मध्य प्रसारित हो और जो भविष्य निर्माण के निमित्त संगठित रूप में संकल्पित करे । परिवर्तन ही ऋत है ! आवश्यकता आशावादिता के साथ आगे बढ़ने की है । जिस भूमि ने वैदिक काल से ही गांगी वाचकनवी एवं मैत्रीयी जैसी विद्युषियों को नारी में भी समाहित विद्वता का प्रतिनिधित्व करते देखा हो, उसका भविष्य भला उज्ज्वलतम क्यों न हो ।

अब यदि इस पर चर्चा करें कि ""Let's Inspire Bihar !!" के अंतर्गत करना क्या है तो वह भी स्पष्ट करता हूँ :-

1. अपनी समृद्ध विरासत तथा स्वयं की क्षमता को जानिए एवं समझिए ।
2. मानवीय क्षमता के चरमोत्कर्ष की चर्चा करते हुए मैंने उपनिषदों के अत्यंत प्रेरणादायक एवं महत्वपूर्ण श्लोक "ऊँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाऽपूर्णमुदच्यते ।" पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमिवा वसिष्यते ।"

को अनेक अवसरों पर उद्धृत किया है जिसमें यह वर्णन मिलता है कि पूर्ण को खण्डित करने पर भी हर खण्ड पूर्ण ही रहता है और युनः पूर्ण में ही विलीन हो जाता है; अर्थात् हर आत्मा जो परमात्मा का ही अंशरूप है उसमें उसके सभी गुण समाहित हैं । ऐसे में युवा मन में अपने सामर्थ्य के प्रति किसी प्रकार का सदैह न हो इसके लिए यह अनुभूति आवश्यक है कि इश्वर (पूर्ण) की वह असीम शक्ति सभी के अंदर पूर्णतः समाहित है और सदैव सही मार्गदर्शन हेतु तत्पर भी है । ऐसे में कहीं और न देखकर यदि हम एकाग्रचित् होकर गहन आत्मचिंतन करें तो सभी के लिए स्वयं मार्गदर्शक तथा इच्छित परिवर्तन के प्रबल वाहक बन जाएंगे ।

3. यह समझना होगा कि स्वयं के सामर्थ्य को जाने बिना जब कई बार दूसरों के अनुसरण के कारण हम अपने मूल्यों से दिग्भ्रमित हो जाते हैं, तब हमारा अपनी मूल क्षमताओं से विश्वास डिग जाता है, जो सर्वथा अनुचित है ।

4. यह समझना होगा कि यदि हम प्रतिकूल परिस्थितियों के समक्ष निराश होते हैं तो हम युवावस्था में

समाहित उस असीम उर्जा के स्रोत से संभवतः स्वतः विच्छिन्न होते जाते हैं जिसके मूल में आशावादिता एवं सकारात्मकता सन्निहित है ।

5. यदि अपने पूर्वजों के कृतियों से आप प्रेरित हैं और स्वयं की असीमित क्षमताओं के विषय में स्पष्ट हैं तो केवल स्वयं तक सीमित मत रहिए, इस अद्भुत प्रेरणा का प्रसार कीजिए ।

6. लघुवादों यथा जातिवाद, संप्रदायवाद, लिंगभेद आदि संकीर्णताओं से परे उठकर बिहार तथा भारत के उज्ज्वलतम भविष्य के निर्माण हेतु बृहत् चिंतन करें तथा दूसरों को भी प्रेरित करें ।

7. प्रेरित युवा संगठित होने का प्रयास करें जिससे नकारात्मकता के विरुद्ध युद्ध हेतु संकल्पित सकारात्मक विचारों की शक्ति प्रबल हो उठे । संगठन को बृहत् स्वरूप प्रदान करें हेतु "Let's Inspire Bihar !" के जिलावार चैप्टरों से सोशल मीडिया एवं भौतिक माध्यमों से जुड़ें जिनकी स्थापना आपके जिले के प्रेरित युवा समन्वयकात्माओं द्वारा की जा रही है । बिहार के सभी जिलों के युवाओं और अप्रवासी बिहारवासियों के लिए भी प्रारंभ में सोशल मीडिया के माध्यमों ही चैप्टरों को प्रारंभ किया जा रहा है जिनसे जुड़ने के लिए आप अपने जिले या नगर से संबंधित फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं अथवा ""Let's Inspire Bihar !!" पर अपने नाम, उम्र, जिला का नाम और दूरभाष संख्या के साथ इमेल कर सकते हैं ताकि आपके क्षेत्र से संबंधित समन्वयकर्ता आपसे संपर्क स्थापित कर सकें ।

8. प्रेरित युवाओं के साथ अपने व्यस्त समय में से कुछ समय सकारात्मक सामाजिक गतिविधियों के निमित्त चिंतन एवं योगदान हेतु भी समर्पित करें ।

9. जो लघुवादों से ग्रसित हैं तथा दिग्भ्रमित हो रहे हैं उनके मार्गदर्शन हेतु अपने स्तर से भी प्रयास करें । उन्हें समझाने का प्रयास करें कि यदि व्यक्ति अपने वास्तविक सामर्थ्य को जान ले तथा सफलता प्राप्त करने के निमित्त अत्यंत परिश्रम करे तो कोई भी लक्ष्य असाध्य नहीं रह जाता । मिलकर, हम निश्चित ही राष्ट्रहित में अपने जीवन काल में कुछ उत्कृष्ट योगदान समर्पित कर सकते हैं ।

10. सकारात्मकता विचारों एवं प्रेरणादायक उदाहरणों को सोशल मीडिया पर "Let's Inspire Bihar !" हैशटैग के साथ साझा करें ।

भविष्य परिवर्तन के निमित्त युवाओं द्वारा संकल्पित सकारात्मक चिंतन एवं योगदान ही बिहार के उज्ज्वलतम भविष्य की दिशा स्थापित करने का एकमात्र विकल्प है । इतिहास की प्रेरणा में ऐसी अद्भुत शक्ति समाहित है जो बिहार समेत संपूर्ण भारतवर्ष के भविष्य को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है । मन भविष्यात्मक दृष्टिकोण के निमित्त विशेषकर युवाओं से स्वरचित पक्षियों के माध्यम से आह्वान करना चाहता है -

"पूर्व प्रेरणा करे पुकार, आओ मिलकर गढ़ें नव बिहार ।

नव चिंतन नव हो व्यवहार, लघु वादों से मुक्त हो संसार ।

जान परंपरा का विस्तार, दीर्घ प्रभाव का सतत प्रसार ।

बृहत् चिंतन सह मूल्यों पर, आधारित युवा करें विचार ।"

(लेखक विकास वैश्वर जी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी व बिहार सरकार के गृह विभाग में विशेष सचिव हैं)

सत्ता के लोभी लोग बिहार की जनता के जान के साथ कर रहे हैं खिलवाड़



बिस्कोमान के चेयरमैन व राजद विधानपार्षद **सुनीलकुमारसिंह** ने कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार सत्ता के मद में चूर है यह बिहार के लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है पूरे देश में जहां अन्य राज्य के मुख्यमंत्री कोरोना के बैन को तोड़ने में लगे हुए हैं वहीं बिहार के मुख्यमंत्री दूसरे दलों को तोड़ने फोड़ने में लगे हुए हैं इसका ताजा उदाहरण लोजपा में हुई फूट है। बिहार में 15 वर्षों से ज्यादा समय से सत्तासीन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा करना चाहती है क्यों नहीं बताती है कि बिहार में कितने उद्योग धंधे लगे क्यों नहीं बताती है कि बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर कितना ऊपर उठा है कितने लोगों को रोजगार मिला है कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारी है बाढ़ जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कितना विजय प्राप्त किया गया है लोगों को बरगलाने के लिए आप पिछली सरकारों का दुहाई देते हैं आपको तो जनता ने लगातार जनादेश दिया फिर आप बिहार के विकास से मुंह क्यों चुराते हैं। लालू राबड़ी राज की दुहाई देकर आप बिहार की जनता को कितना ठगने का काम करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह के साथ विशेष बातचीत में राजद विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि इन लोगों को बिहार के विकास से कोई लेना-देना नहीं यह लोग सत्ता के लोभी लोग हैं बिहार की जनता ने आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया आपने जोड़ तोड़ गठजोड़ करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री से बनने से रोकने के लिए साजिश रची जनादेश का अपमान किया। आप की नीति और नीयत सिर्फ और सिर्फ सत्ता कुर्सी

वहीं बिहार के मुख्यमंत्री दूसरे दलों को तोड़ने फौड़ने में लगे हुए हैं इसका ताजा उदाहरण लोजपा में हुई फूट है। बिहार में 15 वर्षों से ज्यादा समय से सत्तासीन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा करना चाहती है कि बिहार में कितने उद्योग धंधे लगे क्यों नहीं बताती है कि बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर कितना ऊपर उठा है कितने लोगों को रोजगार मिला है कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारी है बाढ़ जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कितना विजय प्राप्त किया गया है लोगों को बरगलाने के लिए आप पिछली सरकारों का दुहाई देते हैं आपको तो जनता ने लगातार जनादेश दिया फिर आप बिहार के विकास से मुंह क्यों चुराते हैं। लालू राबड़ी राज की दुहाई देकर आप बिहार की जनता को कितना ठगने का काम करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह के साथ विशेष बातचीत में राजद विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि इन लोगों को बिहार के विकास से कोई लेना-देना नहीं यह लोग सत्ता के लोभी लोग हैं बिहार की जनता ने आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया आपने जोड़ तोड़ गठजोड़ करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री से बनने से रोकने के लिए साजिश रची जनादेश का अपमान किया। आप की नीति और नीयत सिर्फ और सिर्फ सत्ता कुर्सी

के इर्द-गिर्द घूमती है। बिहार के मुख्यमंत्री पर प्रहर करते हुए उन्होंने कहा कि आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपकी नजरों में प्रदेश में विकास की गंगा

बह रही है फिर आप अपना इलाज करवाने दिल्ली क्यों जाते हैं बिहार के हॉस्पिटलों पर आपको भरोसा क्यों नहीं है आप क्या संदेश देना चाहते हैं। विपक्ष की भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में जनबूझकर विपक्ष को तहस-नहस करने की साजिश रची जा रही है विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है विकास योजनाओं में विपक्ष की सहमति तक नहीं ली जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा चुकी है। बिहार की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है जनतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता सब कुछ देख रही है कि अपदा विपदा में आप किस तरह घरों में छुपे हुए हैं जब आपको लोगों के आंसू पोछने चाहिए तब आप अखबारों में विज्ञापन देकर चेहरा चमका रहे हैं दूसरे दलों को तोड़ रहे हैं अपनी कुर्सी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। सुनील कुमार सिंह यहीं नहीं रुक उन्होंने कहा कि जब बिहार की जनता का जन आक्रोश भड़कता है तब इनको विशेष राज्य के दर्जे की याद आती है सत्ता के लोभ के लिए संप्रदायिक शक्तियों के गोद में बैठने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के विकास से कोई लेना-देना नहीं है उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की गदी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम मर्टेंरियल है बिहार की जनता ने इस बार ही उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए हरी झंडी दे दी थी पर सत्ता का पावर का दुरुपयोग करके जनबूझकर जनादेश का अपमान किया गया। बिहार में ना कोई नीति है ना नियम है ना बेरोजगारों के लिए कोई कार्ययोजना।

प्रगति के पथ का संवाद बनेगा बिहार में विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग



बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है विकास से समझौता नहीं किया जाएगा न्याय में के साथ विकास की अवधारणा को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए जनप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह कृत संकल्पित हैं राज्य के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी अपनी अहम भूमिका अदा करने की तैयारी में हैं राज्य के युवा युवतियों को हुनरमंद करने के लिए विभाग के द्वारा कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं साथ ही साथ विभाग के द्वारा राज्य भर के लोगों से ऐसे प्रोजेक्ट अविक्षार आमत्रित किए जा रहे हैं जिससे किसी भी क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हो ऐसे किसी भी सुझाव या अविक्षार के लिए विभाग के द्वारा ₹3 लाख की बजाए की भी व्यवस्था की गई है बिहार के युवाओं को हुनरमंद बनाना पहला लक्ष्य कहा बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। विभाग द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। यदि उसमें कोई त्रुटि होगी या कोई कमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा। सुमित कुमार ने कहा कि जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है उसका निर्वाहन पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। सभी कॉलेजों की समीक्षा की जा रही है। हमारी कोशिश है कि हर बेहतर सुविधा छात्रों को उपलब्ध कराई जाए। बिहार के छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दूसरे राज्य में जाते हैं। यहां पर मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। कोई नई योजना शुरू करनी हो या पुरानी योजना में बदलाव तो हम बेहिचक करेंगे।

"जो जिम्मेदारी मिली है उसपर पूरी तरीके से खड़ा उतरेंगे। युवाओं की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि चकाई बनेगा चंडीगढ़ के सभी को साकार करने के लिए हर सार्थक पहल की जाएगी। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। तीन महीने के भीतर 170 करोड़ की विकास योजना की स्वीकृति ही गयी। शीघ्र ही इन योजनाओं का कार्य शुरू होगा। क्षेत्र का सर्वांगीण विकास ही हमारी प्राथमिकता है। सड़क, सिंचाई से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं नक्सलबाद, उग्रवाद जैसी समस्याओं को लेकर भी काम किया जाएगा।

विभाग द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी समीक्षा की जाएगी।

यदि उसमें कोई त्रुटि होगी या कोई कमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा। सुमित कुमार ने कहा कि जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है उसका निर्वाहन पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। सभी कॉलेजों की समीक्षा की जा रही है। हमारी कोशिश है कि हर बेहतर सुविधा छात्रों को उपलब्ध कराई जाए। बिहार के छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दूसरे राज्य में जाते हैं। यहां पर मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। कोई नई योजना शुरू करनी हो या पुरानी योजना में बदलाव तो हम बेहिचक करेंगे। उन्होंने कहा कि हर सार्थक पहल की जाएगी। यदि कोई नई सुझाव मीडिया या आम लोगों द्वारा दिया जाएगा तो उसपर भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की बरनार जलाशय योजना, अजय, घाघरा जलाशयों को दुर्लक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की सोच है कि युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए रोजगार के अवसर सुनित किये जायेंगे। प्लेसमेंट सेल की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जो विश्वास उन पर

राज्य के मुख्या नीतीश कुमार और क्षेत्र चकाई की जनता ने जताया है उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि चकाई बनेगा चंडीगढ़ के सभी को साकार करने के लिए हर सार्थक पहल की जाएगी। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। तीन महीने के भीतर 170 करोड़ की विकास योजना की स्वीकृति ही गयी। शीघ्र ही इन योजनाओं का कार्य शुरू होगा। क्षेत्र का सर्वांगीण विकास ही हमारी प्राथमिकता है। सड़क, सिंचाई से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं नक्सलबाद, उग्रवाद जैसी समस्याओं को लेकर भी काम किया जाएगा।

अब स्कृप्टले पर्दे पर गुरु डॉक्टर एम. रहमान



अनूप

आनंद कुमार पर बनी फिल्म सुपर-30 के बाद अब बिहार के एक और गुरु की कहानी फिल्मी पर्दे पर आएगी। पटना में सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले गुरु रहमान पर 'मैं भी गुरु रहमान' फिल्म बन रही है। फिल्म को लेकर गुरु रहमान काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि अगले साल यह फिल्म आ जाएगी। गुरु रहमान ने अपनी आनेवाली फिल्म के बारे में बताया कि इस फिल्म की पटकथा माधव सक्सेना ने लिखी है। फिल्म का स्क्रिप्ट दो भागों में बंटा है। फर्स्ट हाफ में दर्शकों को जहां संघर्ष और प्रेम की झलक दिखेगी, वहीं सेकंड हाफ में गरीब बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के सपने को मूर्त रूप देने की जद्दोजहद दिखेगी। उन्होंने बताया कि फिल्म में गुरु रहमान का फिरदार आयुष्मान खुराना, रणबीर सिंह, शाहिद कपूर या विक्की कौशल में से कोई एक निभाएंगे। 81 करोड़ के बजट से इस फिल्म का निर्माण हो रहा है। गुरु रहमान समाज के लिए एक मिसाल हैं। अब तक सौ से अधिक लड़कियों का कन्यादान करा चुके हैं। उन्होंने खुद भी सामाजिक बंधनों को तोड़ते हिंदू महिला से शादी की है। शादी के बाद इनकी पत्नी

आज भी हिंदू धर्म का पालन कर रही हैं। गुरु रहमान अपने विचार और कर्म पर विश्वास रखते हैं। वे वेद के भी अच्छे जानकार हैं। इनका जन्म सारण जिले के बसंतपुर में 10 जनवरी 1974 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा डेहरी ऑन सोन से प्राप्त की। उसके बाद स्नातक करने के लिए बगास हिंदू विश्वविद्यालय चले गए। यहां से उन्होंने प्राचीन भारत एवं पुरातत्व में स्नातक और मास्टर्स भी किया। इसके बाद कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में वह पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे, जहां यूजीसी ने उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया। साल 1997 में इन्होंने ऋग्वेद कालीन आर्थिक एवं सामाजिक विशेषण विषय पर पीएचडी पूरी की। डॉ. रहमान ने 1997 प्रेम विवाह किया। इनकी पत्नी का नाम अमिता है, लेकिन अंतरधार्मिक विवाह करने के कारण समाज और उनके घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं हुआ। रहमान बताते हैं कि घर वाले अमिता को इस शर्त पर अपनाने को राजी थे कि वह इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले डॉ. रहमान को यह मंजूर नहीं था। इन्होंने पत्नी पर कभी कोई दबाव नहीं बनाया। इस कारण घर वालों ने उनसे नाता तोड़ लिया। शादी के लगभग सात वर्षों तक दोनों पति-पत्नी अलग रहे। रहमान लॉज में

और अमिता गर्ल्स हॉस्टल में रहीं। भाड़ा चुकाने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी।

आर्थिक सहयोग नहीं मिलने के कारण यह दौर काफी कठिन था। किसी तरह कुछ दिन गुजरे। बाद में प्रो. विनय कंठ की कोचिंग में पढ़ाने का मौका का मिला। इससे महीना में तीन-चार हजार रुपए आने लगे। साल 2004 में इनकी एक किडनी खराब हो गई। इलाज करने के दौरान इनका सारा पैसा खर्च हो गया। इस बजह से इनकी पत्नी को गहना तक बेचना पड़ा। काफी इलाज के बाद भी जब रोग ठीक नहीं हुआ तो इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लिया। इससे इन्हें काफी आराम मिला। इसी के बल पर यह आज तक स्वस्थ हैं और घंटों तक छात्र-छात्राओं को पढ़ाते हैं। गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए इन्होंने अपनी बेटी अदम्या अदिति के नाम पर 2010 में संदलपुर इलाके में अदम्या अदिति गुरुकुल की नींव रखी। ये प्रयासरत थे कि यहां एक अनाथालय का निर्माण कराया जाए, जिसमें सैकड़ों गरीब बच्चों को मुफ्त में खाने-पीने, रहने और शिक्षा की व्यवस्था हो। मात्र 11 रुपए में गरीब बच्चों के सपनों को मूर्त रूप देने के सपने को साकार करने में लग गए। इस फिल्म में गुरु रहमान के जिंदगी के अनछुए पहलुओं को दर्शक देख पाएंगे।

मनोज कुमार सिंह को बनाया गया भाजपा का प्रदेश मीडिया प्रभारी



तो क्या सारण लोकसभा क्षेत्र से अगले चुनाव में मनोज कुमार सिंह भी ताल ठोकेंगे यह हम नहीं कह रहे यह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है मनोज कुमार सिंह सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के भावलपुर के रहने वाले हैं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य हैं लंबे वक्त से भाजपा में बने हुए हैं आसाम में इन्हें भाजपा का प्रदेश मीडिया प्रभारी भी बनाया गया था संगठन में बड़े नेताओं के साथ ही इनके बेहतर तालमेल हैं जो अक्सर क्षेत्र में बड़े कार्यक्रमों के रूप में देखने को मिलता है हालांकि मनोज कुमार सिंह से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं भाजपा एक लोकतात्रिक पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान मिलता है यहां पद पावर के लिए लोग पार्टी से नहीं जुड़ते हैं।

आसाम में इन्हें भाजपा का प्रदेश मीडिया प्रभारी भी बनाया गया था संगठन में बड़े नेताओं के साथ ही इनके बेहतर तालमेल हैं जो अक्सर क्षेत्र में बड़े कार्यक्रमों के रूप में देखने को मिलता है हालांकि मनोज कुमार सिंह से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं भाजपा एक लोकतात्रिक पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान मिलता है यहां पद पावर के लिए लोग पार्टी से नहीं जुड़ते हैं।

जहां कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान मिलता है यहां पद पावर के लिए लोग पार्टी से नहीं जुड़ते हैं पार्टी की सेवा करने वाले लोगों को पार्टी समय आने पर जरूरी ईनाम देती है फिलहाल वह सारण लोकसभा क्षेत्र में लोगों की सेवा में लगे हुए हैं उनके द्वारा जगह-जगह हेल्थ कैंप के आयोजन हो रहे हैं वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है पीड़ित कार्यकर्ताओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है उन्होंने कहा कि वे फिलहाल अभी इन सब चीजों से दूर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं सारण उनकी जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे।

निर्देशकों की पसंद बनी संजना सिल्क

अपने ठुमको अपनी अदाओं से दर्शकों के दिलों को घायल कर देने वाली और आइटम डांस के लिए मशहूर अभिनेत्री संजना सिल्क इन दिनों फिल्म निर्देशकों की पहली पसंद बनी है। संजना सिल्क अपने बेतरीन डांस परफॉर्मेंस के कारण हमेशा भोजपुरी फिल्म जगत में चर्चे में रहती है।

संजना सिल्क ने बताया कि वो उत्तरप्रदेश के मऊ जिले से है उनके बचपन से ही अभिनेत्री बनने का सपना था इसी जुनून के कारण वो मुम्बई में आयी और वहाँ संघर्ष करने लगी लंबे समय और काफी संघर्ष के बाद उन्हें फिल्म मिलना शुरू हुई जो दर्शकों के प्यार



आशीर्वाद से आज तक मिलती आ रही है उन्होंने ये भी बताया कि वो आइटम डांस के साथ साथ फिल्मों में अभिनय भी करती है।

बता दे कि भोजपुरी फिल्म जगत में कई मशहूर अभिनेत्रियों ने आइटम डांस से शुरूआत करके फिल्म जगत में नाम कमाया है। लोगों का मानना है की आइटम क्वीन के नाम से जानी जाने वाली अभिनेत्री सीमा सिंह की जगह अब संजना सिल्क ले रही है क्योंकि शादी होने के बाद सीमा सिंह ने फिल्म जगत से अभिनय और डांस से विदा ले ली थी। इसलिए अब आइटम डांस का नाम आता है तो सबसे पहले संजना सिल्क को बुलाया जाता है।

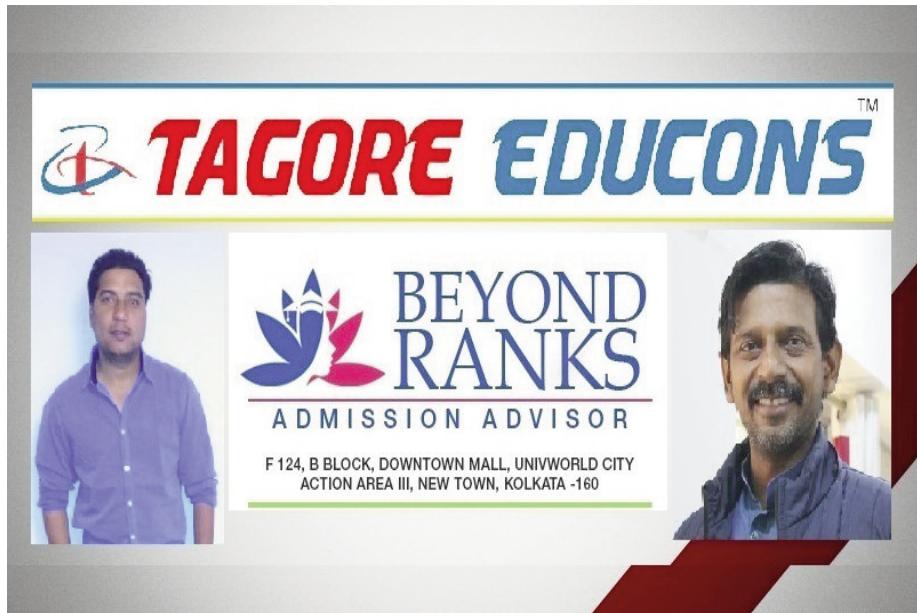
संजना सिल्क एक अच्छी अभिनेत्री होने के साथ साथ सरल स्वभाव और खूबसूरती की रानी है जिन्हें

देखकर लोगों के दिलों में गुदगुदी होने लगती हैं।

संजना सिल्क के फिल्मी ग्राफ के बारे में बात करें तो उन्होंने भोजपुरी फिल्म जगत के लगभग सभी सुपरस्टारों के साथ काम किया जो सुपरहिट रही। संजना सिल्क की इस साल आने वाली फिल्मे तेजस्वीनी यादव आईपीएस, पिस्टल पाण्डेय, स्वर्ग से सुंदर गाँव हमार, सैया सरकारी, तोहरे प्यार में पागल बानी, पुलिस डायरी, दुलहन लाईब बलिया से, तेजा का तेवर, जनता दरबार और फिरौती, दिल बेचारा आदि कई फिल्में हैं और लॉकडाउन के बाद उन्होंने कई फिल्में साइन की जिनमें से मौत का सौदागर, क्या यही प्यार है, हत्यारा और भी कई फिल्में हैं। इसी वर्ष उन्हें सरस सलिल भोजपुरी सिने अवार्ड में आइटम क्वीन अवार्ड से भी नवाजा गया।

टैगोर एड्यूकॉन्स अब पश्चिम बंगाल में

पटना / कोलकाता : देश की प्रसिद्ध एजुकेशनल कन्सलटेन्सी टैगोर एड्यूकॉन्स अब पश्चिम बंगाल में बियोंड रैंक कन्सलटेन्सी के साथ मिलकर काम करेगी। इसके लिये टैगोर एड्यूकॉन्स कन्सलटेन्सी के निदेशक धनंजय कुमार सिन्हा एवं बियोंड रैंक कन्सलटेन्सी के निदेशक आनंद कुमार (राठौड़) ने अपनी-अपनी सहमति दे दी है। टैगोर एड्यूकॉन्स का मुख्यालय पटना है एवं बिहार में यह लम्बे समय से कार्यरत है, जबकि बियोंड रैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। इस सन्दर्भ में टैगोर एड्यूकॉन्स के निदेशक धनंजय कुमार ने बताया कि किसी भी संस्था का विस्तार एक सामान्य प्रक्रिया है। हर संस्था समय के साथ-साथ अपना विस्तार करना चाहती है। इसी के तहत टैगोर एड्यूकॉन्स ने भी पश्चिम बंगाल में अपने विस्तार का निर्णय लिया है। धनंजय ने बताया कि हर व्यक्ति या संस्था को एक भरोसेमंद साथी की तलाश रहती है। बियोंड रैंक पश्चिम बंगाल की एक प्रतिष्ठित संस्था है। इसका पश्चिम बंगाल में एक बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क है। अतः यह मेल एक-दूसरे के लिये काफी फलदायी होगा। श्री सिन्हा ने बताया कि दरअसल टैगोर एड्यूकॉन्स की शुरुआत भी 2001 में पश्चिम बंगाल से ही हुई थी। सबसे पहले इसका कार्यालय पश्चिम बंगाल के शार्तिनिकेतन में खुला था। बाद के दिनों में यह बिहार में ज्यादा सक्रिय हो गया। बावजूद इसके संस्था को अपनी जन्मभूमि बंगाल से लगाव तो है ही। बियोंड



रैंक के निदेशक आनंद कुमार ने इस गठबंधन पर खुशी जताते हुए कहा कि यह प्रस्ताव टैगोर एड्यूकॉन्स की तरफ से आया था जिस पर उन्होंने अविलम्ब सहमति दे दी। आनंद ने कहा कि चूंकि टैगोर एड्यूकॉन्स देश की एक पुरानी एवं विश्वसनीय संस्था है एवं इसके निदेशक

धनंजय कुमार सिन्हा का कन्सलटेन्सी के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है, तो यह गठबंधन दोनों ही संस्थाओं को कई प्रकार से मजबूती पहुंचाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी दोनों कन्सलटेन्सी के संबंध एवं सामंजस्य काफी बेहतर रहे हैं।

प्रधानमंत्री के आंसू सच्चे हैं तो क्या हुआ?

1980 में जब इंदिरा गांधी के जवान बेटे संजय गांधी की मौत हवाई हादसे में हुई थी तब उन्हें चाहे जितना दुख रहा हो, इसका उन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया। तब पत्र-पत्रिकाओं में छपी उनकी एक तस्वीर अब भी सबकी स्मृति में टंगी हुई है जिसमें वे काला चश्मा लगाए अपने बेटे का शव निर्निमेष भाव से देख रही हैं। मैं फिर दुहरा रहा हूं कि मैं उन लोगों में नहीं हूं जो प्रधानमंत्री के आंसुओं को बिल्कुल घड़ियाली आंसू मानते हैं। मुझे यह मानने में जरा भी गुरेज नहीं कि प्रधानमंत्री के आंसू सच्चे होंगे, वे दिल से निकले होंगे। कुछ दिन पहले राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई के दौरान भी गुजराती पर्यटकों पर श्रीनगर में आतंकी हमले की खबर साझा करते-करते वे रो पड़े थे। तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये आंसू नकली हैं। तब भी मैंने लिखा था कि वे असली आंसू होंगे। लेकिन आंसू असली भी हों तो क्या? क्या आंसू बहाना संवेदनशील होने की निशानी है? यह भावुकता की निशानी है और भावुकता बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। भावुक लोग अक्सर तर्क का साथ छोड़ देते हैं। वे भावनाओं में बह जाते हैं। 1984 में जो लोग इंदिरा गांधी की हत्या पर आंसू बहा रहे थे, वही लोग बाद में सिखों को बिल्कुल राक्षसों की तरह मार रहे थे। 2002 में जिन लोगों के आंसू गोधरा में जलती हुई ट्रेन के भीतर

मारे गए कारसेवकों को लेकर रुक नहीं रहे थे, उन्हें अगले तीन महीने तक अड्डहास करते देखा जा सकता था। जब पूरा गुजरात एक जलती हुई ट्रेन बना हुआ था। भावुकता बहुत एकांगी चीज़ होती है। वह बहुत ताकालिक चीज़ भी होती है। हम नकली कहनियों पर भावुक हो उठते हैं। हम घटिया फिल्मों पर आंसू बहाने लगते हैं। जीवन में जो लोग अपनी बहनों को प्रेम करने पर गोली मार दें, वे भी सिनेमा में नायिका का संघर्ष देख रो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने कुचे-बिल्लियों की मौत पर दुखी होते हैं, लेकिन गली के कोने पर आधी रात को ठंड में भीख मांगते बच्चों को देखकर वे नहीं पसीजते।

भावुकता प्राकृतिक तौर पर आ जाती है। जिन लोगों से हम जुड़े होते हैं, उनके प्रति एक तरह की अतिरिक्त उदारता और आवेग का अनुभव करते हैं। लेकिन संवेदनशीलता विकसित करनी पड़ती है। संवेदनशील होने के बाद अपने दिए हुए संसार को और बड़ा करना, और ज्यादा फैलाना है। संवेदनशील होने का मतलब वास्तविक दुखों और तकलीफों के प्रति सजग होना होता है। संवेदनशील होने का मतलब तर्क और विवेक के साथ ममत्व को जोड़ना होता है। प्रधानमंत्री सिर्फ भावुक हैं या संवेदनशील भी हैं? इसमें सीधे-सीधे कोई लकीर खींच देना- या प्रधानमंत्री को

किसी एक ओर खड़ा कर देना भी वैसी ही असंवेदनशीलता या भावुकता होगी जो हमारे बहुत सारे साथी मोदी विरोध में दिखाते हैं। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री अगर संवेदनशील हैं भी तो कई अवसरों पर उन्होंने इस संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया है। अगर वे संवेदनशील होते तो बंगाल की चुनावी रैली में उमड़ी भारी भीड़ पर खुशी जताने की जगह चिंता जताते- लोगों से अपील करते कि वे घर जाएं और कोरोना से दूर रहे। लेकिन उन्हें एक बात भी इस आशंका ने नहीं दिया कि इतनी भारी भीड़ के बीच कहीं कोरोना भी टहल रहा है। वे संवेदनशील होते तो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुछ सम्मान के साथ देखते, उनसे संवाद करते और उनको आशवस्त करने की कोशिश करते कि उनकी नागरिकता खतरे में नहीं पड़ेगी।

बल्कि प्रधानमंत्री संवेदनशील होते तो देश के भीतर एक बड़े तबके में फैली असुरक्षा की भावना को ठीक से पहचानते और उसे अपने साथ लेने की कोशिश करते हुए अपने उद्धर बहुसंख्यक समर्थकों से अपील करते कि वे ऐसी कोई हरकत न करें जिससे इस देश के दूसरे समुदायों के भीतर यह डर या शिकायत हो कि उनको दूसरे दर्जे का नागरिक न बना दिया जाए।

भारत में कोरोना से कितने मरे, 42 लाख या 3 लाख?

न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आंकलन कर बताया है कि इस साल जनवरी तक भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या 42 लाख से भी अधिक हो सकती है। दूसरी लहर की गिनती नहीं है। गहुल गांधी ने इस खबर का लिंक ट्रिवटर पर साझा कर दिया तो स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन नाराज हो गए। उन्होंने लिख दिया कि लाशों पर राजनीति कांग्रेस स्टाइल। पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप हो रहे हैं, लेकिन लगता है उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है।

गहुल गांधी को दिल्ली से अधिक न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखें। गिद्धों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी ठीक नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि उन्हीं की सरकार ने गिद्धों को बचाने के लिए पांच साल का एक एक्शन प्लान बनाया है। वह कार्यक्रम 2006 से चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने गिद्धों के प्रति जिस घृणा का प्रदर्शन किया है वह अफसोसनाक है।

आसाम में उड़ते गिद्धों को नहीं मालूम कि मोदी सरकार के मंत्री डॉ हर्षवर्धन उनके बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक उसी तरह डॉ हर्षवर्धन को नहीं मालूम कि उनके सरकार के पर्यावरण मंत्री ने गिद्धों को बचाने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए पांच साल का एक एक्शन प्लान बनाया है। 16 नवंबर 2020 को इसे लांच किया गया और जावडेकर ने ट्रीट भी किया था। मालूम होता तो डॉ हर्षवर्धन गहुल गांधी के ट्रीट की आलोचना में गिद्धों पर ऐसी टिप्पणी नहीं करते। एक्शन प्लान वाली रिपोर्ट में पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो लिखते हैं कि भारत में गिद्धों के सामाजिक और सांस्कृति महत्व को कम शब्दों में इस तरह से रखा जा सकता है कि वे मृत जानवरों के मांस को खाकर पर्यावरण को साफ रखने का काम करते हैं। तो इस तरह कोविड की इस दूसरी लहर में टीका और मरने वालों की संख्या को लेकर तरह तरह के बयानों से अगर कोई झूठ साफ करने का काम करता है तो वह गिद्ध है और गिद्ध होकर भारत की संस्कृति की रक्षा करता है। कोई भी व्यक्ति जो सरकार के झूठे दावों को चुनौती देता है भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाला गिद्ध कह सकता है और गौरव कर सकता है। एक्शन प्लान के अनुसार देश के पांच राज्यों में गिद्धों के प्रजनन केंद्र बनाएं जाएंगे जिनमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है।

अभी कुछ दिन पहले डॉ हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक चेतना की चिन्ता में रामदेव को पत्र लिखा था, लेकिन गिद्धों के प्रति उनका नजरिया बता रहा है कि उन्हें भी वैज्ञानिक नजरिए को बेहतर करने की जरूरत है। वैसे थाली बजाना साइंटिफिक टेंपर नहीं था बल्कि साइंटिफिक टेंपर का पंचर कर देना था। अभी बात खबर नहीं ढूँढ़ी है। शुरू हो रही है। इस ट्रीट में डॉ हर्षवर्धन कहते हैं कि गहुल गांधी को न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा है दिल्ली पर नहीं। क्या स्वास्थ्य मंत्री यह कह रहे हैं कि जो दिल्ली कहे उसे सच मानना ही होगा? तो यही बात वो भारतीय मीडिया को भी कहना चाहेंगे? सबसे पहले दूसरी लहर में कोविड से मरने वालों की सरकारी संख्या को चुनौती तो भारतीय भाषाई अखबारों ने दी है। गुजरात के अखबारों ने दी। इसी को आधार बनाकर दुनिया भर के विद्रोह मरने वालों की सही संख्या और सरकार के झूठ का विश्लेषण कर रहे हैं। क्या डॉ हर्षवर्धन भारतीय अखबारों की रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहेंगे? किस दिल्ली पर भरोसा करें, खुद प्रधानमंत्री को ही अंकड़ों पर भरोसा नहीं लगता। क्या डॉ हर्षवर्धन को नहीं मालूम कि 15 मई को प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा है कि संख्या ज्यादा है तो बताने से पीछे न हटें। खावाहमखावा हिंदुओं को बदनाम कर दिया। डॉ हर्षवर्धन को कोई इतना ही बता दे कि पारसी समाज गिद्धों को कितनी आदरणीय निगाह से देखता है। जानना हो तो गुजरात के नवासारी ही चले जाएं। जहां पारसी समाज अतिम संस्कार के लिए जाना पसंद करना है। वहां गिद्धों की कमी से चिन्तित रहता है। मरने वालों की सही संख्या का पता लगाना गिद्ध होनी नहीं है बल्कि सत्यमेव जयते के आदर्शों का पालन करना है। बालमीक रामायण के अरण्य कांड के पचासवें सर्ग का श्वेत संख्या तीन की याद दिलाना चाहता हूं। जिसमें जटायु कहते हैं हे दस



मुख रावण मैं प्राचीन सनातन धर्म में स्थित, सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान गिद्धराज हूं। मेरा नाम जटायु है। भैया, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। गिद्धराज सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य के साथ खड़े हैं और निंदित कर्म का विरोध कर रहे हैं। सबको पता है कि सरकार ने मरने वालों की संख्या सही नहीं बताई है। हर किसी को गिद्ध बन कर उस पर सवाल करना चाहिए। दुनिया भर के विद्रोह सरकारी दावों से अलग अखबारों में छाँपी खबरों और अन्य माध्यमों से अंकड़ा लेते हैं। क्योंकि सरकारें झूठ बोलती हैं। फर्जी डेटा देती हैं। इसे लेकर इमोशनल होने की क्या जरूरत है।

केरल एक ऐसा राज्य है जहां के अखबारों में मरने वालों की सूचना और श्रद्धांजलि छापने की परंपरा है। इसके लिए किसी से पैसा नहीं लिया जाता है। हिन्दी प्रदेशों से निकलने वाले हिन्दी और अंग्रेजी के अखबारों में श्रद्धांजलि छपवाने के पैसे देने होते हैं। मलयालम भाषा के अखबार वर्षों से प्रिट और आनलाइन संस्करणों में मुफ्त में श्रद्धांजलियां छापते रहे हैं। अखबारों के हर जिला संस्करण में एक पन्ना श्रद्धांजलि और मरने वालों की सूचना का होता ही है। केरल के पाठकों के लिए यह देख कर रख देने वाला पन्ना नहीं होता है बल्कि उनकी नजर इस पन्ने पर जाती ही जाती है। आप चाहें तो मलयालम मनोरमा, माध्यमम, मातृभूमि, केरला कौमुदी के किसी भी संस्करण को उठा कर देख सकते हैं। माध्यमम अखबार के एक पत्रकार ने बताया कि केवल सूचना देनी होती है, मरने वालों की सूचना छपेगी ही। मना कर ही नहीं सकते। यह एक तरह से केरल के अखबारों की पब्लिक सर्विस है। अगर परिवार चाहता है कि मौत का कारण कोविड लिखे तो अखबार लिखते हैं। नहीं बताता तो नहीं लिखते हैं। हमें इसकी जानकारी नहीं है कि इन अखबारों ने सरकारी अंकड़ों की तुलना में छपने वाली श्रद्धांजलियों की संख्या को अधिक पाया या सही पाया। डॉ हर्षवर्धन चाहें तो इनकी गिनती कर केरल सरकार के आंकड़ों को चुनौती दे सकते हैं लेकिन जानबूझ कर कोई इस मालूम की तह तक नहीं जाना चाहता है। मगर रिसर्चर तो गिनती करेंगे। क्योंकि सही संख्या से ही आप कोविड या किसी भी महामारी से लड़ने की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। खराब प्लानिंग से कितने लोग मर गए और मार दिए गए यह जानना जरूरी है तभी आप आगे की सही प्लानिंग कर पाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में चिन्मय तुबे का एक लेख छपा है। चिन्मय बता रहे हैं कि 1918 में जब भारत में स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी आई थी तब कितने लोग मरे थे उसकी संख्या को लेकर आज तक शोध हो रहे हैं। उस वक्त के सैनिटरी कमिशनर नॉर्मन व्हाइट में इन्हीं ईमानदारी तो थी कि उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत में साठ लाख लोग मरे होंगे, और संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। 1921 में जब जणगणना हुई तो सर्वे करने वालों ने देखा कि गांव के गांव खाली हो चुके हैं।

पीएम केयर फंड के तहत खरीदे वेंटिलेटर कितने काम आ पाए?



आखिर हजारों करोड़ रुपये से खरीदे गए इन वेंटिलेटर की दूसरी लहर में क्या भूमिका रही, इसका मूल्यांकन क्या दस साल बाद होगा?

पीएम केयर के तहत सप्लाई किए गए वेंटिलेटर की खराब गुणवत्ता को लेकर एक साल से मीडिया में विस्तार से खबरें छप रही हैं। कभी मामूली खराबी तो कभी खराखाब में कमी का बहाना बना कर इस मसले की सच्चाई छलकती रहती है। आखिर हजारों करोड़ रुपये से खरीदे गए इन वेंटिलेटर की दूसरी लहर में क्या भूमिका रही, जब नहीं चली तब और जब चल रही थीं तब। इसका मूल्यांकन क्या दस साल बाद होगा? 15 मई को सकार एक बयान जारी करती है कि हृप्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कुछ राज्यों में वेंटिलेटर के स्टोरेज में पड़े होने की कुछ रिपोर्टों को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वेंटिलेटर के उपयोग और संचालन का तत्काल ऑडिट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरी हो तो स्वास्थ्य कर्मियों को वेंटिलेटर के ठीक से संचालन के लिए रिफ्रेश ट्रेनिंग प्रदान की जानी चाहिए, हाँ इसमें यह नहीं लिखा है कि वेंटिलेटर घटिया है जिसकी शिकायत कई डाक्टरों ने

की है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि पीएम केयर फंड से घटिया वेंटिलेटर की सप्लाई कैसे हो गई।

झारखण्ड को केंद्र से 1250 वेंटिलेटर मिले हैं। जिनमें से अधिकांश कोविड के इलाज में सक्षम नहीं हैं। मरीज की जरूरत इस मशीन से पूरी नहीं होती है। जब इसका इस्तमाल आईसीयू में होता है तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं। रांची के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल रिम्स में हरबंस ने देखा कि पीएम केयर्स फंड से मिले अधिकांश वेंटिलेटर को स्टोर में रख दिया गया है। हॉस्पिटल के अंदर क्रिटिकल केयर के कुछ विशेषज्ञों से मिला, उन्होंने कैमरे पर बोले होने से मना कर दिया लेकिन कैमरा बंद होने पर बताया कि कोरोना के गंभीर संक्रमितों में हमेशा इंवेजिव व नॉन इंवेजिव युक्त वेंटिलेटर की जरूरत होती है, लेकिन कई कंपनियों ने सामान्य वेंटिलेटर की सप्लाई कर दी है। उनका कहना है कि इस वेंटिलेटर से सिर्फ ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। वेंटिलेटर में मरीजों को लंबे समय तक रखा जाता है, इसलिए ऐसे मशीन को एक सपाह तक चला कर छोड़ा जाता है। यह देखा जाता है कि मशीन बीच में तो काम करना बंद तो नहीं कर रही है। इन सभी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही कंपनी को अस्पताल

द्वारा एनओसी दिया जाता है। जबकि पीएम केयर से राज्य में दिये गये वेंटिलेटर के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मशीन देने के बाद कंपनी के प्रतिनिधि पूछने तक नहीं आये।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का भी कहना है कि सरकार तो चलाना चाहती है लेकिन मशीन ही लायक नहीं है इसलिए इन्हें खोलकर वापस डब्बे में डाल दिया गया। वेंटिलेटर किसी काम के नहीं हैं।

बिहार के सुपौल में पिछले साल जून में ही पीएम केयर्स के तहत छह वेंटिलेटर आए थे। जिनका इस्तमाल नहीं हो सकता। पता चला कि वेंटिलेटर की सप्लाई करने वाली कंपनी ने कुछ जरूरी पार्ट्स अभी तक नहीं दिए हैं। उन्होंने सदर अस्पताल में देखा कि वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। चलाने वाले स्टाफ नहीं हैं। लोगों के मरने और हाइकार मरने के बाद 15 मई को स्वास्थ्य विभाग जागता है। आदेश होता है कि एक डॉक्टर, चार तकनीशियन और आठ वार्ड बॉय को रखा जाएगा लेकिन 21 मई तक डॉक्टर यहाँ काम पर नहीं आए। वेंटिलेटर शुरू नहीं हो सका। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ अरुण कुमार वर्मा कहते हैं कि डॉक्टर से बात हुई है, शीघ्र योगदान करेंगे और सेवकान मशीन



का जार के लिए स्टाफ को पतना भेजा गया है। जब तक प्रधानमंत्री को ऑडिट रिपोर्ट पहुंचेगी, ऐसे मामलों की लीपापेती हो चुकी होगी। अस्पताल प्रशासन को वेंटिलेटर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की भी चिंता है। 15 दिन पहले ही ऑक्सीजन प्लांट का सर्वे हुआ है।

हमें लगा था कि इस बीच चालू हो गया होगा लेकिन पता किया तो स्थिति जस की तस थी। वेंटिलेटर के संचालन के लिए जिस एनेस्थेसिस्ट डॉ अमित कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया था उन्होंने लिखित तौर पर ज्ञाइन करने से इंकार कर दिया है। वेंटिलेटर का जार आ गया है लेकिन चलाने वाला नहीं है। जो मरीज यहाँ आता है उसे वहाँ भेजने का सिलसिला जारी है जहाँ यही समस्या उसका इंतजार कर रही है। यह समस्या केवल बिहार या झारखण्ड की नहीं है। पीएम केरार के वेंटिलेटर के खराब होने की खबरें तो पिछले साल से छप रही हैं। ऑडिट होने की बात अब की गई है जब लोग मरे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हर जगह से तमाम रिपोर्ट छप चुकी हैं, हमारे कई सहयोगियों ने भी की हैं लेकिन इसके घटिया निकलने पर कोई हलचल नहीं है। क्या इसलिए कि पीएम केरार से मिला है?

20 मई की दिव्य भास्कर और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट तो प्रधानमंत्री के ऑडिट वाले आदेश के बाद

छपी है। इस रिपोर्ट में सुनील सिंह बघेल ने बताया है कि केंद्र ने राज्यों को जो वेंटिलेटर दिया है वो हांफ गए हैं। कहीं पर वोल्टेज कम हो जाता है तो कहीं पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। यही नहीं, कहीं कहीं पर 5 रू. के प्यूज की वजह से पीएम केरार वाले वेंटिलेटर ठप्प हैं। पांच रुपये के प्यूज की वजह से। जिन कंपनियों ने वेंटिलेटर की सप्लाई की है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने, रखरखाव और अतिरिक्त कल पुर्जे पहुंचाने में देरी कर रही हैं। 23 मई के ईडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए। केंद्र ने पीएम केरार फंड के तहत राज्य को 592 वेंटिलेटर दिए जिनका इस्तमाल नहीं हो सकता। इन वेंटिलेटर को लेकर राज्य सरकार ने भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को 571 शिकायतें भेजी हैं। केवल 180 का समाधान हुआ है। 366 मशीनों में ऑक्सीजन कम हो जाने, कंप्रेसर फेल हो जाने की शिकायतें आई हैं। किसी का पार्ट गायब था तो किसी को कंपनी की तरफ से लगाया नहीं गया था।

ऐसा क्यों है कि राजस्थान और झारखण्ड के स्वास्थ्य मंत्री इन वेंटिलेटर को लेकर बोलते हैं जहाँ विपक्ष की सरकार है और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री वेंटिलेटर की तरफदारी करते हैं। कोई कमी नहीं दिखती है। जान तो आपकी है। क्या वो भी कांग्रेस और बीजेपी के अनुसार हो गई है। वेंटिलेटर को लेकर डॉ हर्षवर्धन ने अखबारों में छपी कुछ खबरों को ट्वीट किया है। जिन अखबारों

में वेंटिलेटर को लेकर सवाल पूछे गए हैं उन्हें नहीं, बल्कि उन खबरों को किया है जो पीएम केरार की वाहवाही करती हैं। एक खबर में बताया है कि पीएम केरार फंड से वेंटिलेटर का उत्पादन तीन गुना हो गया है। दूसरी खबर में बताया गया है कि केंद्र ने वेंटिलेटर को सोर्पोर्ट न मिलने के कारण राज्यों की खिंचाई की है। केंद्र की टीम ने वहाँ जा कर उन पार्ट्स को बदला उसके बाद वेंटिलेटर चलने लगा। खुद ही बता रहे हैं कि नए वेंटिलेटर की क्या हालत है। पार्ट्स की कमी से नहीं चल रहे थे। और सवाल इसका है ही नहीं कि वेंटिलेटर का उत्पादन कितना गुना हुआ, सवाल है कि उसकी गुणवत्ता कैसी है? 15 मई को पीएमओ ऑडिट की बात करता है और 22 मई को हर्षवर्धन खुद को पसंद आने वाली खबरों की कतरन को ट्वीट करते हुए ऑडिट शब्द का इस्तमाल करते हैं। क्या अखबार की कतरन ऑडिट है? 11 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय सात राज्यों को पत्र लिखता है जहाँ वेंटिलेटर का इस्तमाल नहीं हो रहा है। लेकिन वेंटिलेटर के इस्तमाल न होने की खबर तो अभी तक आ रही है। 24 मई तक।

पीएम केरार के वेंटिलेटर पर उठ रहे सवाल को लेकर आहत होने की जरूरत नहीं है कि यह पीएम केरार का है। सवाल इसलिए उठना चाहिए कि खराब वेंटिलेटर जानलेवा हो सकता है। वैसे इन सवालों का जवाब तो

आने से रहा। बदले में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई मैसेज आ जाएगा कि कुछ हुआ ही नहीं। इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अपने एक छात्र को फेल कर दिया। इस यूनिवर्सिटी पर भरोसा करने के कारण ही रामदेव को अपने बयान से वापस लेना पड़ा। जबकि एक दिन पहले कहा था कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया। क्या रामदेव वाकई व्हाट्सएप फार्वर्ड के आधार पर बयान दे रहे थे? हम नहीं जानते कि मैसेज किसका था, कहीं आईटी सेल का तो नहीं था?

9 मई को त्रिपुरिकेश एम्स की इमारत में रामदेव प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे। वहां पर एक मैसेज पढ़ते हैं और बताते हैं कि व्हाट्सएप फार्वर्ड है जिसमें लिखा है कि एलोपैथी स्ट्रुपिड और दिवालिया साइंस है। लेकिन मैसेज पढ़ने के बाद रामदेव कहते हैं कि जितने लोगों की मौत हास्पिटल न जाने से हुई, आक्सीजन न मिलने के कारण से हुई, उससे ज्यादा की मौत आक्सीजन के बावजूद हुई और एलोपैथी दवाओं के बावजूद हुई। इसे सिर्फ एक बयान की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, जिस लेकर रामदेव ने माफी मांग ली है। आईटी सेल परेशान है कि लाशों के ढेर देख रही जनता को कैसे बरगलाया जाए। किस तरह के बहाने बनाए जाएं जिससे सरकार को जवाबदेही से बचाया जा सके। रामदेव एलोपैथी को लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार तो बताते हैं लेकिन एक बार भी मोदी सरकार की नीति की नाकामी नहीं कहते। व्हाट्सएप के फार्वर्ड मैसेज की डिजाइन पोलिटिकल है और सरकार को जवाबदेही से मुक्त करने की है। इसलिए रामदेव के माफीनामे से बात

खत्म नहीं हो जाती है। हुक्मत के हमराहियों को पता है कि समाज ने देखा है कि लाखों मरे हैं, मगर बताया गया हजारों में। उनके इस गुस्से पर पानी डालने के लिए तरह तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं। दूसरी लहर नहीं आई थी तब इन्हीं रामदेव की तथाकथित दवा कोरोनिल के लांच के समय परिवहन मंत्री और नितिन गडकरी गए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो स्वास्थ्य मंत्री से कोरोनिल के लांच में जाने और कोरोनिल की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाया था। कोई एकशन नहीं हुआ। विवादित आंकड़ा ही सही 12 दिनों में पचास हजार की आधिकारिक संख्या ने बहुत कुछ बदला है वर्ता रामदेव की तथाकथित दवा कोरोनिल का लांच करने वाले डॉ हर्षवर्धन ने रामदेव को पत्र नहीं लिखा होता और रामदेव भी माफी नहीं मांगते। तथाकथित दवा इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार के दो दो मंत्रियों के लांच करने के बाद भी मोदी सरकार ने इस दवा में भरोसा नहीं जताया है और आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में इसका जिक्र नहीं किया है। जिस तरह रेमडिसिवर और प्लाजमा को लेकर बहुत महीनों बाद आईसीएमआर ने कहा कि ये उपयोगी नहीं हैं। जितने आत्मविश्वास से रामदेव एलोपैथी को स्ट्रुपिड कह देते हैं शायद उतना आत्मविश्वास घट में नहीं है कि कह दे कि कोरोनिल का सेवन न करें या यही कह दे कि कोरोनिल का सेवन करें।

ऐसा नहीं है कि एलोपैथी पर सवाल नहीं उठाए जा सकते लेकिन उसका एक तरीका तय है। मेडिकल जर्नल में हर दिन एलोपैथी के दावे को लेकर बहस

चलती रहती है। रामदेव को एलोपैथी के बजाए अस्पतालों के भीतर की कुव्वस्था की बात करनी चाहिए। बताना चाहिए कि ये अस्पताल के नाम पर अस्पताल नहीं हैं। इनके पास डाक्टर नहीं हैं। आक्सीजन नहीं है। वैट्लेटर नहीं हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है नाम लेकर बात करना चाहिए। सूरक्षा के भाजपा विधायक वी डी झालावडीया कोविड कम्युनिटी वार्ड में जाकर रेमडिसिवर का डोज निकालते हैं और द्विप में इंजेक्शन देते हैं। वी डी झालावडीया डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्स नहीं हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराज सिंह परमार ने कहा है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल को पांचवीं कक्षा पास झालावडीया से प्रेरणा लें एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लें जहां भाजपा के कार्यकर्ता और विधायकों को इंजेक्शन देने की ट्रेनिंग दी जाए। अखबारों में झालावडीया का बयान छ्या है कि अगर कुछ गलती हुई है तो माफी मांगता हूं। मैं तो सिर्फ लोगों की सेवा कर रहा हूं। लाखों लोगों की मौत पर रोने से लेकर इंजेक्शन देने का यह तमाशा अगर विश्व गुरु भारत के प्रांगण में नहीं होगा तो कहां होगा वत्स। कुर्सी पर कलाकार बैठ गए हैं और कलाकारों को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है।

कोरोना ने जब दस्तक दी थी तब यह बात जोर शोर से कही गई थी कि इससे लड़ने का एक ही हथियार है विज्ञान। विज्ञान का मतलब तर्क और तथ्य। हमने पिछले एक साल में वैज्ञानिक सोच के नाम पर यही हासिल किया है। परंपरा की आड़ में मूर्खता को आगे कर दिया ताकि बहस अपमान को लेकर हो, अस्पताल को लेकर





नहीं। पिछले साल जब थाली बजाने की अपील हुई तो आलोचना डरी सहमी थी। पत्रकार तारीफ कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का जनता पर कितना प्रभाव है। असल में वे इस फैसले की आलोचना से खुद को बचा रहे थे। पर्यावरणविद् दुनू रंग ने प्रो दिनेश मोहन के बारे में लिखते हुए एक प्रसंग का जिक्र किया है जो मैं थाली बजाने वाले इस मुल्क में पढ़ना चाहता हूँ। 1980 में वैज्ञानिक चेतना को लेकर भारत के वैज्ञानिकों ने एक बयान जारी किया था। इस बयान में लिखा है कि जब सामाजिक ढांचा और वर्गीकरण तार्किं और वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किए गए समाधानों को लागू करने में रुकावट पैदा करे तो वैज्ञानिक चेतना की यही भूमिका होनी चाहिए कि वह ऐसी सामाजिक रुकावटों की बुनावट की परतों को खोल कर सबके सामने रख दे और बताए कि यह रुकावट क्यों तर्क आधारित नहीं है। लेकिन हम सामाजिक रुकावटों, अंधविश्वास के आगे परंपरा के नाम पर इस तरह से चुप हो गए कि कहीं थाली बजाने और दीया जलाने पर सवाल उठाने का मतलब भारतीयता और परंपरा का अपमान न समझ लिया जाए। इटली में लोग बालकनी पर खड़े होकर नर्स डाक्टर के लिए ताली बजा रहे थे, हमने थाली बजाकर डाक्टर और नर्स को बीच राह में छोड़ दिया। डाक्टर अपनी तनखाव के लिए आंदोलन पर उत्तर आए। वैसे तालाबंदी के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए लोगों ने अपनी बालकनी में खड़े होकर थाली बर्तन बजाए थे।

याद तो होगा ही कैसे ध्वनि प्रदूषण की परवाह किए बिना अस्पतालों के बाहर सेना के बैंड को भेज दिया

गया। अस्पताल के बाहर बैंड बजाने का आइडिया क्या वैज्ञानिक था? लेकिन सरकार की तारीफ हो रही थी, मोटी मोटी हेडलाइनें इतरा रही थीं, अस्पतालों के ऊपर वायु सेना के हेलिकाप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। जबकि कैमरा घूमना चाहिए था कि अस्पतालों के भीतर और सबको बोलने की आजादी होनी चाहिए थी कि यहां क्या है, क्या होना चाहिए। बाहर बैंड बजाता रह गया और आप भूल गए कि अस्पताल में आक्सीजन नहीं है, वैटिलेटर नहीं है। पिछले साल ही बहस होनी चाहिए थी कि अगर मार्च 2020 में सेन सारे प्राइवेट अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है, वहां जनता के लिए इलाज को प्री कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? भारत में न सरकारी अस्पतालों को लेकर बहस हुई और न प्राइवेट अस्पताल को लेकर जिनमें से अधिकांश दुकान ही हैं, अस्पताल नहीं। जहां लोग कैसे कैसे मरे और मारे गए हैं आप जानते हैं मगर बहस के केंद्र में नहीं है। गोदी मीडिया ने पूरा साल तबलीग जमात, सुशांत सिंह की मौत के फर्जी कवरेज में निकाल दिया और आपको बहला दिया। इस बार भी वही हो रहा है। कोविड का कवरेज पीछे जाने लगा है। बिहार मध्यबनी के सकरी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एक तस्वीर आई है। यह तस्वीर ग्लोबल इंडियन के लिए नहीं है। केवल आंतरिक भारतीयों के लिए है ताकि बदनामी न हो। टूल -किट पर फिर से बहस हो रही है लेकिन कोई देखने वाला नहीं कि अस्पतालों में इलाज के टूल किट ही नहीं हैं।

कागज पर मौजूद इस अस्पताल का वजूद आप देख सकते हैं। यह तस्वीर आपसे सवाल पूछ रही है कि आप

सरकार से सवाल पूछें जो आपसे कहती है कि हमें मिलकर कोरोना को हराना है। लेकिन यहां तो मिलभगत के कारण आप और हम कोरोना की जंग हार रहे हैं। आपके परिवारों और परिचितों में इतने लोग मर गए। फैसला आपको करना है। हेडलाइन बदल देने से देश नहीं बदल जाता है। इस वक्त अस्पतालों को मैनेज करने की ज्यादा जरूरत है न कि हेडलाइन मैनेजमेंट की। बात पोल खुलने की नहीं है, वो तो पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है, बात है आपकी जिंदगी की।

शिमला के आईजीएमएस अस्पताल में यह महिला इस्लाइ भावावेश में हैं क्योंकि इनका कहना है कि इनके पति को सही इलाज नहीं मिला। ऑक्सीजन नहीं मिला जिससे उनकी मौत हो गई। अस्पताल खुद ही अपनी पोल खोल रहा है। कह रहा है कि जिन स्टाफ ने गलत व्यवहार किया वो आउटसोर्स वाले हैं। उन्हें अब ट्रेनिंग दी जाएगी कि मरीजों के परिजन से कैसे व्यवहार करें। अस्पताल में जब तक आउटसोर्स और ठेके पर लोग रखे जाते रहेंगे यही होता रहेगा। पूछिए कि क्या बिना ट्रेनिंग के लिए आउटसोर्स पर लोग रख लिए गए? पूछिए कि क्या इन्हें समय पर और पर्याप्त पैसा मिलता है, पूछिए कि आउटसोर्स पर काम करने वाले कब रखे गए और कितने दिन के लिए रखे गए।

याद दिला रहा हूँ ताकि याद रहे कि आपके अपने किस हालात में तड़पा कर मारे गए हैं। यह याद रखना जरूरी है ताकि अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार हो और अस्पताल की जबाबदेही तय हो। पारदर्शिता आए। मरीजों के परिजनों को सारी सूचना दी जाए। याद रखिएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की टीकाकरण नीति पर उठाए गंभीर सवाल

क्या आप उन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं जिन्होंने भारत में रहते हुए कोरोना के टीके की खोज की? क्या आपने उनका चेहरा देखा है जिस तरह मंगलयान के समय प्रधानमंत्री के साथ इसरो के वैज्ञानिकों को घुलते-मिलते देखा था। माना गया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने टीके की खोज की है लेकिन उन भारतीय वैज्ञानिकों का जिक्र मन की बात में नहीं मिलता है। इसी के साथ आपको बताया गया भारतीय कंपनियों ने टीके की खोज की है। इसमें भी साफ हो गया कि सीरम ने टीके की खोज नहीं की है, वो दूसरे की खोज के आधार पर टीका बना रही है। अब बच गई कोवैक्सिन बनाने वाली भारत बायोटेक। इस भारतीय कंपनी का टीका क्यों नहीं कोविशील्ड की तरह उपलब्ध है और कई जगह तो उपलब्ध ही नहीं है। रुकिए, हर बात में वन नेशन एक ही भाषण के तहत बार बार एक नेशन, वन राशन, वन नेशन वन टैक्स की बात करने वाली मोदी सरकार वन नेशन में एक टीका एक दाम की बात करना भूल गई। यही नहीं, टीके की खरीद की नीति ऐसे बनाई कि लगता है वन नेशन नहीं, वन नेशन में हर स्टेट अपना नेशन है, वो अपना ग्लोबल टेंडर निकाले और खरीदे। इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बताया गया लेकिन अब इसकी पोल हर स्तर पर खुलती जा रही है। दुनिया में भी और देश के भीतर भी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि टीका की खरीद और वितरण से नीति का सारा रिकार्ड अदालत में पेश किया जाए। पिछली सुनवाई में ही अदालत का सदेह गहरा हो गया था जब कोर्ट ने सिर्फ इतना समझना चाहिए कि उस नीति का आधार क्या है कि एक ही कंपनी से केंद्र सरकार दामों में टीका खरीद रहा है, राज्य अलग दाम में और प्राइवेट कंपनी अलग दाम में। कोर्ट ने कहा कि हम पालिसी डाक्यूमेंट देखना चाहते हैं कि इसकी समझ किस आधार पर तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कह दिया कि सरकार ने 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के टीका देने की जो नीति बनाई है उसका कोई तार्किक आधार नहीं है। यानी बिना सोचे समझे बनाई गई लगती है।

भारत में महामारी के डेढ़ साल से अधिक अर्सा हो चुका है। इतने लोग मर गए और मार भी दिए गए। तोता रटंत की तरह बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चल रहा है लेकिन अदालत और जनता देख रही है कि हर जगह टीका केंद्र बंद होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्प्रूतनिक की खरीद कैसे हुई है, इसकी सारी जानकारी पेश करें। कोर्ट ने



टीका अभियान की पूरी नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया।

कोर्ट ने सरकार से ये कहा है

■ सरकार बताए कि पहले तीन चरणों में आबादी के कितने प्रतिशत पात्र लोगों को टीका दिया गया है

■ इसमें गांवों और शहरों की आबादी का प्रतिशत भी बताया जाए

■ कोवैक्सिन, कोविशील्ड और स्प्रूतनिक की खरीद का जो भी रिकार्ड है उसका पूरा डेटा दिया जाए

■ जिसमें यह साफ साफ जानकारी हो कि केंद्र सरकार ने किस-किस तारीख को खरीदने के आर्डर की प्रक्रिया शुरू की है

■ हर तारीख को कितने डोज की खरीद का आर्डर किया है, किस तारीख को सप्लाई की बात कही गई है

■ सरकार यह भी बताए कि उसने पहले दूसरे और तीसरे चरण में बाकी आबादी को टीका देने की क्या तैयारी की है?

अब सरकार को बताना होगा कि किस तारीख को टीके का आर्डर किया गया है। दुनिया के कई देश पिछले साल मई जून और अगस्त में ही टीके का आर्डर कर रहे थे। भारत क्या कर रहा था थाली बजाने के अलावा। भारत ने कब टीके का आर्डर किया। जनवरी 2021 में जा कर। इस सवाल का जवाब विपक्ष पूछ रहा था लेकिन सरकार साफ-साफ नहीं बता रही थी।

यही वो सवाल हैं जो राहुल गांधी शुरू से पूछ रहे हैं कि कोरोना से लड़िए लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ लड़िए। हर जानकारी को सामने रखिए और टीका को लेकर इधर-उधर की बात मत कीजिए। सवाल है कि क्या सरकार कोर्ट में यह जानकारी देगी या मना कर देगी, या लिफाफा सिस्टम तो नहीं आ जाएगा कि हम लिफाफे में बताएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान होने के दावे पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि हलफमाना दायर करते समय हर दस्तावेज की कापी लगाएं। फाइल की नोटिंग लगाएं। जिससे पता चले कि टीका की नीति को लेकर क्या सोचा जा रहा था। दो हफ्ते के भीतर हलफमाना देना होगा।

44 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ही टीका नहीं है। जिन्हें पहला डोज लगा था उन्हें दूसरे डोज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। अचानक दूसरे डोज का गैप बड़ा दिया गया कि तीन महीने के अंतराल पर दूसरा डोज लिया जा सकेगा। जिस टीके को भारतीय कहा जा रहा था कोवैक्सिन का पता ही नहीं है कुछ। कंपनी दावा करती है लेकिन लोग टीके का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं राज्यों पर टीका खरीदने के लिए थोप दिया गया ताकि पॉलिटिक्स होती रहे और टीवी में डिबेट होता रहे। जबकि पूरी दुनिया में केंद्र सरकार ही टीका खरीद कर अपने राज्यों को दे रही है। वो भी मुफ्त। केंद्र सरकार को ग्लोबल टेंडर निकालना था लेकिन इसकी जिम्मेदारी राज्यों को दे दी गई। बस

राज्यों से यह नहीं कहा गया कि अपना अपना विदेश मंत्री भी खब लें और दूतावास भी खोल लें।

केरल विधानसभा ने सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से मांग की है कि कोविड का टीका मुफ्त दिया जाए और नागरिकों को समय पर टीका दिया जाए। कुछ दिन पहले ही केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अन्य मुख्यमंत्रियों से केंद्र पर मिलकर दबाव डालने की अपील की थी।

अब उड़ीसा और झारखण्ड ने भी कहा है कि केंद्र सरकार ही टीका खरीदे और राज्यों को दे। दोनों राज्यों ने कहा है कि विदेशी कंपनियां राज्यों से सीधे तौर पर डील नहीं करना चाहती हैं। ओडिशा ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था लेकिन कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। टीका बनाने वाली कंपनियां कानूनी सुरक्षा मांगती हैं, इसकी गारंटी केवल केंद्र दे सकता है। केंद्र को क्या यह पता नहीं था, बिल्कुल पता होगा फिर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी किए बगैर राज्यों पर ग्लोबल टेंडर का भार डाल दिया गया। अब केंद्र सरकार कह रही है कि कानूनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है।

अब वो हेडलाइन गायब हो गई है जिसके जरिए प्रोपैरेंडा रचा गया कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चल रहा है। इसकी हालत ये है कि राज्यों के मुख्यमंत्री सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं। एक दूसरे से अपील कर रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। आम तौर पर कम बोलने वाले और विवादों से दूर रहने वाले नवीन पटनायक को भी यह कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने लिखा है कि

डियर चीफ मिनिस्टर

पिछले एक साल से कोविड-19 की महामारी ने दुनिया भर के देशों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ज्यादातर देशों ने संक्रमण के कई कई लहर देखे हैं। भारत भी अपवाद नहीं है। हम लोग अभी तक दो दो लहर देख चुके हैं। दूसरी लहर के बाद लोग अगली लहर और वायरस के अगले रूप को लेकर डरे हुए हैं। भारत का हर नागरिक इस महामारी को लेकर किसी न किसी रूप में चित्तित है। अपने को खो देने का डर है या नौकरी या कारोबार खो देने का डर है। कोई नहीं बचा है। लोगों को आगे की लहरों से बचाने और उम्मीद देने का एक ही तरीका है टीका। जिन देशों ने टीका अभियान पर ध्यान केंद्रित किया है वहाँ पर कोविड की स्थिति में कमाल का सुधार है। हमें भी अपने लोगों को भरोसा देना होगा। जब तक सभी राज्य टीका को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देंगे, युद्ध स्तर पर काम नहीं करेंगे तब कोई राज्य सुरक्षित नहीं है। लेकिन यह जंग राज्य अकेले नहीं लड़ सकते हैं न ही टीका खरीदने के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए लड़ सकते हैं।

केंद्र सरकार ने जब से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका देने के तीसरे चरण का एलान किया है तब से टीके की मांग बढ़ गई है। इस नीति के कारण राज्य और प्राइवेट सेक्टर भी टीका खरीद सकते हैं। कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाला लेकिन साफ है

कि ग्लोबल कंपनियां केंद्र सरकार की तरफ देख रही हैं। उन्हें केंद्र से स्पष्ट आश्वासन चाहिए। ग्लोबल कंपनियां राज्य सरकारों से सौदा नहीं करना चाहती हैं। दूसरी तरफ घरेलु कंपनियों की भी अपनी सीमाएं हैं, वे भी सप्लाई का वादा नहीं कर पा रही हैं। मौजूदा हालात में एक ही रास्ता है कि केंद्र सरकार टीका खरीदे और राज्यों को बांटे ताकि जल्द से जल्द सभी नागरिकों को टीका मिल सके।

जय हिन्द नवीन पटनायक

इसी तरह का पत्र झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने ने भी लिखा है। अदालत का आदेश हो और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आवाज सब एक तरह से एक ही दिशा में है कि केंद्र खरीदे। इस पूरी प्रक्रिया में डेढ़ महीने से अधिक का समय बर्बाद हुआ है। 19 अप्रैल को केंद्र ने राज्यों को कहा कि वे टीका खरीद लें और 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका देने का काम शुरू कर देंगे। केंद्र के पास टीका खरीदने का डेढ़ साल का वक्त था और राज्यों को टीका अभियान शुरू करने का 11 दिन दिया जाता है। राज्यों के पास पैसे नहीं हैं। केंद्र ने केंद्रीय बजट में टीका अभियान के लिए 35000 करोड़ का प्रावधान किया था।

24 मई को केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार ने रिञ्चर्व बैंक से जो पैसा लिया है, 99,000 करोड़ उसका इस्तमाल टीका खरीदने में व्यय नहीं किया जाता। केरल हाई कोर्ट में भी टीका नीति को लेकर सुनवाई हो रही है। केरल हाई कोर्ट ने तो हिसाब भी लगा दिया कि अगर 250 रुपये के हिसाब से भी टीका खरीदें तो 34000 करोड़ में पूरी आवादी के लिए टीका आ जाएगा। यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि 35000 करोड़ दिया गया था टीके के लिए, इस पैसे का अब तक कैसे इस्तमाल हुआ है। व्ययों इस पैसे का इस्तमाल 18-44 साल की उम्र के लोगों को टीका देने के लिए नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि आप खुद ही कंपनियों से खरीदें लेकिन कितना खरीदेंगे यह केंद्र सरकार बताएगा। पैसा राज्यों का होगा लेकिन सप्लाई का कोटा केंद्र तय करेगा। विपक्ष की सरकारें जहाँ मुख्य हैं वहाँ बीजेपी की सरकारें चुप हैं। लेकिन वहाँ की हाईकोर्ट से आती आवाजों से पता चल रहा है कि उनके पास भी जवाब नहीं है। 26 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में यह तो बताया है कि तीन करोड़ टीके का आर्डर दिया जा चुका है लेकिन यह नहीं बताया है कि टीका कब मिलेगा। इस पर सरकार चुप है। कोर्ट को राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में बताया है कि टीका निर्माताओं ने यह नहीं बताया है कि सप्लाई कब करेंगे।

ये जवाब है गुजरात सरकार का हाई कोर्ट में। आपने हिन्दी में यह समझा कि आप किसी कंपनी को तीन करोड़ टीके का आर्डर देते हैं और कंपनी आपको बताती नहीं है कि टीका कब मिलेगा, फिर भी आप आर्डर देते हैं। ऐसा खरीदार आपने देखा है क्या दुनिया में। माल कब मिलेगा बिना जाने माल का आर्डर दे दिया। जिस पर दावा किया कि दुनिया का सबसे बड़ा

टीका अभियान चल रहा है। इस झूठ का पदार्पण अदालत से लेकर चैराहे तक पर हो चुका है। आप खुद देख रहे हैं। एक ही जगह इस झूठ का परचम लहरा रहा है वो है गोदी मीडिया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हम सब की जिंदगी दांव पर है और इतने लोगों की जान चली गई तब टीका को लेकर ये हाल है। भले शिवराज सिंह चैहान न बोल पाएं लेकिन उनके राज्य की हकीकत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सामने आ रही है। बुधवार को ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार बताए कि राष्ट्रीय टीका नीति के आठवें क्लाज का क्या औचित्य है। इसी के तहत राज्य 25 प्रतिशत खरीद सकेंगे और प्राइवेट सेक्टर भी 25 प्रतिशत टीका खरीद सकेगा। याचिकार्ता वकील सुनील गुप्ता ने सवाल किया है कि अगर प्राइवेट सेक्टर सीधे 25 प्रतिशत टीका खरीद सकता है। एक दिन यह भी घोटाला सामने आ सकता है कि प्राइवेट सेक्टर को 25 प्रतिशत से अधिक टीका दिया गया है। आखिर इसकी निगरानी की प्रक्रिया क्या है। फरवरी में फाइजर ने आपात स्थिति में मंजूरी के अपने आवेदन को वापस ले लिया था। जब लोग मरने लगे तब अप्रैल में कई विदेशी कंपनियों को भारत में टीके की सप्लाई की अनुमति दे दी गई। तब से अब तक दो महीने गुजर गए लेकिन स्पूतनिक के अलावा किसी विदेशी कंपनी का स्पष्ट बयान नहीं है कि टीका कब आएगा। सरकार ने कहा है कि जिस किसी टीके को चुनिंदा देशों में मंजूरी मिली है हम उसे मंजूरी दे देंगे। इसी बात पर पहले मंजूरी नहीं दी गई तो कंपनियां चली गईं। अब जब कंपनियों को बुलाया जा रहा है तो उनके पास इतने आर्डर हैं कि वे भारत के नए आर्डर को लेकर कोई गारंटी देने को तैयार नहीं। राज्यों को तो मना ही कर दिया। यही हाल ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस की दवा को लेकर है।

इस बीमारी के आ जाने के बाद दवा की नीति का एलान होने लगता है। बताया जाता है कि कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है और आयात का आर्डर भी। उस एलान के भी कई दिन गुजर गए हैं लेकिन दवा नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी दवा से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। यही नहीं आज तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य को अभी तक ब्लैक फंगस की दवा क्यों नहीं भेजी गई है। सोचिए वहाँ के मरीजों की क्या हालत हो रही होगी। उनकी किसी की भी वक्त जान जा सकती है। इस हत्या की जिम्मेदारी किसकी है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इसी मामले में केंद्र और राज्य से जवाब मांगा है।

तो इस तरह से सरकार का हर दावा की नीति का एलान होने लगता है। बताया जाता है कि कंपनियों को ध्वस्त हो चुका है। टीका में हो रही देरी देश को किसी और लहर के कगार पर लाकर खड़ा कर देगी। एक बार फिर से तबाही आएगी। नए नए दावों के साथ दिन काटने की यह तरकीब अदालतों के इजलास में लड़खड़ा गई कोविड के कारण न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के हिसाब से कोई दस हजार बच्चे हैं। कुछ के दोनों माता पिता गुजर गए हैं और कुछ के एक। कुछ बच्चे लावारिस भी हैं। ऐसे बच्चों की परवरिश की नीतियां बन रही हैं लेकिन क्या वो काफी होगा।

सीबीएसई की नई मूल्यांकन योजना का स्वागत है



© BCCL 2018. ALL RIGHTS RESERVED.

बोर्ड का वैकल्पिक मूल्यांकन मॉडल छात्रों के लिए अनिश्चितता को समाप्त करेगा। इस वर्ष मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का एक उत्पाद हो सकता है, लेकिन इसे मूल्यांकन मॉडल की व्यापक समीक्षा करने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, विशेष रूप से छोड़ने वालों के लिए स्कूल।

हालाँकि, सरकार, स्कूल बोर्डों और शिक्षा क्षेत्र के लिए कोरोनावायरस महामारी से उत्पन्न व्यवधान में एक मूल्यांकन सबक है। मूल्यांकन के तरीकों में लंबे समय से लंबित संरचनात्मक सुधारों को शुरू करने का समय आ गया है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय (एससी) को बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद कक्षा 12 के छात्रों को अंक देने के लिए अपना मूल्यांकन मानदंड सौंप दिया। फॉर्म्यूले के अनुसार, परिणाम कक्षा 10 और 11 (प्रत्येक में 30: वेटेज होगा) और कक्षा 12 में एक छात्र के प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाएगा, जिसमें 40: वेटेज होगा। कक्षा 10 और 11 के लिए, टर्म परीक्षा में पांच

पेपरों में से तीन में से सर्वश्रेष्ठ अंक पर विचार किया जाएगा। कक्षा 12 के लिए यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखा जाएगा। कक्षा 12 के सभी छात्रों को बराबरी पर रखने के लिए, स्कूलों द्वारा अपनाए गए अंकन तंत्र में अंतर को देखने के लिए एक मॉडरेशन कमेटी हो सकती है। परिणाम 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे।

सीबीएसई की मूल्यांकन योजना का स्वागत किया जाना चाहिए। हो सकता है कि यह सभी हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों को खुश न करे - लेकिन इस समय में परफेक्ट अच्छे का दुश्मन नहीं हो सकता। बोर्ड परीक्षा आयोजित करना एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम होता। और इसलिए एक वैकल्पिक मॉडल की आवश्यकता थी, और तीन वर्षों में एक छात्र के प्रदर्शन की जांच करना अकादमिक कौशल का एक अच्छा संकेतक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल्यांकन सूत्र उस अनिश्चितता को समाप्त करता है जिससे छात्र अब 15 महीने से जूझ रहे हैं, और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देगा। ढांचा, जिसे संशोधित किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो

तो संशोधित किया जा सकता है, अब इसे चालू किया जाना चाहिए।

हालाँकि, सरकार, स्कूल बोर्डों और शिक्षा क्षेत्र के लिए कोरोनावायरस महामारी से उत्पन्न व्यवधान में एक मूल्यांकन सबक है। मूल्यांकन के तरीकों में लंबे समय से लंबित संरचनात्मक सुधारों को शुरू करने का समय आ गया है। एक परीक्षा के आधार पर छात्रों की सीखने की क्षमता, ज्ञान के आधार, रुचियों और कौशल को आंकना और फिर उनके भविष्य को निर्धारित करने का आधार बनाना, खामियां हैं। वर्षों से शैक्षिक पैनल ने शिक्षा को रटने-लटने और बाँ पाठ्यपुस्तक-आधारित जानकारी के पुनरुत्पादन में त्रुटि की ओर इशारा किया है। यह महत्वपूर्ण विश्वेषणात्मक क्षमताओं और एक विषय की एक छात्र की समझ का आकलन करने की कीमत पर आया है, और छात्रों के बीच विविधता की उपेक्षा करता है। मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का एक उत्पाद हो सकता है, लेकिन इसे मूल्यांकन मॉडल की समीक्षा करने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, खासकर स्कूल छोड़ने वालों के लिए।

अस्पतालों के बाहर लाश में बदल रही जनता



सरकार के पास एक साल का वक्त था। अपनी कमज़ोरियों को दूर करने का। उसे पता था कि कोविड की लहर फिर लौटेगी लेकिन उसे प्रोप्रेगेंडा में मजा आता है। दुनिया में नाम कमाने की बीमारी हो गई है।

दुनिया हंस रही है। चार महीने के भीतर हम डाक्टरों और हेल्थ वर्करों को भूल गए। अस्पताल और श्मशान में फर्क मिट गया दिल्ली और लखनऊ का फर्क मिट गया है। अहमदाबाद और मुंबई का फर्क मिट गया है। पटना और भोपाल का फर्क मिट गया है। अस्पतालों के सारे बिस्तर कोविड के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। कोविड के सारे गंभीर मरीजों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा है।

कोविड के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों के मरीजों को कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। कीमो के मरीजों को भी लौटना पड़ा है। अस्पताल के बाहर एंबुलेंस की कतारें हैं। भर्ती होने के लिए मरीज घंटों एंबुलेंस में इंतजार कर रहे हैं। दम तोड़ दे रहे हैं।

जिन्हें आईसीयू की जरूरत है उन्हें जनरल वार्ड भी नहीं

मिल रहा है जिन्हें जनरल वार्ड की जरूरत है उन्हें लौटा दिया जा रहा है। शवों को श्मशान ले जाने के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। सूरत से खबर है कि विद्युत शवदाह गृह में इतने शव जल कि उसकी चिमनी पिंगल गई। लोहे का प्लेटफार्म गल गया। कई और शहरों से खबर है कि श्मशान में लकड़ियां कम पड़ जा रही हैं। अखबारों में जगह-जगह से खबरें हैं। संवाददाता श्मशान पहुंच कर वहां आने वाले शवों की गिनती कर रहे हैं क्योंकि सरकार के आंकड़ों और श्मशान के आंकड़ों में अंतर है। सूरत के अलावा भोपाल और लखनऊ से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। अंतिम संस्कार के लिए टोकन बंट रहा है। एंबुलेंस आने में वक्त लग रहा है। एंबुलेंस के आने में कई घंटे लग रहे हैं। लखनऊ के इतिहासकार और पद्म श्री योगेश प्रवीण के परिजन एंबुलेंस का इंतजार करते रह गए। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा अधिकारी को फोन किया। तब भी एंबुलेंस का इंतजाम नहीं हो सका। ब्रजेश पाठक ने पत्र लिखा है कि हम

लोगों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। यही हाल सैंपल लेने का है। कोविड के मरीज के फोन करने के दो दो दिन तक सैंपल लेने कोई नहीं आ रहा है। सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। सरकार के पास एक साल का वक्त था। अपनी कमज़ोरियों को दूर करने का। उसे पता था कि कोविड की लहर फिर लौटेगी लेकिन उसे प्रोप्रेगेंडा में मजा आता है। दुनिया में नाम कमाने की बीमारी हो गई है। दुनिया हंस रही है। चार महीने के भीतर हम डाक्टरों और हेल्थ वर्करों को भूल गए। उन्हें न तो समय से सैलरी मिली और न प्रोत्साहन राशि। जिन्हें कोविड योद्धा कहा गया वो बेचारा सिस्टम का मारा-मारा फिरने लगा। न तो कहीं डाक्टरों की बहाली हुई और न नसं की।

जो दिखाने के लिए पिछले साल कोविड सेंटर बने थे सब देखते देखते गायब हो गए। आपको याद होगा। साधारण बिस्तोरों को लगाकर अस्पताल बताया जाता था। आप मान लेते थे कि अस्पताल बन गया है। उन बिस्तोरों में न आक्सीजन की पाइप लाइन है न किसी

और चीज की। मगर फोटो खींच गई। नेताजी ने रातड़ं मार लिया और जनता को बता दिया गया कि अस्पताल बन गया है। क्या आप जानते हैं पिछले साल जुलाई में दिल्ली में सरदार पटेल कोविड सेंटर बना था। दस हजार बिस्तरों वाला। एक तो वह अस्पताल नहीं था। ब्वारिटिन सेंटर जैसी जगह को अस्पताल की तरह पेश किया गया। अस्पताल होता तो उतने डाक्टर होते। एंबुलेंस होती। वो सब कहा है? जगह-जगह से फोन आ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीज को ये दवा चाहिए वो दवा चाहिए। इस बात का कोई प्रचार नहीं है कि संक्रमण के लक्षण आने के पहले दिन से लेकर पांचवे दिन तक क्या करना है। किस तरह खुद पर निगरानी रखनी है। कौन सी दवा लेनी है जिससे हालात न बिगड़े। इतना तो डाक्टर समझ ही गए होंगे कि संक्रमण के लक्षण आने के कितने दिन बाद मरीज की हालत तेजी से बिगड़ती है। उससे ठीक पहले क्या किया जाना चाहिए। क्या आपने ऐसा कोई प्रचार देखा है जिससे लोग सतर्क हो जाए। स्थिति को बिगड़ने से रोका जाए और अस्पतालों पर बोझ न बढ़े।

हमने एक मुल्क के तौर पर अच्छा खासा वक्त गंवा दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत नहीं किया। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में टीकाकरण शुरू हो सकता था लेकिन तरह तरह के अभियानों के नाम पर इसे लटका कर रखा गया और निर्यात का इस्तमाल अपनी छवि चमकाने में किया जाने लगा। और जब दूसरी कंपनियों के टीका अनुमति मांग रहे थे तब ध्यान नहीं दिया गया। जब हालात बिगड़ गए तो आपात स्थिति में अनुमति दी गई। अगर पहले दी गई होती तो आज टीके को लेकर दूसरे हालात होते। खैर।

आप खुद भी देख रहे हैं। हर सवाल का जवाब धर्म में खोजा जा रहा है। सवाल जैसे बड़ा होता है धर्म का मसला आ जाता है। धर्म के मुद्दे को प्राथमिकता मिलती है। स्वास्थ्य के मुद्दे को नहीं। आप यही चाहते थे। धर्म की झूठी प्रतिष्ठा का धारण करना चाहते थे। अधर्मी नेताओं को धर्म का नायक बनाना चाहते थे। उन्होंने आपको आपकी हालत पर छोड़ दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है राज्य में हालात भगवान भरोसे है। अस्पतालों का हाल भगवान भरोसे है। जिसे भगवान बनाते रहे वह चुनाव भरोसे हैं। उसका एक ही पैमाना है। चुनाव जीतो।

आप जनता लाचार है। उसकी संवेदना शून्य हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस अपनों को लेकर अस्पताल जा रही है, लाश लेकर श्मशान जा रही है। जनता ने जनता होने का धर्म छोड़ दिया है। सरकार ने सरकार होने का धर्म छोड़ दिया है। मूर्ति बन जाती है। स्टेडियम बन जाता है। अस्पताल नहीं बनता है। आदमी अस्पताल के बाहर मर जाता है।

इस बात का कोई मतलब नहीं है कि गृहमंत्री चुनाव प्रचार में हैं। मास्क तक नहीं लगाते। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में हैं। मास्क लगाते हैं। एक ही बात का मतलब है कि क्या आप बाकई मानते हैं कि मरीजों की जान बचाने का इंतजाम सही से किया गया है? मेरे पास एक जवाब है। आप गोदी मीडिया देखते रहिए। अपने सत्यानाश का घजराहेण देखना चाहिए।

लखनऊ बन गया है लाशनऊ, धर्म का नशा बेचने वाले -लोगों को मरता छोड़ गए



भारत को विश्व गुरु बनाने के नाम पर भोली जनता को ठगने वालों ने उस जनता के साथ बहुत बेरहमी की है। विश्व गुरु भारत आज मणिकर्णिका घाट में बदल गया है। जिसकी पहचान बिना आक्सीजन से मरे लाशों से हो रही थी। अखबार लिखते रहे होंगे कि दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। आम और खास हर तरह के लोगों को अस्पताल के बाहर और भीतर तड़पता छोड़ दिया गया लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार विनय श्रीवास्तव ट्रिवटर पर मदद मांगते रहे। बताते रहे कि आक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। कोई मदद नहीं पहुंची और विनय श्रीवास्तव की मौत हो गई। धर्म की राजनीति के नाम पर लंपटों की बारात सजाने वाले इस देश के पास एक साल का मौका था। इस दैरान किसी भी आपात स्थिति के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को तैयार किया जा सकता था। लेकिन नहीं किया गया। इस बार की हालत देखकर लगता है कि भारत सरकार ने कोविड की लहरों को लेकर कोई आपात योजना नहीं बनाई थी। दरअसल अहंकार हो गया है और यह वास्तविक भी है कि लोग मर जाएंगे फिर भी धर्म के अफीम से बाहर नहीं निकलेंगे और सवाल नहीं कोंगे। लखनऊ अब लाशनऊ बन चुका था। दूसरे शहरों का भी यही हाल था। हालात यह है कि बीजेपी से जुड़े लोग भी अपनों के लिए अस्पताल और आक्सीजन नहीं दिलवा पाए।

पिछले दो महीने किसी के लिए अस्पताल तो किसी के लिए आक्सीजन तो किसी के लिए इंजेक्शन के लिए याद नहीं कितनों को कितनी बार फोन किया होगा। थका देने वाल अनुभव था। सफलता की दर शून्य रही। फ्राड लोग धर्म की आड़ में महान बन गए और लोगों ने सोचना और देखना बंद कर दिया। उस दौर में आपने मूँह सुनने और देखने के लिए अपनी आँखें खोले रखी। इसलिए मेरी कहानी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आम जनता की। जिसके साथ देशभक्ति के नाम पर दुकान चलाने वालों ने गदगी की और बिना आक्सीजन के उसे मरता छोड़ दिया। राष्ट्रवाद कहा है? वह अपने लोगों को अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं दिला पा रहा है। एंबुलेंस नहीं दिला पा रहा है। श्मशान में लकड़ी का रेट बढ़ गया है। लोग अपनों को लेकर चीख रहे हैं। चिल्ला रहे हैं। हिन्दुस्तान का यह संकट वैज्ञानिक रास्तों को छोड़ जनता को मूर्ख बनाने और समझने के अहंकार का संकट है। जनता कीमत चुका रही है। इस हाल में आप खुद को विश्व गुरु कहलाने का दंभ भरते हैं? शर्म नहीं आती है?

इस बीच आई टी सेल सक्रिय हो गया है। गुजरात में लोग मर रहे हैं उस पर वह शर्मिंदा नहीं है। लेकिन मैसेज घुमाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी तो लोग मर रहे हैं। क्या वहां लाशों की रिकार्डिंग करते वक्त फोन की बैटरी खत्म हो जाती है? ये बाला मैसेज आप तक पहुंचा होगा। आपकी मर्जी। आप खुशी खुशी इसकी चेपट में रहें। नोटबंदी के समय कैसा भयावह मंजर था, जब आम लोगों के गुल्लक तक से पैसे उड़ गए, उसी तरह का दौर इस वक्त गुजर रहा है। आम लोगों की सांसें उखड़ जा रही हैं। फ्राड नेताओं ने आक्सीजन का इंतजाम नहीं कर सके और लोग मर गए। वो कल फिर महान बन जाएंगे। धर्म का मुद्दा कम तो है नहीं। कहीं कोई मस्जिद कहीं कोई मंदिर का मसला आ जाएंगा और वे आपके रक्षक बन कर आ जाएंगे। लेकिन जब आक्सीजन देकर रक्षा करने की बात आएंगी तो भाग जाएंगे। कोई व्यवस्थित लोकतंत्र होता तो आपराधिक मुकदमा चलाया जाता सरकार पर। खैर। आप व्हाट्स एप यूनिवर्सिटी में वो जो मुगली घुट्टी पिला रहे हैं पीते रहिए।

इस दौर में आप हिम्मत मत हारिए लेकिन झूठी उम्पीद भी मत रखिए। आपके साथ क्रूरता हुई है। आपको पहले धर्म का नशा दिया गया फिर आपकी पीठ में छुरा मारा गया। फ्राड लोगों का गिरोह दलील दे रहा है कि आधी आबादी बीमार पड़ जाए तो कोई भी अस्पताल फेल हो जाए। मूर्खों ने यह नहीं बताया कि तुमने कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने वेंटिलेटर लगाए हैं, तुमने कितने टेरेसिंग सेंटर बनाए हैं? पत्रकार पूछते रहे कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया, मगर अहंकार सातवें आसमान पर है। जबाब देने की जरूरत भी नहीं। जाने दीजिए। इस वक्त सारा प्रयास लाशों को हेडलाइन से हटाने का हो रहा है। गोदी मीडिया सक्रिय हो जाएगा। एक दो दिन इंतजाम कीजिए। जल्दी खबरें आ जाएंगी कि स्थिति नियंत्रण में आ गई है। फिर एक रिपोर्ट आएंगी कि कैसे प्रधानमंत्री ने रात रात जागकर सब मैनेज किया। यहां पाइप लाइन डलवाई। वहां आक्सीजन भिजवाया। इस तरह श्मशान में अपनों को जला कर लौटे लोग अलग-थलग कर दिए जाएंगे। फिर से आप महान शासक के विश्व गुरु भारत में रहने लगेंगे। एक काम यह भी हो सकता है कि रामदेव की दर्वाई बेचने वाले डॉ हर्षवर्धन को बर्खास्त कर दिया जाए ताकि मोदी जी महान हो जाएँ। बस ऐसी दो चार हेडलाइन की जरूरत है। हेडलाइन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आक्सीजन भले कुछ कम हो जाए।

मौत की संख्या ज्यादा है तो भी राज्य सरकार को बताना चाहिए : प्रधानमंत्री



क्या हम कभी जान पाएंगे कि भारत में कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है। अलग-अलग मॉडल के आधार पर कोरोना से मरने वालों की संख्या तीन लाख की जगह छह लाख भी हो जाती है और 42 लाख तक भी चली जाती है। अलग-अलग मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर गांवों कस्बों में जाकर मरने वालों की संख्या का पता कर रहे हैं तब देख रहे हैं कि सरकारी आंकड़ा बहुत ही कम है। छह लाख की मौत को तीन लाख बता देना और 40 हजार की मौत की जगह चार हजार बता देने का यह खेल कब रुकेगा। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इक्वल्यूएशन की वेबसाइट पर ताजा अनुमान यह है कि भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या 9 लाख से अधिक हो सकती है। इसी तरह न्यूयार्क टाइम्स ने दर्जन भर एक्सपर्ट के साथ मिलकर तीन अनुमान पेश किए हैं। इसके हिसाब से भारत में कोविड से अब तक मरने वालों की संख्या कम से कम छह लाख होगी, मोटा-मोटी 15 लाख और अधिक से अधिक 42 लाख तक हो सकती है। कोई भी मॉडल सरकार के आंकड़े के करीब नहीं है, बल्कि कम से कम डेढ़ गुना या दुगुना तो है ही।

लजारो गामियो और जेम्स ग्लांज ने इसके लिए भारत में हुए तीनों सीरों सर्वों के डेटा को आधार बनाया है। भारत में संक्रमित मरीजों की आधिकारिक संख्या 2 करोड़ 72 लाख है और मरने वालों की आधिकारिक संख्या 3 लाख से कुछ अधिक है। न्यूयार्क टाइम्स ने कम से कम के आधार पर अनुमान लगा कर देखा तो भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 40 करोड़ से अधिक नजर

आती है और मरने वालों की संख्या 6 लाख। अखबार के अनुसार जो संख्या ठीक ठीक बैठती नजर आती है वो है 53 करोड़ से अधिक लगती है और तब मरने वालों की संख्या 16 लाख होगी। अब तीसरा अनुमान खराब से खराब हालत के आधार पर लगाया गया है। इसके अनुसार 70 करोड़ से अधिक संक्रमित हुए होंगे और मरने वालों की संख्या 42 लाख हो सकती है। कई देशों में कोरोना से मरने वालों की संख्या पर सवाल उठे हैं। भारत के आंकड़ों को लेकर केवल बाहर की यूनिवर्सिटी में ही नहीं, बल्कि यहां भी शक की नजर से देखा जा रहा है। लोग भी नोट कर रहे हैं कि सरकारी आंकड़े कम हैं। अगर सरकारी संख्या की विश्वसनीयता इतनी ही होती तो प्रधानमंत्री मोदी को देर से ही सही, यह नहीं कहना पड़ता कि अगर संख्या ज्यादा है तो भी राज्य सरकार को बताना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेसिलविन्या के पीएचडी छात्र आशीष गुप्ता और मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन के मुराद बानाजी ने भी गुजरात को लेकर एक अध्ययन किया है। हिन्दू अखबार में उनका लेख छ्या है। गुजरात का सरकारी आंकड़ा है कि एक साल में कोविड से 9,665 लोग मरे हैं। लेकिन आशीष गुप्ता और मुराद बानाजी का अनुमान है कि पिछ्ले 71 दिनों में कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 82,500 तक जा सकती है। कहां साल भर में दस हजार और कहां 71 दिन में 82 हजार से ज्यादा। आंकड़ों को कितना छ्या लेगी सरकार।

आशीष और मुराद ने दैनिक भास्कर और दिव्य भास्कर को रिपोर्टिंग के आधार पर मरने वालों की संख्या का

अनुमान लगाया है। हाल ही में दिव्य भास्कर के मुताबिक गुजरात में 1 मार्च से 10 मई के बीच मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 1 लाख 23 हजार मौतों का पंजीकरण हुआ है। इन 71 दिनों में पंजीकरण की यह संख्या पिछ्ले साल के ठीक इसी समय की संख्या से बहुत अधिक है। पिछ्ले साल 1 मार्च से 10 मई के बीच 58000 मौतों का पंजीकरण हुआ था। तब भी कोविड की लहर थी। इस संख्या के साथ साथ आशीष और बानाजी ने 2015 से 2018 के बीच गुजरात में मौतों के पंजीकरण की औसत संख्या निकाली और पाया कि इस साल जितनी मौतों का अनुमान था उसकी तुलना में 40,000 मौत ज्यादा हुई हैं। जबकि सरकार कहती है कि इस दौरान 4200 लोग ही मरे। दिव्य भास्कर ने बताया है कि इस साल मरने वालों में 20 प्रतिशत 25 साल से कम थे। आशीष और मुराद ने देखा कि 2018 में 25 साल से कम के नौजवानों के मरने का प्रतिशत 15 था। तो इसी वर्ग में दस प्रतिशत की वृद्धि है। आशीष गुप्ता डेमोग्रेफी एंड सोश्योलॉजी विभाग में पीएचडी कर रहे हैं और मुराद बानाजी गणित के लेक्चरर हैं।

आशीष और मुराद ने लिखा है कि कोविड से मौत का आंकड़ा इसलिए भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि कई बार अस्पताल का डाक्टर ही कोविड से मरने पर भी कोविड कारण नहीं लिखता है। घरों में जो मौत हो रही है, उनकी गिनती नहीं हो रही है। नदियों में किनी लाशें बहा दी गईं और उन्हें परंपरा के नाम पर खारिज कर दिया गया। ये शव बिहार के हैं या यूपी के, इस पर बहस हो गई लेकिन कोविड से इनकी मौत हुई है या नहीं, इसकी गिनती नहीं

हुई। यही नहीं इसकी जांच तो हो रही है कि प्रयागराज के किनारे दफन किए गए शवों से पीली चादरें क्यों हटाई जा रही हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं कि तीन साल पहले भी ऐसे ही दफनाए गए थे। लेकिन कोई नहीं बता रहा कि इनमें से कितनों की मौत कोविड से हुई है। परंपरा ही है तो तीन साल पहले की क्यों, हर साल की तस्वीर हो सकती है, क्या ये परंपरा मार्च और अप्रैल मई महीने में ही देखी गई है। इन तस्वीरों से इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि ये शव कोविड के हैं या नहीं। केवल अस्पतालों में होने वाली मौत की गिनती हो रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूयार्क टाइम्स के एक्सपर्ट ने भी घरों में होने वाली कोविड मरीज की मौत की गिनती को लेकर सवाल उठाया है। बंगलुरु से हमारे सहयोगी नेहाल ने एक रिपोर्ट भेजी है। नेहाल की रिपोर्ट बताती है कि कर्नाटक में होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे 700 लोगों की मौत हुई है। ऐसी संख्या की गिनती अगर हर राज्य से होने लगे तो मरने वालों की संख्या कुछ और होगी। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में कोविड से हुई मौतों को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। 25 जिलों के 28 ब्लॉड्रो प्रमुख और 46 संवाददाताओं ने इस रिपोर्ट पर काम किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दैनिक भास्कर की टीम ने जब 512 गांवों और ब्लॉक्स के रिकॉर्ड देखे और अपनी छानबीन की है। गांगानगर में जहां 48 मौतें बताई गई वहीं वहां के 28 गांवों में ही 50 दिनों के भीतर 517 अर्थियां उठी हैं। 512 गांवों और ब्लॉक में 14,482 अर्थियां उठी हैं। कोरोना की दूसरी लहर में राजस्थान में कोविड से मरने वालों का सरकारी आंकड़ा 3918 है। तीन गुना से अधिक का अंतर है। इस हिसाब से देखें तो देश भर के स्तर पर मरने वालों की संख्या तीन लाख से बाहर लाख से अधिक हो जाती है। न्यूयार्क टाइम्स का अनुमान बहुत दूर नहीं लगते हैं।

मरने वालों की संख्या रहस्य नहीं है। दुस्साहस है। लोग बता रहे हैं और सरकारें चुप हैं। जब डेटा पर इतना संदेह हो तो फिर इस लडाई को झूट से नहीं जीता जा सकता। बोकारो का एक किस्सा इस संर्द्ध में महत्वपूर्ण हो जाता है। अरविंद कुमार मास्क में हैं और अपने सिलेंडर के साथ अपनी बैंक शाखा में चले आए हैं। अरविंद के बेटे सिलेंडर को खींच कर ला रहे हैं और साथ में पत्ती है। इस हालत में अरविंद का बैंक आना उनकी जान के लिए खतरा हो सकता था लेकिन वे यह बताने आए हैं ताकि उनके अधिकारी को भरोसा हो सके कि वे वाकई बीमार हैं। अरविंद का कहना है कि दस दिन से बुखार था जिससे वो ठीक हो गए हैं। इसके बाद भी फैफड़े में संक्रमण के बाद ऑक्सीजन सपोर्ट में है लेकिन बैंक के अधिकारी उन्हें काम पर बुलाते हैं। पेमेंट को लेकर भी खींचतान करते हैं। इसके लिए इस्टीफा भी दे दिया लेकिन मंजूर नहीं हुआ। तो इस हालत में बैंक ही आ गए ताकि अफसर को यकीन हो जाए कि अरविंद आक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कोविड के समय में बैंकों में तबादले भी हो रहे हैं और जो कर्मचारी कोविड से मर रहे हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वित्त मंत्रालय को बताना चाहिए था कि कोविड की दूसरी लहर में कितने बैंक कर्मी दूसरी करते हुए संक्रमित हुए और मरे हैं। जब यूपी के शिक्षकों को मुआवजा मिल सकता है और आश्रित को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है तो बैंक कर्मियों या दूसरे सरकारी सेवकों के लिए ऐसी

नीति क्यों हैं। इसी के साथ यूपी से तीन प्रसंग पेश करना चाहता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में शामली में कुछ गांव वालों को कोरोना की वैक्सीन के बजाए एन्टी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया गया था। यह पता तब चला जब कांदला के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर 72 साल की अनारकली ने टीका लगवाने के बाद एनएम को अपना आधार कार्ड दे कर कहा कि वह उनका आधार नंबर दर्ज कर ले। अनारकली को एनएम ने कहा कि ता काटने का टीका लगाने पर आधार की जरूरत नहीं होती। तब उन्हें पता चला कि उन्हें कुत्ता काटने पर लगने वाली सुई लगा दी गयी है। अब यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में 20 लोगों को कोरोना के टीके की पहली डोज कोविशील्ड और दूसरी कोवाक्सिन लगा दी गयी है। जिले के सीएमओ ने माना कि यह गलती हुई है। दोषी पहचान लिए गए हैं उनके खिलाफ कर्वाई की जाएगी। लेकिन जिन्हें अलग अलग कंपनियों के टीके लग गए हैं उनका बता होगा। सिद्धार्थनगर के औदृहीकलां गांव के रामसूरत ने बताया कि उन्हें और उनके साथियों को जिले के बढ़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 1 अप्रैल को कोविशील्ड लगाई गई थी। 14 मई को उनलोगों को टीके की दूसरी डोज लगाई गई। उनके टीका लगवाने के बाद जब एनएम ने और टीका मंगवाया तब टीका इशु करने वाले डॉक्टर ने बताया कि उनलोगों को गलत टीका लग गया है। गलत टीका लगवाने वाले गांव वाले अब किसी अनहोनी से डेरे हुए हैं। रामसूरत ने कहा कि ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर कुछ गलत हो गया है। उससे कहीं कुछ हो न जाये?

तीसरा प्रसंग कानपुर देहात से है और घटना अप्रैल के पहले हफ्ते की है। इंजेक्शन लगाने वाली साहायक नर्सिंग मिडवाइफरी मोबाइल पर बात करने में इन्हीं मश्शूल थीं कि उससे एक महिला को दो बार टीका लगा दिया। जब महिला ने उनसे पूछा कि क्या अब दोनों डोज एक ही दिन लग रही है। तब उसने महिला से कहा कि तुम टीका लगवाने के बाद यहां से हटीं क्यों नहीं? यह तुम्हारी गलती से दो बार टीका लग गया। देश को चाहिए टीका, बहस हो रही है ट्रिवटर पर। रात भर लोग अपना अकाउंट चेक करते रहे कि ट्रिवटर बंद तो नहीं हो गया। ट्रिवटर को भी झूट के नीचे झूट लिखने की जरूरत ही क्या थी। सरकार है, आपके सच को झूट साबित कर दे, लेकिन अपने झूट को क्यों झूट कहें। हम एक गंभीर मुक्त हैं लेकिन कोई हमें हल्का काम करने से नहीं रोक सकता। लडाई सीमा पर होती है और हम बदला मोबाइल एप से लेने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए ले चलता हूं प्लॉस बैंक में। तभी पता चलेगा कि हमने ठीक एक साल पहले टिक-टॉक को भी सबक सिखाया था, क्या वैसा ट्रिवटर के साथ होने वाला है?

क्या आत्म निर्भर भारत आयात निर्भर भारत बनने लगा है?

जून 2020 का महीना था। तपती गर्मी में तालाबंदी की मार और कोरोना माहामारी सर पर सवार। खबर आ रही थी कि चीन की सेना भारत के पूर्वी लद्धाख की सीमा के भीतर आ गई है। झड़प हुई है जिसमें भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सीमा में कोई नहीं आया। उन्होंने तो उनका नाम तक नहीं लिया। सबने समझा कोई नहीं आया मतलब चीन नहीं आया। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने भी ऐसा ही कहा। राष्ट्र ने गंभीरता से

लिया कि कोई नहीं आया लेकिन तभी खबर आने लगी कि दोनों देश जमीन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सीमा पर सैनिक तैनात हैं तो सिविलियन को भी कुछ करना ही था। व्यापारियों की संस्था सी-एआईटी (बाप्ज) ने बहिकार के लिए 500 सामानों की सूची बना दी। डिबेट होने लगी। उद्वेलित राष्ट्र कहां विश्राम करता है। नजर में आ गया टिक टॉक। नेशन के लोग भूल गए थे कि चीन का है, लाकडाउन में घरों में बंद लोग कूद फांद कर वीडियो बना रहे थे, अपलोड करने की तैयारी में ही थे कि टिक-टॉक बंद। सबने नेशन का साथ दिया। निर्णय कड़ा हो तो नेता भी बड़ा होता है। टिक-टॉक से ग्लोबल हो रहे लोकल कलाकार पुनरु लोकल हो गए। इसके बाद 267 चीनी एप हमने मोबाइल फोन से उड़ा दिए। नेशन ने टकराव का नाम तरीका निकाल लिया। इंट का जबाब पत्थर से देने के बजाए इंट का इस्तमाल विकास में करने लगा। चीन से सामानों के आयात की नीतियां कठोर होने लगीं। 3 जुलाई 2020 का दिन भी कड़े निर्णय लेने वाला ऐतिहासिक दिन था। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि चीन से तनाव के बीच भारत वहां से बिजली के उपकरणों का आयात नहीं करेगा। राज्य सरकारों की बिजली कंपनियों से भी कहा कि वे चीन से आयात न करें। मंत्री जी ने कहा कि हम बर्दाशत नहीं कर सकते कि कोई देश हमारी सीमा में घुस आए। बातों-बातों में हमने चीन को इतना कठोर सबक कभी नहीं सिखाया था।

इसका मतलब यह नहीं कि अपने स्टूडेंट्स को सबक सिखाने के बाद टीचर दोबारा क्लास में नहीं जाएगा। एक साल पहले चीन से आयात पर अंकुश के फैसले को महान बताने वाले मंत्री चीन से आयात पर आंखें मूँदने लगे हैं। आक्रोश की जगह आयात ने ले ली है। चीन से आक्सीजन कंस्ट्रटर और सिलेंडर का आयात होने लगा है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि चीन से छह हजार आक्सीजन सिलेंडर आयात कर लिया गया है। नेशन की नेशनलिट भावनाएं आहत नहीं हुईं। एक साल पहले कहां तो हम चीन के बने एप डिलिट कर रहे थे, एक साल बाद हम चीन के सिलेंडर से आक्सीजन ले रहे थे। बाईं द वे सीमा पर जो विवाद था उसका समाधान फाइनल नहीं हुआ है। कर्नाटक ने भी चीन से 200 आक्सीजन कंस्ट्रटर का आयात कर लिया। बहुत से सामान तो बुहान से आए हैं जहां से कोरोना आया था। राजस्थान ने भी कहा है कि चीन से 6900 आक्सीजन कंस्ट्रटर का आयात करेगा।

अफसोस की बात है कि इन घोषणाओं के खिलाफ पुतला फूंकने वाले इन दिनों अपनी सोच को पोजिटिव करने के जुगाड़ में लगे हैं।

क्या आत्म निर्भर भारत आयात निर्भर भारत बनने लगा है? जाहिर है चीन भी अपनी वाहवाही करेगा। बताने लगा कि भारत की अलग अलग कंपनियों ने चालीस हजार आक्सीजन कंस्ट्रटर के आयात का आडर किया है। भारत में तैनात चीन के राजदूत ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ग्लोबल टाइम्स को बताया है। 29 अप्रैल को चीनी राजदूत ने ट्वीट किया था, चीन से दो हफ्तों के भीतर 61 मालवाहक जहाज आए हैं। 5000 से अधिक आक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति हुई है। 21,569 आक्सीजन जनरेटर और 3800 टन दवाओं की आपूर्ति हुई है। 2 करोड़ से अधिक मास्क की भी आपूर्ति हुई है।

शरद पवार के घर पर विपक्षी की बैठक क्यों हुई, और जहां प्रशांत किशोर फिट बैठते हैं



राष्ट्र मंच क्या हैं?

राष्ट्र मंच द्वारा शरद पवार के घर पर कुछ नेताओं की बैठक बुलाए जाने के बाद सोमवार को एक विपक्षी सभा को लेकर राजनीतिक हलचल शुरू हो गयी थी। तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर सियासी घमासान फिर शुरू हो गया है। जबकि तीसरे मोर्चे की बात बार-बार होती रही है। इस बार मुख्य अंतर यह है कि भारतीय राजनीति में सबसे तेज और सबसे अनुभवी नेताओं में से एक एनसीपी सुप्रियो शरद पवार को एक भूमिका निभाते हुए देखा जा रहा है। जबकि दिग्गज नेता पिछले लगभग दो दशकों से कांग्रेस के करीबी सहयोगी रहे हैं, 22 जून को नई दिल्ली में उनके आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। एक विपक्षी सभा के आसपास राजनीतिक हलचल 21 जून को राष्ट्र मंच के बाद शुरू हुआ - एक ब्रॉड-पार्टी प्लेटफॉर्म जिसे 2018 में एक राजनीतिक कार्रवाई समूह के रूप में लॉन्च किया गया था - जिसे पवार के घर पर कुछ विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई गई थी।

मंच मूल रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और पूर्व राजनीतिक के सी सिंह के दिमाग की उपज था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा (अब तृणमूल कांग्रेस के साथ), जद (यू) के पूर्व नेता पवन वर्मा और तृणमूल के पूर्व नेता दिनेश के साथ-साथ इस विचार को औपचारिक आकार दिया गया और उनके द्वारा एक मंच के रूप में विकसित किया गया। त्रिवेदी (अब भाजपा के साथ) 2017 के अंत की ओर। प्रारंभिक विचार लेखकों, कलाकारों, ट्रेड यूनियन नेताओं और पत्रकारों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को एक साथ लाने के लिए एक मंच स्थापित करना था, जिन्होंने इन नेताओं द्वारा समर्थित भारत के विचार को साझा किया, और जो किसी भी संगठित राजनीतिक संरचना का हिस्सा नहीं थे। राजनीतिक कार्रवाई समूह को औपचारिक रूप से

जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च इवेंट में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चैधरी ने किया था।

इस कार्यक्रम में त्रिवेदी, वर्मा, राकांपा सांसद मजीद मेमन, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता, रालोद नेता जयंत चैधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम पाल, हरसोहन ध्वन और शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद थे।

यशवंत सिन्हा ने उस समय कहा था कि राष्ट्र मंच एक गैर-पार्टी राजनीतिक कार्रवाई समूह होगा, जो किसी विशेष दल के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों को उजागर करने का काम करेगा।

तो तब से राष्ट्र मंच ने क्या किया है?

समूह भाजपा विरोधी आवाजों को रैली करने की कोशिश कर रहा है। इसके सदस्य दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री कमल मोरारका के दिल्ली स्थित आवास पर मिलते

थे। मंच के विचार-विमर्श में प्रोफेसर अरुण कुमार जैसी कई गैर-राजनीतिक हस्तियां शामिल थीं।

जनवरी 2020 में, सिन्हा ने सीएए और प्रस्तावित एनआरसी के विरोध में राष्ट्र मंच के बैनर तले गांधी शांति यात्रा शुरू की। मार्च 2021 में, सिन्हा, जिन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया था, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल में शामिल हो गए। चुनावों में भाजपा की करारी हार के बाद, तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने संघीय मोर्चे का आँदोलन किया। इसी तरह का विचार पहले टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रखा था। केसीआर के नाम से मशहूर राव ने 2018 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की थी, लेकिन बातचीत ज्यादा नहीं चल पाई थी और पार्टियों ने 2019 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा था। भाजपा की 2019 की जीत ने विपक्ष को चैकॉ दिया - कई अभी भी अचंभे में हैं। केसीआर जैसे तीसरे मोर्चे के समर्थक और समर्थक चुप हो गए, और कभी-कभी संसद में महत्वपूर्ण कानून पर भाजपा का समर्थन भी किया। तीसरे मोर्चे के मूल समर्थक, वामपंथी दल, उस रास्ते को फिर से लेने के लिए उत्सुक नहीं लग रहे थे।

फिर 22 जून की बैठक का क्या महत्व है?

उत्साह ज्यादातर शरद पवार के मैके पर आने के कारण रहा है, जिनकी राकांपा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपी का हिस्सा थी, और जो अब महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के साथ सत्ता साझा करती है।

22 जून की शाम को मंच की बैठक के बाद, राकांपा नेता मजीद मेमन ने इस बात से इनकार किया कि पवार ने बैठक बुलाई थी, भले ही उन्होंने इसकी मेजबानी की थी।

मेमन ने यह भी दावा किया कि यह सुझाव कि बैठक विशेष रूप से कांग्रेस को छोड़कर भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट करने का एक प्रयास था, हृनिराधारह थे।

जबकि महाराष्ट्र में महा विकास अंगाड़ी गठबंधन सरकार के भीतर वास्तव में कुछ गड़ग़ड़ाहट है, राष्ट्र मंच कहाँ फिट बैठता है?

कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि यह पानी का परीक्षण करने का प्रयास हो सकता है - और कांग्रेस और भाजपा दोनों को एक संकेत भेज सकता है। राष्ट्र मंच ने अब तक खुद को राजनीतिक विचारधारा के लिए अपने सदस्यों की कभी-कभार होने वाली बैठकों तक ही सीमित रखा है - और इस बैठक के लिए इसे सामने रखने से योजना को गति नहीं मिलने की स्थिति में एक कवर मिलता है।

कई विपक्षी नेताओं ने लंबे समय से शिकायत की है कि कांग्रेस भाजपा से मुकाबला करने के लिए किसी भी ठोस प्रयास के लिए आवश्यक नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ है। तो क्या इस कदम का मकसद कांग्रेस को नींद से जगाना है?

कुछ विपक्षी नेताओं का विचार है कि गैर-कांग्रेसी दलों को जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस द्वारा पहल करने की प्रतीक्षा किए बिना हाथ मिलाना चाहिए। उनका मानना है कि कांग्रेस चाहे तो इस समूह में



शामिल हो सकती है।

हालाँकि, यह नेतृत्व के सवाल को जन्म देता है। वाम दलों का मानना है कि एक गैर-भाजपा गठन कांग्रेस के बिना व्यवहार्य नहीं होगा, जिसकी अखिल भारतीय उपस्थिति है। कुछ विपक्षी नेताओं की उपस्थिति में राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी करने का पवार का निर्णय शायद राजनीतिक मूड़ को मापने का एक प्रयास है।

पवार की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, और बैठक को महत्व प्रदान करती है। वह भारत के सबसे वरिष्ठ सक्रिय विपक्षी राजनेता हैं। स्येक्टर के अधिकांश नेताओं के साथ उनके अच्छे समीकरण हैं। उनके विशाल प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव को देखते हुए उन्हें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक विश्वसनीय चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। हालाँकि, उम्र पवार के पक्ष में नहीं है - वह पहले से ही 80 वर्ष के हैं, और अगले लोकसभा चुनाव के समय तक 83 वर्ष के हो जाएंगे।

फर भी, कुछ विपक्षी नेताओं का मानना है कि चुनाव के बाद नेतृत्व के विवादास्पद और पेचीदा सवाल को छोड़कर, वह भाजपा विरोधी दलों को एक साथ लाने के लिए शीट एंकर की भूमिका निभा सकते हैं, अगर स्थिति पैदा होती है।

पार्टियों के बीच सीट बंटवारे और सीट समायोजन का मुद्दा भी पेचीदा है। लेकिन ज्यादातर नेताओं का मानना है कि पहला कदम पार्टियों को एक मंच पर लाना होगा।

प्रशांत किशोर कहाँ फिट होते हैं?

प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की जीत के बाद उच्च सवारी कर रहे हैं, जिनके पुनः चुनाव अभियान में उन्होंने कामयाबी हासिल की। वह पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी हैं। उन्होंने डीएमके और वाईएसआरसीपी के अभियानों को संभाला है, और उनके पास एम के स्टालिन और वाई एस जगन मोहन रेड़ी दोनों के साथ संचार की लाइनें खुली हैं।

किशोर के पास राजनीतिक कद की कमी है। आखिरकार, वह एक बैकरूम ऑपरेटर है। लेकिन एक बार जब पवार एक किशोर ऑपरेशन के लिए अपना वजन बढ़ा देते हैं, तो वह बाधा दूर हो जाती है। किशोर पिछले दो हफ्तों में पवार से दो बार मिल चुके हैं। यह

स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने क्या चर्चा की - हालाँकि, राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी करने का पवार का फैसला उस दिन आया जब किशोर उनसे दूसरी बार मिले थे। सार्वजनिक रूप से किशोर ने मंगलवार की बैठक और तीसरा मोर्चा बनाने की संभावित कोशिशों से खुद को दूर कर लिया है। वह एक समय राहुल गांधी के करीबी थे, और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के अभियान का प्रबंधन किया था।

क्या इस तरह के मोर्चे के निर्माण से कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला है?

कांग्रेस के पास हासिल करने के लिए कुछ नहीं है। वास्तव में, यह आख्यान कि पार्टी विपक्ष का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, कुछ पार्टियों को तीसरा मोर्चा बनाने का विकल्प तलाशने के लिए छोड़ देना, कांग्रेस के लिए बुरा है।

तथ्य यह है कि कई पार्टियों को कांग्रेस के साथ व्यापार करना मुश्किल होगा, अपने राज्य के गढ़ों में स्थिति को देखते हुए - उदाहरण के लिए आप, टीआरएस, अकाली दल और बीजद, राज्य स्तर पर कांग्रेस के सभी प्रतिद्वंद्वी हैं। सपा और बसपा जैसे कुछ अन्य लोग कांग्रेस से दूरी बनाए रखना पसंद करेंगे।

कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि तीसरे मोर्चे का प्रयोग विफल होने के लिए अधिष्ठात्र है - और यह कि कांग्रेस के बिना एक विपक्षी मोर्चा अव्यावहारिक है। उनका मानना है कि व्यापक विपक्षी एकता संभव है, लेकिन केवल कांग्रेस के नेतृत्व में। हालाँकि, राज्य-स्तरीय समीकरण क्या हैं, यह कल्पना करना मुश्किल है कि लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कैसे काम कर सकता है।

क्या बनर्जी, पवार, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को कहना चाहिए कि नवीन पटनायक और उद्घव ठाकरे भी हाथ मिला ले, यह कांग्रेस के लिए बुरा खबर होगी। जटिल विपक्षी परिवर्तन, और क्षेत्रीय दलों के दबाव और दबाव ने अतीत में एक विश्वसनीय तीसरे मोर्चे के गठन में अक्सर बाधा डाली है भाजपा विरोधी गठबंधन के उभरने के रास्ते में यही कारण आने की संभावना है।

पवार का एक प्रयास - यदि वे वास्तव में ऐसा करते हैं - विपक्षी राजनीति में एक आकर्षक चरण की शुरूआत होगी।

जीवन को बचाने वाले को भी निर्दयी कोरोना ने नहीं बख्शा



18 मई 2021 इतना मनहूस होगा, कल्पना नहीं थी। उस दिन अपराह्न डॉ० प्रभात कुमार चले गये। लाखों, करोड़ों लोगों के जीवन को बचाने वाले को भी निर्दयी कोरोना ने नहीं बछाया। पटना के मेडिवर्सल अस्पताल से हैदरगाबाद के प्रसिद्ध किंग्स अस्पताल तक उनकी यात्रा जल्दी हो पूरी हो गई। यात्रा तो एक दिन सबकी पूरी होती ही है लेकिन वे अपनी यात्रा इतनी जल्दी पूरी कर लेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने पीछे न केवल परिवार बल्कि बिहार के लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को भी आधा-अधूरा बीच में ही छोड़ दिया। उनसे अपने सम्बंधों को याद कर मत विचित्र हो जाता है, लेकिन प्रकृति को इससे क्या लेना-देना। सैकड़ों शिक्षकों के फोन आ रहे हैं जिनसे उनकी व्याकुलत उजागर हो रही है। आखिर हम कर ही क्या सकते हैं?

डॉ० प्रभात कुमार से मेरी पहली मुलाकात 2004 में

नयी दिल्ली में सिक्खों के एक अस्पताल में हुई थी। हमारे मित्र का० बच्चन प्रभाकर ने उनके पास मुझे भेजा था। मेरी पुत्री रोति को हृदय सम्बंधी बीमारी का संदेह हुआ। मैं ऐस्स नयी दिल्ली जाने की सोच रहा था। लेकिन वहाँ की भोड़ और प्रक्रिया देखकर मैं भयभीत था। बच्चन जी आवास पर आये थे। चर्चा चली तो उन्होंने डॉ० प्रभात कुमार का परिचय देते हुए भरोसा पूर्वक एक सिफारिशी पत्र दिया। दिल्ली पहुँचकर खोजते-खोजते मैं उस अस्पताल में पहुँचा। मेरा नाम सुनकर एक हँसता मुस्कुराता नौजवान गले में आला लटकाये बाहर आया। मुझे अपने कमरे तक ले गया और तुरन्त मेरी बातें सुनकर ऐस्स में पैरवी कर दी। मुझे उस डॉक्टर से मिलने को कह दिया। दूसरे दिन में भीड़भाड़ वाले उस दिल्ली ऐस्स में पहुँचा। खोजते खोजते डॉक्टर तक पहुँचा। पता चला कि डॉक्टर लैब

में हैं। वहाँ तक मैंने खबर भिजवाई और डॉक्टर यादव ने लैब में ही रोति को बुलाकर देख सुनकर दर्वाई लिख दी। दिल्ली से लौटकर बच्चन जो को बताया। वे भी सन्तुष्ट हुए। इसके पूर्व डॉ० प्रभात कुमार से मैं कभी मिला भी नहीं था। बात आयी गयी ही गई।

नयी दिल्ली छोड़कर डॉ० प्रभात कुमार 2005 में हार्ट हास्पीटल में योगदान कर लिए। उस समय कार्डियोलाजी में डॉ० ए.के. ठाकुर एक बड़ा नाम था। इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान पटना को डॉ० ठाकुर ने ही पहचान दिलाई थी। बाद में कंकड़बाग में उन्होंने अपना अस्पताल हार्ट हास्पीटल शुरू किया था। डॉ० ठाकुर, डॉ० प्रभात जी के गुरु थे और उनकी काबिलियत, मिहनत और शील स्वभाव से परिचित थे। बच्चन जो उनके आवास पर हमेशा एक दो दिन के अन्तराल पर जाया करते थे और वहाँ से मेरे यहाँ आते

थे। एक दिन उन्होंने सूचना दी कि डॉ० प्रभात हार्ट हास्पीटल में आ गये। अब हमलोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक दिन उनके छोटे-छोटे बच्चों के एक निजी स्कूल में नामांकन के लिए पैरवी भी किये। अब बच्चन जो ही हमारे और डॉ० प्रभात कुमार के बीच एक सेतु बन गये। उसके पहले तक मैं किसी बीमारी के लिए पाली क्लीनिक में डॉ० ए.के. गौड़ अथवा डॉ० शकील के यहाँ जाया करता था। चूंकि पाली क्लीनिक भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। इसलिए उस पर विशेष अधिकार बनता था।

2008 में एक दिन दिल्ली से लौटने के क्रम में मुझे ट्रेन में कुछ कठिनाई महसूस हुई। घर लौटा तो उस दिन तैयार होकर विधान परिषद में मीटिंग अटेंड किया। शिक्षक संघ में कुछ आवश्यक कार्यों की भीड़ थी। शाम तक निपटाकर पाली क्लीनिक जाकर ई.सी.जी. कराया लेकिन कोई लक्षण नहीं मिला। रात आठ बजे हार्ट हास्पीटल जाकर प्रभात जी को दिखाया सब नॉर्मल मिला लेकिन रात दो बजे भारी एंजाइन दर्द हुआ। जल्दी-जल्दी हार्ट हास्पीटल गया। पहुँचते ही बहेश हो गया। हार्ट अटैक हो चुका था। डॉ० प्रभात कुमार आवास जा चुके थे। आनन-फानन में बुलाए गये। उन्होंने ही इलाज किया। सुबह नोंद टूटी तो आई.सी.यू. में था। डॉ० ठाकुर, डॉ० प्रभात कुमार का इलाज चला। कई दिनों के बाद अस्पताल से मुक्त हुआ तो बच्चन जी ने बताया कि डॉ० प्रभात ने काफी मिहनत करके जान बचायी क्योंकि वही हमारे बीच सेतु थे। तब मैं डॉ० प्रभात कुमार का एक पेशेन्ट था। डॉ० प्रभात जी के सौजन्य से ही एस्कोर्ट्स में जो बाद में फोर्टीस में तब्दील हुआ, मैं इलाज के लिए गया। सारी व्यवस्था उन्होंने ही किया।

मैं तो दिल्ली से एकदम अन्जान था। उस समय डॉ० अशोक सेठ अमेरिका में थे, फलतरु डॉ० कलेर ने मेरा ए.जी.ओ.प्लास्टी किया। एक साल तक एक्कोर्ट्स में रोटीन चेकअप कराता रहा। बाद मैं हार्ट हास्पीटल में चेकअप होने लगा और डॉ० साहब से नजदीकियों ज्ञों-ज्ञों बढ़ती गई उनके गुणों से अवगत होने का अवसर मिलता गया। उन्होंने पटना में हृदय की चिकित्सा को एक नया आयाम दिया और हार्ट हास्पीटल में एन्जियोप्लास्टी, बाल्ब बदलना आदि ऑपरेशनल काम भी उनके नेतृत्व में शुरू हो गया। गाँवों के निम्न मध्यवर्ग के मरीजों की सफल चिकित्सा होने लगी। नयी दिल्ली जाने की जरूरतें कम पड़ गई।

बच्चन जी के निधन के बाद एक दिन अचानक सुबह-सुबह डॉ० प्रभात मेरे आवास पर आये। मैं आश्वर्यकृत हुआ कि क्या बात है? वे बच्चन जी को बहुत आदर करते थे और इस बात से परिचित थे कि मैं उनका अभिन्न हूँ। चाय के क्रम में प्रभात जी ने कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि गाँव में बच्चन भैया की प्रतिमा लगायी जाय। उनके नाम पर कोई पुस्तकालय या हेल्थ सेन्टर संचालित हो। इस काम में आपका सहयोग चाहिए। तत्काल हमलोगों ने योजना को अनिम रूप दिया और उसी दिन से उनके आवास पर मेरा आना-जाना शुरू हुआ। बच्चन जी के चलते डॉ० साहब के गाँव के मुखिया, डॉक्टर, इंजीनियर, आदि सभी बड़े लोग मुश्खले परिचित थे। वशिष्ट मुखिया जी तो मेरे चुनाव में भगवानपुर हाट बूथ ही सम्हालते थे। उधर के तीन प्रखण्डों वसंतपुर, लकड़ी नबोगंज और भगवानपुर का



सारा भार बच्चन जी ही खुद ओढ़ लेते थे। गाँव में बच्चन जी की जमीन पर एक सामुदायिक भवन का० बढ़ीनारायण लाल के ऐच्छिक कोष से बना था। बाद में मैंने चार लाख रुपये खर्च कर उसकी मरम्मत, चहारदीवारी रंगाई-पोटाई करायी थी उसी में बच्चन जी की प्रतिमा लगायी गयी। उनको पुण्यतिथि पर एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ। मैंने जिले की कम्युनिष्ट पार्टी और क्षेत्र के लोगों को मुखिया जी ने लगाया। समारोह की सारी व्यवस्था शामियाना, माइक, कुर्सी, जलपान आदि का प्रबंध डॉ० प्रभात कुमार के सौजन्य से हुआ। उनके सभी भाई समारोह में लगे रहे। एक दिन पहले थोड़ा सर्दी जुकाम के कारण उन्होंने हमसे न जाने की अनुमति मांग ली। समारोह डॉक्टर प्रभात के अनुसार अच्छे तरीके से सम्पन्न हुआ। डॉ० साहब, उनका परिवार, बच्चन जी के दामाद मुरारी, बेटियां परिवार वाले काफी प्रसन्न हुए।

डॉ० प्रभात से हमारी नजदीकियाँ बढ़ती गई और जब किसी शिक्षक या मित्र को डॉ० प्रभात से दिखाने की आवश्यकता हुई, मैंने फोन करके समय दिला दिया। सैकड़ों शिक्षकों का कल्याण हुआ। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नाम पर वे आसानी से उसी दिन देख लेते और मेडिकल का जो बिल होता उसमें दस-बीस हजार छोड़ भी देते। जबकि उनके यहाँ रोगियों की अपार भीड़ के चलते छ: छ: महीने पर एप्लायांटमेंट मिलता। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ अथवा कम्युनिष्ट पार्टी के साथियों के लिए डॉ० प्रभात कुमार का दरवाजा हमेशा खुला रहता। उनसे परिवारिक रिश्ते जुड़ गये। मेरे बेटे फोन करके या वाट्सअप से उनसे सलाह मशविरा कर लेते समय तय करा देते। उनकी महानता का यह आलम था सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उनके ड्राइंग रूप से बाहर बैठे मेरे ड्राइंगर, अंगरक्षक को भी बाहर निकलकर खुद चाय नशता पूछते बाहर मेरी गड़ी तक मुझे छोड़ते।

प्रतिवर्ष छठ महापर्व के अवसर पर एक या दो दिन के लिए डॉ० प्रभात कुमार अपने गाँव बड़कागाँव जरूर जाते। यह सिलसिला बच्चन प्रभाकर के जीवित रहते ही शुरू हो गया था। अगल-बगल के गाँवों से हजारों लोग उनसे दिखाने के लिए आते। वे किसी व्यक्ति को

निराश नहीं करते। जब तक सरे लोगों को देखकर सन्तुष्ट नहीं कर लेते तब तक देखने का सिलसिला बन्द नहीं होता। लोग वर्षों से छठ का इत्तजार करते अपने पास जो दवाइयाँ होती मुफ्त में देते। कुछ लोगों को जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते पटना बुलाकर देखते यह सिलसिला उनका लगातार आजीवन जारी रहा।

डॉ० प्रभात कुमार का एक ही सपना था कि पटना में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल शुरू किया जाय जहाँ एक छठ के नीचे गरीबों को सभी प्रकार के इलाज की व्यवस्था हो इसके लिए राजेन्द्र नगर में जमीन लेकर उन्होंने कायारंभ भी कर दिया था। अगर 2020 में कोरोना की लहर नहीं आई होती तो ओ. पी.डी. शुरू हो गया होता लेकिन काल को यह मंजूर नहीं था। यह प्रोजेक्ट बिहार के लोगों के लिए एक बरदान होता। लेकिन सपने जल्दी पूरे कहाँ होते हैं? हमारा सपना था कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में हृदय रोग पर उनका एक व्याख्यान कराऊँ और शिक्षकों से उन्हें और जोड़ हूँ। लेकिन मन की बात मन में ही रह गई। पहली जनवरी को प्रतिवर्ष मेरे आवास पर आकर मुझे एक बेहतरीन कलम और डायरी देते लेकिन अब वह भी संभव नहीं हो पायेगा। पहली जनवरी 2021 में मेरे जन्मदिन पर उनके द्वारा भेट कलम उनकी आखिरी निशानी होगी। फोन पर ठीक से रहने अथवा जांच कराने के लिए उनके द्वारा बुलावा भी नहीं आ पायेगा? आज सोचता हूँ तो मन का विश्वास और गहरा होता जाता है। ये पक्षियाँ उन पर कितना सटीक बैठती हैं। हजारों साल नर्सिंग अपनी बेनूरी पे रोती हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा काल कितना क्रूर है। नियति कितनी प्रबल है। जब उनके नहीं होने का समाचार आया तो मैं सीवान के जिला पदाधिकारी के साथ कोरोना पर एक वच्चर्वल बैठक में था। दो दिन पहले उनके भाई से उनके स्टेंबल होने की सूचना मिली थी। अन्दाजा था कि मई के आखिर तक वे पटना लौटेंगे लेकिन लौटने ही रह गया। डॉ० साहब! बिहार और देश बड़े गौर से आपको सुन रहा था। आप कहाँ चले गये?

**बड़े गौर से सुन रहा था जमाना,
तुम्हीं सो गये दास्तों कहते-कहते।**

घाटी में नए प्रकार के युद्ध के प्रवेश का संकेत



जम्मू में भारतीय वायु सेना स्टेशन पर इंपैक्ट चार्ज से लैस इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के दो किलोग्राम से अधिक के दो बम को गिराया गया। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि आतंकवादी हमले में दो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और एक घट्टच्च ग्रेड विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था।

यह घटना घाटी में नए प्रकार के युद्ध के प्रवेश का संकेत है। ड्रोन का इस्तेमाल पहले हथियारों के परिवहन और गिराने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह पहली घटना है जब ड्रोन का इस्तेमाल किसी हमले को अंजाम देने के लिए किया गया है।

डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए दोनों धमाकों में ड्रोन के इस्तेमाल होने की आशंका है। धमाकों में दो लोगों को मामूली चोट आई है। विस्फोट शनिवार दोपहर 1.37 बजे और 1.42 बजे हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाकों की आवाज दो किलोमीटर दूर से सुनी गई।

पुलिस ने यह भी कहा कि जम्मू पुलिस ने नवाल इलाके से 5-6 किलोग्राम वजन का एक आईईडी

बरामद किया। पुलिस ने कहा कि बरामदगी से एक बड़ा आतंकी हमला टल गया है और मामले में हिरासत में लिए गए संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस विफल आईईडी विस्फोट के प्रयास में और भी संदिग्धों के पकड़े जाने की संभावना है। पुलिस ने कहा कि वे अन्य एजेंसियों के साथ जम्मू हवाई क्षेत्र में हुए विस्फोटों पर काम कर रहे हैं और इस मामले की एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जांच जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक टीम रविवार तड़के जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर पहुंची।

भारतीय वायु सेना के प्रवक्ता ने रविवार सुबह कहा, हजाम्मू वायु सेना स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में रविवार तड़के दो कम तीव्रता वाले विस्फोटों की सूचना मिली। एक ने एक इमारत की छत को मामूली नुकसान पहुंचाया, जबकि दूसरा एक खुले क्षेत्र में विस्फोट हुआ। किसी भी उपकरण को कोई नुकसान नहीं हुआ। सिविल एजेंसियों के साथ जांच जारी है।

21 जून को, श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, डीजीपी ने कहा था कि कुपवाड़ा सेक्टर से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी हो

रही थी और हाल ही में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और हथियार जब्त किए गए थे। उन्होंने कहा था, जम्मू में एलओसी और आईबी पर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की घुसपैठ हो रही थी, जो फिलहाल रुक गई है।

हालांकि जम्मू हवाई अड्डे पर ड्रोन हमलों में किसी की जान नहीं गई, फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर यह आतंक के एक नए अभियान में पहला बचाव है, तो यह कश्मीर आतंकवाद में एक खतरनाक चरण का प्रतीक है, जिसके परिणामस्वरूप भारी हताहत हो सकते हैं। अभी तक, जो ड्रोन हमले के बारे में सुनते हैं, वह यह है कि ये अपेक्षाकृत कम तीव्रता वाले बम थे और जिन ड्रोनों ने उन्हें जमा किया था, उन्हें सटीक जीपीएस निदेशांक पर ऐसा करने के लिए पूर्व-क्रमादेशित किया गया था।

पहले बम ने एक तकनीकी इमारत को नुकसान पहुंचाया, दूसरा एक खुले क्षेत्र में विस्फोट हुआ। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों ने पहले से ही गुब्बारों से जुड़े इस तरह के बमों का इस्तेमाल किया

था। ये बम प्रशांत महासागर के पूरे क्षेत्र को पार करेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी समुद्र तट पर अपना पेलोड जमा करेंगे। सैन्य रूप से, हालांकि, वे पूरी तरह से महत्वहीन थेरू प्रशांत क्षेत्र में 9300 से अधिक बम भेजे जाने के बावजूद केवल एक व्यक्ति मारा गया था। प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि में आतंक की भावना पैदा करना और अमेरिका द्वारा संचालित दण्ड से मुक्ति की भावना को समाप्त करना था। इसमें वे शानदार ढंग से विफल रहे।

पिछले 30 वर्षों के दौरान, ड्रोन ने महत्वपूर्ण रूप से विकसित किया है और क्षमता में बढ़े ऐमाने पर छलांग लगाई है। उन्होंने अफगानिस्तान और अन्य हॉटस्पॉट में अल कायदा और अन्य आतंकवादी संगठनों पर कहर बरपाया है, जिनका उपयोग इजरायल और अमेरिकियों दोनों द्वारा लक्षित और सटीक उन्मूलन के लिए किया जाता है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हालिया युद्ध में हमने ड्रोन के एक वीडियो फुटेज को अपने लक्ष्यों पर झपट्टा मारते हुए देखा है जैसे कि दहला देने वाले रूसी 300 वायु रक्षा प्रणाली। जो चीज इन हथियारों को विशेष रूप से खतरनाक बनाती है, वह यह है कि वे बहुत कम उड़ान भरते हैं जिससे वे रडार के संपर्क में आने से बच जाते हैं और यदि पकड़ में आये भी तो तुरंत निकल जाते हैं। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि इन आधुनिक ड्रोनों में एक अत्यंत उच्च प्रौद्योगिकी है। आमतौर पर, दो तरह से डेटा ट्रांसफर के लिए आवश्यक विशाल बैंडविड्थ के साथ समस्याएँ

भारतीय वायु सेना के प्रवक्ता ने रविवार सुबह कहा, हजारी वायु सेना स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में रविवार तड़के दो कम तीव्रता वाले विस्फोटों की सूचना मिली। एक ने एक इमारत की छत को मामूली नुकसान पहुंचाया, जबकि दूसरा एक खुले क्षेत्र में विस्फोट हुआ। किसी भी उपकरण को कोई नुकसान नहीं हुआ। सिविल एजेंसियों के साथ जांच जारी है।

21 जून को, श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, डीजीपी ने कहा था कि कुपवाड़ा सेक्टर से नशीले पदार्थी और हथियारों की तस्करी हो रही थी और हाल ही में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और हथियार जब्त किए गए थे। उन्होंने कहा था, शजमू में एलओसी और आईबी पर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थी और हथियारों की घुसपैठ हो रही थी, जो फिलहाल रुक गई है।

होती हैं जैसे कि छवि को रिले करना और उपग्रह के माध्यम से ड्रोन और ऑपरेटर के बीच सूचना को लक्षित करना क्योंकि वहां संचार की रेखा एक निश्चित दूरी से परे संभव नहीं है।

ध्यान दें कि हालांकि आज के ड्रोन सैन्यीकृत ड्रोन नहीं थे, लेकिन एकी संभावना में, सस्ते वाणिज्यिक ड्रोन जो पूर्व-प्रोग्राम पर आधारित सही ठिकानों पर उड़ सकते हैं या वहां की रेखा के भीतर रेडियो नियंत्रित हो सकते हैं। इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि कैसे आतंकवादी समूह इन उपकरणों के साथ-साथ सीमाओं और अवसरों का उपयोग करने का इरादा रखते हैं। शुरूआत के लिए ऐसा लगता है कि हमला अपेक्षकृत कच्चे उपकरण द्वारा किया गया है, जो पूर्व नियंत्रित जीपीएस निदेशांक पर विस्फोट करने के लिए सेट है और ऐसा लगता है कि रिमोट ऑपरेटर द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है। यह हमें भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, सभी संवेदनशील प्रतिष्ठानों में जीपीएस जैमर लगाने से यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे ड्रोन जीपीएस सिग्नलों के जाम होने के कारण अपने रास्ते से हट जाएं। इसी तरह, हम वाणिज्यिक ड्रोन निर्माताओं के साथ जियो फैसिंग समझौते कर सकते हैं। इस तरह के एक समझौते से यह सुनिश्चित होगा कि निर्माता अपने उत्पादों में प्री-प्रोग्राम कोड डालते हैं जो उन्हें कुछ क्षेत्रों में या उसके आसपास उड़ान भरने से रोकते हैं - विशेष रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के आसपास।



कोरोना ने बदल दी 'अंतिम संस्कार' की परिभाषा



हिन्दू धर्म में अंतिम संस्कार का अपना एक अलग ही विधान पुराणजीवियों के द्वारा बताया गया है। इसमें मरने के बाद सबसे पहले यह देखा जाता था कि मरने वाला अच्छे समय में मरा है या नहीं। अगर मरते समय पंचक लगा होता था तो अंतिम क्रिया के पहले पंचक शाति के लिये पूजा होती थी। अंतिम क्रिया में चिता की लकड़ी आम और चंदन का प्रयोग होता था। धी और गंगाजल का प्रयोग होता था। शव की अंतिम क्रिया से पहले नदी के पानी में नहलाया जाता था।

मरने वाले की आत्मा को शाति मिले इसके लिये गाय का दान और कई तरह के दान पंडित को दिये जाते थे। चिता के शव की राख को ले जाकर गंगा दी में प्रवाहित किया जाता था। क्योंकि हिन्दू धर्म में अंतिम क्रिया गंगा के किनारे सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अब हर शव गंगा के किनारे नहीं जलाया जा सकता इस कारण शव की चिता के अंष को गंगा में प्रवाहित करने का चलन था। अंतिम संस्कार के बाद तेरहवीं का संस्कार होता था। जिसमें बाल बनवाने से लेकर दावत खिलाने

तक के काम होते थे।

ना दान ना संस्कार

कोरोना काल में इस अंतिम संस्कार की परिभाषा बदल गई है। जिन लोगों मौत कोरोना से हो रही है उनके शव को अंतिम संस्कार के लिये घर वालों को नहीं दिया जाता है। यह शव पूरी तरह से पीपी किट में पैक होता है। अस्पताल से शव दाह संस्कार के लिये घाट पर ले जाया जाता है। वहां लकड़ी की जगह पर बिजली से शव को जलाया जाता है। शव को पीपी किट सहित की जला दिया जाता है। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ने के बाद बिजली से जलाने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में अब खुले में लकड़ियों के सहरे ही शवदाह होने लगा है।

इससे शव को जलाने के लिये आम और चंदन तो मिल ही नहीं रहा। जंगल की जलाऊ लकड़ी वाले पेड़ों से मिलने वाली लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। शव को जलाने के समय किसी भी तरह के अंतिम

संस्कार में होने वाली पूजा को नहीं किया जाता है। न ही घर वालों को कपाल क्रिया करने का मौका मिलता है। शव के जल जाने के बाद जगह को खाली करने के लिये सरकारी जेसीबी मशीन से वहां को साफ कर दिया जाता है। जिससे नये शवों का दाह संस्कार हो सके।

ना घर परिवार ना रिश्तेदार

अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को देखे तो कोरोना काल में यह पूरी तरह से बदल गई है। पहले जहां अंतिम क्रिया में घर, परिवार, मित्र और नाते रिश्तेदार शामिल होते थे। अब केवल सरकारी मशीनरी ही काम करती है। पंडित, पुजारी और घाट पर काम करने वाले डोम अब इसका हिस्सा नहीं रह गये हैं। अंतिम संस्कार के बाद चिता की राख को गंगा में प्रवाहित करना मुश्किल हो गया है। क्योंकि सामूहिक अंतिम संस्कार में चिता को पहचान कर उसकी राख ले जाना नामुमकिन हो गया है। उसको उपर वहां जाने पर कोरोना फैलने के

खतरे को देखते हुये तमाम परिवार वहां जाने से बचते हैं।

अंतिम संस्कार के बाद होने वाली पूजा, तेरहवीं संस्कार भी केवल दिखावे के लिये रह गये हैं। तमाम परिवार अखबारों में विज्ञापन देने और धांतिपाठ से ही पूरी तेरहवीं संस्कार को पूरा मान लिया जाता है। कई परिवारों ने अब ह्यूजूम एप्ह्यू घर परिवार और दोस्तों को आपस में जोड़कर अंतिम संस्कार को पूरा करते हैं। इस तरह से कोरोना ने पूरे अंतिम संस्कार को बदल दिया है। अंतिम संस्कार को लेकर होने वाले इस बदलाव का विरोध अब कोई वर्ग नहीं कर रहा है। इसे सहज रूप से सभी ने स्वीकार कर लिया है। अब इसका पालन भी लोग करना चाहते हैं। जिससे किसी और में इस की बीमारी को फैलने से रोका जा सके।

हाशिये पर तेरहवीं संस्कार

देखा जाये तो हिन्दू धर्म में अंतिम संस्कार और तेरहवीं संस्कार को लेकर विरोध शुरू से रहा है। लेकिन पड़े पुजारी हमेशा ही विरोध करने वालों को गलत बताते थे। यही वजह है कि कोरोना से पहले विद्युत शवदाह में अंतिम संस्कार करने वालों को हिन्दू धर्म का विरोधी माना जाता था। लकड़ियों के जरीये अंतिम संस्कार का भी विरोध होता था। क्योंकि शव को जलाने के लिये पेड़ का काटना पड़ता था। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता था। धर्म के पांखड़ के चलते लोग

अंतिम संस्कार के बाद होने वाली पूजा, तेरहवीं संस्कार भी केवल दिखावे के लिये रह गये हैं। तमाम परिवार अखबारों में विज्ञापन देने और धांतिपाठ से ही पूरी तेरहवीं संस्कार को पूरा मान लिया जाता है। कई परिवारों ने अब ह्यूजूम एप्ह्यू घर परिवार और दोस्तों को आपस में जोड़कर अंतिम संस्कार को पूरा करते हैं। इस तरह से कोरोना ने पूरे अंतिम संस्कार को बदल दिया है। अंतिम संस्कार को लेकर होने वाले इस बदलाव का विरोध अब कोई वर्ग नहीं कर रहा है। इसे सहज रूप से सभी ने स्वीकार कर लिया है। अब इसका पालन भी लोग करना चाहते हैं।

लकड़ियों का प्रयोग बंद ही नहीं करना चाहते थे। आज कोरोना काल में उसी विद्युत शवदाह की तरफ हर कोई जाना चाहता है। तेरहवीं संस्कार भी केवल नाममात्र का बचा है। उसमें भी अब कोई बाध्यता नहीं रह गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब लोग ऐसे

कार्यक्रमों में कम जाना चाहते हैं। दूसरे सामान्य परिवार इस तरह से खर्च से बचना चाहते थे। मरीज के इलाज के दौरान अस्पताल में ही इतना खर्च हो जाता है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते। उनको कर्ज लेकर काम चलाना पड़ता है। खर्च का बोझ कम करने के लिये ऐसे खचीले संस्कारों को टाल दिया जाता है।

घर वाले भी होते हैं बीमार

कोरोना संक्रमण में परिवार के एक आदमी के बीमार होने से दूसरे लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। कई मामलों में एक ही घर के कई कई लोग बीमार होते हैं। कई मामलों में घर के कई सदस्य अस्पताल में होते हैं। ऐसे में आगे एक व्यक्ति की मौत हो गई तो उसके क्रियाकर्म को देखने वाला भी कोई नहीं रहता है। ऐसे में तेरहवीं और बाकी संस्कार की बात ही होती है। अस्पताल और इलाज में इतना पैसा खर्च हो जाता है कि परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब हो जाती है। जिसकी वजह से हर परिवार किसी तरह से केवल अपने जीवनयापन की तरफ ही ध्यान दे पाता था। ऐसे में तमाम कर्मकांडों को वह छोड़ना चाहता है। धार्मिक और पुराणजीवियों के दबाव में अभी तक वह रुदियों और रीति रिवाजों को तोड़ने का साहस नहीं दिखा पा रहा था। कोरोना काल में रिवाज खुद की टूट रहे हैं और अब इसका विरोध पुराणजीवी और पड़े भी नहीं कर पा रहे हैं।



बॉलीवुड के ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार का निधन

अनूप नारायण सिंह

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। उन्हें पिछले महीने से ही सांस संबंधित समस्याएं बनी हुई थी। जिसके चलते उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यही पर 98 वर्षीय दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। दिलीप साहब के साथ उनकी पत्नी और अभिनेत्री सायरा बानो उनकी आखिरी सांस तक साथ रहीं। सायरा दिलीप कुमार का खास ख्याल रख रही थीं और फैंस से लगातार दुआ करने की अपील भी कर रही थीं।

दिलीप कुमार की निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक पसर गया है। सेलेक्स सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें, दिलीप कुमार को सांस में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय उनके फेफड़ों के बाहर तरल पदार्थ एकत्र हो गया, जिसे चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक निकाल दिया था और पांच दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। पिछले साल, दिलीप कुमार ने अपने दो छोटे भाइयों असलम खान (88) और एहसान खान (90) को कोरोना वायरस के कारण खो दिया था। जिसके बाद उन्होंने अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह भी नहीं मनाई थी। हालांकि, सायरा बानो ने बताया था कि दोनों भाइयों के निधन की खबर दिलीप साहब को नहीं दी गई थी। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था और उनका पहला नाम यूसुफ खान था। बाद में उन्हें पर्दे पर दिलीप कुमार के नाम से शोहरत मिली। एक्टर ने अपना नाम एक प्रोड्यूसर के कहने पर बदला था, जिसके बाद उन्हें स्क्रीन पर दिलीप कुमार के नाम से लोग जानने लगे।

दिलीप कुमार की शुरूआती पढ़ाई नासिक में हुई। बाद में उन्होंने फिल्मों में अभिनय का फैसला किया और 1944 में रिलीज हुई फिल्म ज्वार भाटा से डेब्यू किया। शुरूआती फिल्में नहीं चलने के बाद, अभिनेत्री नूर जहां के साथ उनकी जोड़ी हिट हो गई। फिल्म जुगनू दिलीप कुमार की पहली हिट फिल्म बनी। दिलीप साहब ने लगातार कई फिल्में हिट दी हैं। उनकी फिल्म मुगल-ए-आजम उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। अगस्त 1960 में रिलीज हुई यह फिल्म उस वक्त की सबसे महंगी लागत में बनने वाली फिल्म थी। दिलीप कुमार को



आठ फिल्मफेयर अर्वांड मिल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा अर्वांड जीतने के लिए दिलीप कुमार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दिलीप कुमार को साल 1991 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। 2000 से 2006 तक वह राज्य सभा के सदस्य भी रहे। 1998 में वह पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से भी सम्मानित किए गए।

(लेखक वरिष्ठ फिल्म पत्रकार व फिल्म संसर बोर्ड कोलकाता रीजन के सदस्य हैं)

Coming Soon

आवश्यकता है पूरे देश में व्यूरो प्रमुख, विज्ञापन प्रतिनिधि की, इच्छुक व्यक्ति अविलंब संपर्क करें।

CB News

24x7

खबर हमारी, फैसला आपका
www.cbnews24x7.com

